MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF THE PRESIDENT —*continued.*

श्री गंगा शरण सिंह (बिहार) : उप-सभापति महोदया, कल मैं काश्मीर के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। दुर्भाग्य हमारा यह रहा है कि काश्मीर के सम्बन्ध में जिस सफाई से और जिस मुस्तैदी से बातें होनी चाहिये थीं उस तरह से नहीं हुईं। आज भी जो कुछ हुआ, जो कुछ मिनिस्टर साहब ने कहा, नाम बतलाने के बारे में, वह भी, इस बात का सबूत है कि एक तरह की सीक्रेसी का, एक तरह की गुप्तता का, एक तरह का रहस्यमय वातावरण वह काश्मीर में बनाए रखना चाहते हैं और उसके चलते बहुत नुकसान हो चुका है। पहले भी हुआ है और अभी भी वह जारी है और शायद आगे भी वह रवैय्या जारी रहे। अगर यह रवैय्या जारी रहेगा तो उससे हमारे मुल्क के लिये दिक्कतें पैदा होंगी। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर के मामले में और ज्यादा सफाई से बात होनी चाहिये, ज्यादा सफाई से काम होना चाहिये। यदि बाल की चोरी का सवाल लिया जाय तो चोरी हुई यह बात समझ में आ भी सकती है, लेकिन चोरी होने के बाद जब फौज के लोग वहां मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे जनता के हजारों आदमी मौजूद थे, ऐसी हालत में वह बाल कैसे फिर से रख दिया गया, कब रख दिया गया, यह बात अभी भी समझ में नहीं आती और इसके मामले में चूंकि सफाई से बातें नहीं कही गई हैं इसलिये उसका नतीजा यह है कि तरह तरह के रयूमर्स, तरह तरह की अफवाहें आज काश्मीर में और काश्मीर के बाहर चल रही हैं। कुछ अफवाहों का जिक्र कल मैंने किया था। और भी अफवाहें आज हमारे मुल्क में चल रही हैं, मैं उनका जिक्र करके आपका समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि काश्मीर के मामले में जितनी सीक्रेसी बरती जा रही है, जरूरत से ज्यादा सीक्रेसी बरती जा रही है, उससे मामला कुछ बिगड़ता जा रहा है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो मुकदमा इस सिलसिले में चले वह खुले आम चलना चाहिये। जो ट्रायल होना चाहिये वह ट्रायल कोई सीक्रेट ट्रायल नहीं होना चाहिये, प्राइवेट ट्रायल नहीं होना चाहिये। आम जनता के सामने वह खुला हुआ ट्रायल हो तब उसके साथ न्याय हो सकेगा और तब हिन्दुस्तान की जनता की शंका का समाधान होगा। अब तक जो मुकदमा चल रहा है काश्मीर में, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। जितने दिनों से वह चल रहा है जिस तरह धीरे धीरे, कछुए की गति से उस मुकदमे की कार्यवाही हो रही है, उसको देखते हुए मैं नहीं जानता कब तक उसका फैसला होगा। जो मुकदमे की गति है उससे न काश्मीर का नाम ऊंचा हो रहा है, न हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जो नया मुकदमा चले उसमें सफाई से काम चले और कुछ कहने का मौका लोगों को न मिले। जहां तक हमारा सवाल है हम शुरू से ही काश्मीर के पूरी तरह से देश के साथ समन्वय के पक्ष में रहे हैं, हम शुरू से चाहते रहे हैं कि काश्मीर का पूरे तौर पर देश के साथ इन्टीग्रेशन हो। आज भी हमारा वही मुतालबा है, आज भी वही मांग है। मेरा ख्याल है कि अगर शुरू में काश्मीर का इन्टीग्रेशन, पूरा समन्वय, देश के साथ हुआ होता तो आज जो समस्याएं देश के सामने आई हैं, काश्मीर के सामने आयी हैं, उनमें से बहुत सी समस्याएं नहीं आतीं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे मिनिस्टर शास्त्री जी ने कल उस सदन में कहा कि काश्मीर के सभी लोग यह चाहते हैं और कुछ उन्होंने इस सम्बन्ध में बातें कहीं। अगर यही बात पहले कही जाती और पहले उस पर अमल किया जाता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी मुश्किलात हमारी आसान हो सकती थीं। इस सम्बन्ध में काफी विलम्ब हो चुका है, काफी देरी हो चुकी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि काश्मीर के मामले में अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिये और इन्टीग्रेशन की पूरी

पूरी कोशिश की जानी चाहिये; नहीं तो यह बीच की चीज चलने वाली नहीं है। अगर काश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो जिस तरह से देश के और हिस्से हैं और जिस तरह से और हिस्सों के साथ बर्ताव किया जाता है उसी तरह से उसके साथ भी बर्ताव किया जाना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि वह हमारा हिस्सा नहीं है, अगर दिल में चोर है, तो वह बात साफ कहिये। इस तरह हां या ना कहने से बात साफ मालूम नहीं होती है। इस तरह से यह बात नहीं चलनी चाहिये जैसा कि पिछले जमाने में काश्मीर के सम्बन्ध में दुविधा से काम लिया गया। मैं देखता हूं कि वही दुविधा जो दिल में पहले काश्मीर और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में थी वही आज भी है। अगर यह दुविधा चलती रही तो इससे देश को नुकसान होगा। इसलिए काश्मीर का पूरी तरह से इन्टीग्रेशन हमारे देश के साथ होना चाहिये। जैसे देश के दूसरे बाशिन्दे हैं, जैसे देश के दूसरे राज्य हैं और जैसे उनके अधिकार और कर्तव्य हैं वैसे ही काश्मीर के होने चाहियें। यह हमारी मांग है।

अब जहां तक सवाल है राष्ट्रपति जी के भाषण का और उसमें जिन विषयों के बारे में जिक्र किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह ठीक है मुनासिब है कि उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रेजीडेण्ट केनेडी की मृत्यु का जिक्र किया गया। लेकिन मुझे अफसोस होता है—प्रेजीडेंट केनेडी की मृत्यु का जिक्र किया गया, वह मुनासिब किया गया, लेकिन हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के निधन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं नहीं समझ सका हूं कि यह गफलत जो हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु का उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस भाषण को जब मैंने पढ़ा और इस बात पर ध्यान आया तो मेरा सर शर्म से झुक गया। यह गफलत जिसकी भी तरफ से हुई है एक शर्मनाक गफलत है और इससे हम सब लोगों का सर नीचे हो जाता है।

मैं यह उम्मीद करता था कि हमारी सरकार और सरकार के लोग ज्यादा एलर्ट होंगे, ज्यादा मुस्तैद रहेंगे और जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भाषण होता तो वे आखिरी एक दो दिन तक की बातों तक का उसमें उल्लेख करते। इस दृष्टि से मैं पाता हूं कि इस भाषण में खामियां हैं। हमारे उपराष्ट्रपति का भाषण जिस रोज हुआ उसके ठीक एक रोज पहले बर्मा के रेवोल्युशनरी कौंसिल के चेयरमैन जेनरल नेविन हमारे मुल्क से गये थे। जहां इस भाषण में दूसरे देशों से आए प्रमुख लोगों का जिक्र हुआ वहां एक दिन पहले ही जो हमारे देश से गये उनका जिक्र नहीं किया गया। इसके बारे में यह कहा जायेगा कि भाषण पहले ही छप चुका था, लिखा जा चुका था, इसलिए उनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया। यह तो कहने की चीज है और इसके बारे में एक्सक्यूज और बहाना बनाया जा सकता है। मेरा कहना है कि जिस समय भाषण दिया गया हो उस समय तक की घटनाओं का उल्लेख उसमें होना चाहिये। बर्मा के रेवोल्युशनरी कौंसिल के चेयरमैन जेनरल नेविन का उस भाषण में उल्लेख होना चाहिये था। जहां दूसरे देश के प्रमुख लोगों के आने का उसमें उल्लेख था वहां उनके आने का उल्लेख भी जरूरी था।

महोदया, देश में भ्रष्टाचार के बारे में काफी चर्चा चल रही है और सदन में भी काफी चर्चा चलती रहती है। उपराष्ट्रपति जी के भाषण में भी उसकी चर्चा है और इसके बारे में एक विजिलेन्स कमीशन बनाया गया है जिसकी कि आजकल बड़ी चर्चा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितनी चर्चा होती है उसके बारे में तजुर्बा यह हुआ है कि जितनी चर्चा

[श्री गंग शरण सिंह]

इसके बारे में की जाती है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है । मैं उम्मीद करता हूं कि विजिलेन्स कमीशन की चर्चा के बाद भी वही रवैय्या जारी नही रहेगा जो अब तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था । भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिस अनुपात से चर्चा हुई उसी अनुपात से भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया । यह तो वही कहावत हुई कि मर्ज बढ़ता गया ज्यूं ज्यू दवा की । मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा उस तरह की बाते नही होंगी । मुझे इसमें इस बात का खतरा है कि जहां तक सरकार के अधिकारियों का प्रश्न है, उसके लिए तो विजिलेन्स कमीशन बनाया गया है लेकिन जहां तक राजनीतिक स्तर पर, मिनिस्टरों के स्तर पर और ऊंची जगहों पर भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके लिए कुछ नही किया गया है । मैं जहां तक समझता हूं भ्रष्टाचार कोई नीचे से विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी की तरह नही है जो कि पृथ्वी के नीचे से, पहाड़ के नीचे से विस्फोट होता हो । भ्रष्टाचार तो नदी की धारा की तरह है और जिस तरह से नदियां पहाड़ों के ऊपर से होकर नीचे उतरती है, नीचे बहती है, समुद्र तक चली जाती हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार की धारा हमारे देश में ऊपर से पैदा होती है । अधिकार के ग्लेशियर में, अधिकार के हिमानी से, वह पैदा होती है और बहती हुई नीचे सतह तक चली जाती है । इसलिए सिर्फ नीचे से ही भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करना बेकार है । उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्गम है वह ग्लेशियर, जहा से भ्रष्टाचार की नदी निकलती है, अगर हम उस स्रोत को रोकने की कोशिश नही करेंगे तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे प्रयत्न बेकार होंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो उसको जहा उसका स्रोत है, उद्गम है, जहा से भ्रष्टाचार पैदा होता है, जहा पर भ्रष्टाचार की जड़ है, वहां पर उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये । अब तक सरकार ने जो कुछ किया है उसका उपराष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पता नहीं चलता है । भ्रष्टाचार का जो स्रोत है उसको रोकने के लिए हमारी सरकार की ओर से कौन सी चेष्टा की जा रही है । यह तो जड़ को न पकड़कर शाखा को पकड़ने की कोशिश हो रही है । शाखा को भी पकड़ना चाहिये लेकिन जड़ को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं ।

एक बहुत ही दर्दनाक चीज है जिसकी तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश में जो इमरजेन्सी की घोषणा हुई थी, सारे देश ने, हर पार्टी ने, लोगों ने पूरे दिल से उसका समर्थन किया था । सारा देश और सारे देश की जनता इस इमरजेन्सी के हक में थी । इस इमरजेन्सी की वजह से सरकार को अधिकार प्राप्त हुए जो साधारणतया प्राप्त नही हो सकते थे । लेकिन उसके बाद सरकार ने जैसा बर्ताव किया, जैसा व्यवहार किया, उसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में अधिकाश जनता यह चाहने लगी है कि इस इमरजेन्सी को खत्म होना चाहिये । इमरजेन्सी में जिसके लिए अधिकार दिये गये थे उस तरह से काम नही लिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया । इमरजेन्सी के लिए इसलिए सरकार को अधिकार दिये गये थे कि देश को तैयार किया जाय, देश को साधनों की दृष्टि से तैयार किया जाय, देश को मनोवृत्ति की दृष्टि से तैयार किया जाय । इसीलिए सरकार को ये अधिकार दिये गये इमरजेन्सी के लिये । लेकिन वह तैयारी नही हुई, या अगर हुई तो देश को पता नही है । भीतर ही भीतर तैयारी हुई हो तो हम नही कह सकते लेकिन बाहर जो तैयारी होनी चाहिये सगठन के जरिये, मनोवृत्ति के जरिये, वह तैयारी हमे देश में देखने में नही आती है । इस इमरजेन्सी का सरकार ने नाजायज फायदा उठाया और दलबन्दी को प्रश्रय दिया गया । डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स का नाजायज फायदा उठाया गया और उसका

नाजायज़ उपयोग किया गया । ऐसी चीज़ों के लिए उपयोग किया गया जिन चीज़ों के लिये नहीं किया जाना चाहिये था और जिस चीज़ के लिये उपयोग किया गया वह शर्म की बात है। जहां साधारण कानून से काम लिया जा सकता था वहां डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स से काम लिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ एक दो बातें इसके संबंध में बतलाना चाहता हूं जिसके बारे में शायद सदन को पता हो । शायद सदन को पता हो और मैं उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने सदन के दो सदस्य प्रो० मुकुट बिहारी लाल और श्री चन्द्र शेखर डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के मातहत गिरफ्तार किये गये थे । किस लिये गिरफ्तार किये गये ? क्योंकि वे यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाना चाहते थे और गुड़ लाने वालों के खिलाफ डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया गया । मैं नहीं समझता कि इस सदन में कोई ऐसा आदमी होगा या देश में कोई ऐसा आदमी होगा जो यह कल्पना करता होगा कि जब डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स बनाये गये थे तो उसका प्रयोग यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाने के लिए किया जायेगा ? क्या डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स यू० पी० से दिल्ली गुड़ लाने वालों के खिलाफ प्रयोग करने के लिये बनाया गया था । एक जमाना था जब हर आदमी तक नमक पहुंचाने के लिए, नमक कानून पर से टक्स उठाने के लिए गांधी जी ने इस देश में एक राष्ट्रीय आन्दोलन किया था । और फ़ख्र के साथ हम सब के सब उसमें जेल गये और हम सब के सब उसमें शामिल हुये । आज शर्म की बात यह है कि हम ऐसी सरकार के मातहत रह रहे हैं जो गुड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग करती है, और पार्लियामेंट के मेम्बरों को गिरफ्तार करती है ।

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : गुड़ का भी चीनी से सम्बन्ध है ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Hang your head in shame. Are you listening, gentlemen of the Treasury Benches.

श्री गंगाशरण सिंह : एक तरफ हम ग्रामोद्योग की बातें करते हैं, एक तरफ हम तमाम दुनिया भर के छोटे उद्योगों की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुड़ के बारे में जो रवैय्या अख्तियार किया गया है, वह मेरी समझ में नहीं आता है । गुड़ के बारे में जो कुछ सरकार कर रही है और जिस तरह से पार्लियामेंट के मेम्बरों पर गुड़ के मामले में आप डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू कर रहे हैं उससे सरकार को चाहे शर्म लगती हो या न लगती हो, लेकिन मुझ को शर्म आपके इस कारनामे से लगती है ।

आज सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है बल्कि जहां कहीं ज़रूरत पड़ी है, ट्रेड यूनियन के लिये जहां कहीं ज़रूरत पड़ी है, वहां अपने दल को, अपनी पार्टी को और सरकार के समर्थकों को बढ़ावा देने के लिये डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया गया है । गोमिया में मैं जानता हूं, मेरे सूबे का सवाल है, वहां गोमिया में बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन, भूतपूर्व और वर्तमान जो चेयरमन हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में, ट्रेड यूनियन के चलते, ट्रेड यूनियन के काम के चलते और ट्रेड यूनियन के झगड़े के चलते । मैं उसमें तफसील से नहीं जाना चाहता । लेकिन कभी यह कल्पना नहीं की गई थी कि जहां आई० एन० टी० यू० सी० के यूनियन के साथ झगड़ा होगा या आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर के साथ झगड़ा होगा, वहां आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर के मुखालिफों के विरुद्ध डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग होगा । वहां श्री बसावन सिंह और श्री सूर्य नारायण सिंह जो कि बिहार लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं और बिहार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व और वर्तमान चेयरमैन हैं, उन दोनों को और उनके साथ कई दर्जन आदमियों को डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत गिरफ्तार

[श्री गंगाशरण सिंह]

कर जेल भेजा गया । अगर यही रवैय्या है डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के प्रयोग का अगर यही रवैय्या रहा इमरजन्सी के जमाने मे, अगर इमरजेंसी का यही नाजायज फायदा उठाना चाहते है तो इससे अच्छा यह है कि इमरजेंसी को खत्म कीजिये । असल जो तैयारी होनी चाहिये चीन का हटाने के लिये, उसके लिये क्या तैयारी कर रहे हैं ? अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वह कम से कम इस सदन के लोगों को नही मालूम है और देश भी नही जानता है । चीन ने जिस जमीन पर दखल कर लिया है उसके लिये क्या कर रहे हैं इमरजेंसी के अधिकार और कानून के जरिये से, उसका पता नही चलता है, लेकिन यहा जो सरकार के दल के विरोधी है, जिनसे मतभेद है उनको दबाने के लिये डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का प्रयोग किया जा रहा है । यह नाजायज चीज है और हमने इसकी कभी कल्पना नही की थी जब डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अधिकार दिये गये थे, जिस समय पार्लियामेंट मे वह पास हुआ था या जिस समय इमरजेंसी यहा डिक्लेयर हुई थी । आज बहुमत के बल पर, आज मेजारिटी के बल पर देश के हित मे बनाई गई चीजों को इस तरह जो *नाजायज उपयोग* मे ला रहे है, वह सिर्फ यही नही है कि गलत है बल्कि मैं तो इसको राजनैतिक बईमानी समझता हू जो आज यह सरकार कर रही है ।

SHRI BHUPESH GUPTA: To put it mildly.

श्री गंगाशरण सिंह जहा तक देश की आर्थिक अवस्था का प्रश्न है, दिन पर दिन अवस्था बुरी होती जा रही है और सरकार जो कुछ कोशिश थोडी बहुत करती है वह इतनी देर से करती है, इतना नाकाफी करती है और इस तरीके से करता है कि उसका कोई असर नहीं होता है । आज जो हमारे यहा कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स बनता है आज की परिस्थिति मे और जो हमारी जरूरते है और इस देश के रहने वालो को जिन चीजो की आवश्यकता है उन पर और इंडेक्स निकालने मे जितने मदो का उसमे उल्लेख करके, इंडेक्स बनता है, अगर आप उन दोनो पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वह चीज काफी आउट-आफ डेट हो गई है और बहुत सी चीजो का, बहुत से मदो का, उससे आज सम्बन्ध नही रह गया है । अभी महाराष्ट्र मे जो लकडावाला कमेटी बनी थी और उसने जो सुझाव दिये थे वे बहुत हद तक सही थे, और जो तरीका हमारा अब तक रहा है उससे वह तरीका कुछ ज्यादा अच्छा है और मेरा खयाल है कि अगर हो सके तो उसमे कुछ और सुधार करके केन्द्रीय सरकार को और दूसरी जितनी प्रादेशिक सरकारे है उनको वह तरीका अख्तियार करना चाहिये । अगर वह तरीका अख्तियार कर *लिया जाता तो शायद* जो इंडेक्स हमारे सामने आ रहे है वे ज्यादा सही आते । लेकिन जो गलत तरीका आपका है, जो बहुत सही तरीका नही है, उसके मुताबिक भी इंडेक्स के नम्बर बढते जा रहे है और उसके मुकाबिले मे आप कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं । उसकी पूर्ति के लिये आप कुछ नही कर रहे हैं और जो कर रहे है वह बिल्कुल नाकाफी है । थोडा सा डियरनेस अलाउंस आप देते है लोगो को, लेकिन जब तक आप डियरनेस अलाउंस देते है या देने का फैसला करते है तब तक इंडेक्स का नम्बर फिर आगे बढ जाता है । इस तरह से डियरनेस अलाउंस और महगाई मे जो भाग-दौड मच रही है, उस दौड मे महगाई बराबर आगे रहती है और डियरनेस अलाउंस आपका बराबर पीछे रहता है । वह कभी उसके पास नही पहुच पाता है । आप रफू करने की कोशिश करते है, लेकिन रफू से काम नही चलता है जैसा कि किसी ने कहा है

कपडा सडा गला हो तो मुमकिन नही रफू,
सीते थे आस्तीन, गरेबान फट गया ।

इतना ही नही है, आगे भी है :

बारे गुनाह बढ़ गया उज्रे गुनाह से,

धोने से और दामने ईमां चिकट गया ।

आज जब मैं इस सम्बन्ध में सोचता हूं तो मुझे बार बार यह बात याद आती है :

धोने से और दामने ईमां चिकट गया ।

आज सब से बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी कदम बढ़ाना चाहिये । नहीं तो देश की जो हालत आज हो रही है, देश की जो तबाही हो रही है और मामलों में, अगर आर्थिक मामला उसी तरह से आगे खराब होता गया, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की हालत एक रोज़ ऐसी हो जायगी जिससे फिर हमारा निस्तार नहीं हो सकेगा । एक ओर तो महंगाई आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर बेकारी का भी वही हाल है । बेकारी के लिये आप कोशिश करते हैं, लेकिन जो बैकलाग है, जो पहले से बेकारी चली आ रही है उसमें बजाय कम होने के बेकारी और बढ़ती ही जाती है । यह महंगाई और बेकारी का सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये मुंह बाये हमें खाने को आ रही हैं और हमारे देश की जो आर्थिक नीति है, उसका पता नहीं क्या हाल होगा; इन दोनों महंगाई और बेकारी के चक्कर में पड़ कर और इसमें सैंडविच हो कर हम क्या हो जायेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair]

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सारी चर्चा के बावजूद अगर सारे देश के भीतर आज आप ग़ौर करें तो पता चलेगा कि इन गृह उद्योगों की जैसी बुरी हालत है वैसी बुरी हालत शायद किसी की नहीं है । कहीं स्कीम ही नहीं बन पाई है । कहीं उनके लिये रा मैटीरियल ही नहीं है, कच्चा माल ही नहीं है । अगर कहीं कच्चा माल है तो फिर उसके लिये उनके पास साधन नहीं हैं । उसके लिये जो उनको उधार मिलना चाहिये, उसके लिये उनको जो पैसा मिलना चाहिये, उसकी भी आज कमी मालूम होती है । हमारे देश की जो अवस्था है, हमारे देश में जितनी बेकारी है, हमारे देश में जितनी जनसंख्या है, उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे छोटे उद्योगों के बग़ैर हमारे देश का उद्धार नहीं होने वाला है । छोटे छोटे उद्योगों के बग़ैर न तो हमारी आर्थिक अवस्था सुधरेगी और न हमारी बेकारी दूर होगी । इसीलिये छोटे उद्योगों की ओर आज सब से अधिक हम लोगों को ज़ोर देना चाहिये ।

ऐसे बहुत से गांव हैं जहां आपने बिजली दे दी है । ऐसे बहुत से गांव मैं जानता हूं बिहार में भी और दूसरे सूबों में भी जहां आपने बिजली दे दी, आपने बिजली के खम्बे खड़े कर दिये, बिजली पहुंचा दी, लेकिन गांव वालों को यह नहीं बताया कि बिजली का उपयोग उद्योगों के लिये किस तरह करना चाहिये, उनको साधन नहीं दिये, नहीं बतलाये । जो हिन्दुस्तान के गांव हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली का उपयोग कर सकते हैं सिर्फ पखों के लिये और रोशनी के लिये और सिर्फ आराम की चीज़ों के लिये । गांवों में अगर आपने बिजली पहुंचाई है, तो उसके साथ ही साथ आप को वहां स्कीमें पहुंचानी चाहियें कि उन गांवों में बिजली का क्या उपयोग होगा, उसका उद्योग से क्या सम्बन्ध होगा, और गांवों में जो कृषि होती है उस कृषि से उसका क्या सम्बन्ध होगा, लेकिन उसमें कोई समन्वय नहीं है । गांवों में जो आप बिजली दे रहे हैं उसके साथ कृषि और उद्योगों का समन्वय नहीं है । हज़ारों गावों में आपने बिजली दी है । उसमें एक तो गवर्नमेंट को घाटा देना पड़ता है और कुछ बड़े लोग अपने घरों में रोशनी लगा सकते है, पंखे लगा सकते हैं, लेकिन बाकी गांव वाले जो गांवों में बिजली जाती है उस बिजली से फायदा नहीं उठा सकते हैं । यह मैं व्यक्तिगत तजुर्बे की बिना

[श्री गगाशरण सिंह]

पर बहुत से गांवों को देख करके कह रहा हूं। आज ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ विशृंखल हो गया है। कोई शृंखलता हमारे बीच में नही है, कोई समन्वय नही है, कोई सामंजस्य नही है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमारे देश में जो नीति चलेगी उसमें कृषि और छोटे उद्योगों के बीच में एक सामंजस्य और समन्वय करना होगा और बिजली का उपयोग अधिक से अधिक हमारे गांव वालो को सिखलाना होगा। इस दिशा में मैं लेनिन के उस कथन और कार्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रूस में क्रांति होने के बाद लेनिन ने सब से ज्यादा ज़ोर जिस पर दिया था, वह इलेक्ट्रीफिकेशन पर ज़ोर दिया था, बिजली पर ज़ोर दिया था और बिजली हर जगह पहुंचाने की उसने चेष्टा की थी और साथ ही साथ बिजली के उपयोग की भी चेष्टा की थी। मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ एकांगीरूप से कर रहे हैं वह एकांगी-रूप से नहीं होना चाहिये बल्कि उसका समन्वय का रूप होना चाहिये, उद्योग का भी और कृषि का भी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में दो बातों का मुख्यत: जिक्र होना चाहिये, लोग यह अपेक्षा रखते हैं—एक तो पिछले वर्ष से इस वर्ष तक भाषण के समय तक जो मुख्य घटनायें हुई हों उनके सम्बन्ध में कुछ जिक्र होना चाहिये और दूसरा यह कि आगे के सम्बन्ध में दिशा का, गति का, कोई उल्लेख होना चाहिये। उस दृष्टि से मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का भाषण बिल्कुल ही सूखा, निर्जीव, बिल्कुल ही दिशा-निर्देशहीन है और एक बाजाब्तगी के बयान की तरह से लगता है, उससे किसी तथ्य का या दिशा का या आज की परिस्थिति में आवश्यक चीज़ का पता नहीं चलता। एक और ऐसी बात इस बार हुई है जिसकी तरफ भी मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आम तौर से अगर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, अभिभाषण होने वाला हो तो अगले साल जो विधेयक आने वाले हों, जो सरकार की नीति हो उनका उल्लेख भाषण में ही सब से पहले हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन इस बार मैंने यह देखा कि उपराष्ट्रपति के भाषण में उनका जिक्र होने के पहले ही यहां के अखबारों में उनका जिक्र हुआ। पता नहीं कि यह चीज़ सरकार के तरफ से दी गई, जानबूझ कर दी गई या अखबार वालों ने अपनी मेहनत के जरिये से, अपने स्कूप के जरिये से हासिल की लेकिन मैं समझता हूं कि हाउस की डिगनिटी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की डिगनिटी और पद्धति के लिहाज़ से भी यह आवश्यक है कि जो ऐसी घोषणा हो वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा हो और अखबारों में पहले से नही निकले। इस बार स्पष्ट रूप से आप पायेंगे कि उपराष्ट्रपति का भाषण जिस रोज हुआ उससे पहले अखबारों में—मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक अखबार में—पूरे कानूनों का और सब चीजों का जिक्र छप गया। ऐसा मालूम होता है—किसी मिनिस्ट्री के अफसर ने दिया, किसी मिनिस्टर ने दिया या किसी ने भी दिया हो या बाजाब्ता सरकार की तरफ से वह दिया गया हो। उन चीजों का उल्लेख भी उस समाचार पत्र में किया गया जिन में से कुछ का तो उल्लेख राष्ट्रपति के भाषण में हुआ ही नहीं लेकिन सब चीजों का जिक्र समाचार पत्र में किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भाषण जब होने वाला हो तो ऐसी बातों का जिक्र—अखबार वालों को आबलाइज करने या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की वजह से इस तरह की बात न करके—उपराष्ट्रपति के भाषण द्वारा ही किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री भगवत नारायण भार्गव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं इस

प्रस्ताव का समर्थन एक कविता के द्वारा कर रहा हूं ।

पाया सतत मान जग में जिन पूज्य राष्ट्रपति ने शुचि अनुपम ।

उन धर्मज्ञ आत्मज्ञानी का हम करते सादर अभिनन्दन ॥

हिन्दी हिन्द राष्ट्र की भाषा निश्चित है उसका अभिवर्धन ।

त्याग मोह आंगल भाषा का करें सभी हिन्दी आराधन ॥

सुखद समाजवाद संयममय जीवन में होवे साकार ।

सत्यं शिवं सुन्दरं का हो जन जन में पावन संचार ॥

दुख दारिद्रय विषमता का हम करें अविद्या का संहार ।

भ्रष्टाचार अनाचारों का कर दें हम अन्तिम संस्कार ॥

जन गन मन हो धर्म न्याय से ओतप्रोत सदा कर्तार ।

सच्चे गांधीवादी बन कर करे देश शासन विस्तार ॥

करके मर्दन मान शत्रु का ऊंचा रक्खें मां का भाल ।

अजय हिन्द की जय सदैव हो पहिनें लाल जवाहर माल ॥

SHRI R. R. DIWAKAR (Nominated): Mr. Vice-Chairman, I must thank you very much for the opportunity that you have given me to make a few observations on the President's Address. I associate myself with the Motion of thanks that has been moved by Shri Deokinandan in this House. I think the subjects covered by the President's speech are so many and so important that I must be satisfied with making a few observations on some of the subjects which I feel are very important. I must say that so far as the tenor and the cast of the whole speech of the President was concerned, we expected a far more brilliant, a far more stirring and a far more directional speech from one who is known throughout the world as an exponent of the Indian cultural point of view and very deeply soaked in what may be said to be the deeper channels o the Indian mind. Yet when it comes to our reading the Presidential Address we feel that it is somewhat of an official narration or enumeration of certain subjects and nothing beyond that. I do not know if the Presidential chair acts as a kind of damper on the enthusiasm and the spiritual power that a man can command outside officialdom and the official chair.

Now, I think I must first draw the attention of the House, Mr. Vice-Chairman, to the new phrase which has been used in the second paragraph of the Address, 'a democratic and socialist order'. I think we have been familiar, so far as reports in the newspapers and the Congress party policies are concerned, with the phrase, democratic social order, and not with 'a democratic and socialist order'. I do not know why these two words have been now separated, if at all this is a repetition of the policies adumbrated at Bhubaneswar. I think if these words continue to be as they are, they raise some problem in semantics. If a socialist order is to be there, unless it is definitely mentioned that it is through democracy and through non-violance, it may mean any type of socialism. Today a socialist order does not necessarily mean a democratic order; nor does a democratic order necessarily mean a socialist order. So India is in a happy position to say that we are trying to arrive at a socialist order through democratic means. I think unless that is clarified in the clearest possible manner it would create confusion in the minds of the people and they would try to interpret these words in their own way. A socialist order of the Communist type today, for instance, is supposed

[Shri R. R. Diwakar.]

to be democratic and Communists declare it in that way to the world. Communism they say, is a socialist order; not only that, it is a democratic order also! That is why I make the plea that these matters require clarification. Moreover we should also examine in what direction we are going. It happens that a socialist pattern was declared as early as the Avadi session of the Congress. Since then we have been travelling along that line and now we come to the socialist order. But if we examine the different sectors in which nationalisation has been introduced, we have no doubt the full impact of nationalisation but we see very little of the socialist order in that nationalisation. If socialism or the socialist order is to spell only nationalisation, I am afraid we shall not be going in the direction of real socialism but in the direction of State Capitalism. Therefore, it is very necessary for a country like ours to have our fingers on the pulse of the direction as to where we are going and be clear about our destination.

Casting a glance at the international field and the remarks made by the President I am very glad to say that a policy, which had been adumbrated by the Government of India through our Prime Minister that there should be a nuclear test ban—which was really speaking advocated as early as 1958—has after all come to pass during the last year. It is partial, no doubt, but something is better than nothing and let us hope that this test ban is extended, in due course, to underground tests as well. Another welcome sign is that the use of nuclear power in and from outer space has been banned by agreement between rulers of the two countries concerned. The establishment of the 'hot line' also is a very welcome sign. At the same time, I do not think that there is any scope for complacency, because simultaneously France has stood out. Not only that. It is actually making progress in nuclear arms. This morning's papers convey the news that France has now jets which can be served and re-filled in mid-air and its planes carrying nuclear war-heads can travel as far as 4,700 miles, meaning thereby that France can very easily cover some of the targets in Russia on the one side and some other countries on the other side. This is not a development which is very happy, especially in view of the progress towards peace that is being made by the two chief nuclear powers. Similarly, China is still out of bounds, so to say, of international peace efforts and, therefore, it is quite free to carry on its experiments and confront the world one day with nuclear bombs. Therefore, there is very much scope or very great necessity to be as alert as India has been from the beginning, not only in international councils but, I think, also as a people, Indians should be alert about these matters. I may mention that as regards nuclear test ban, the people of India also played their humble part. They boldly took upon themselves the responsibility of conveying to the nuclear powers their clear opinion that what the powers were doing was something which was against the health as well as the future of humanity itself; they had no right to poison the atmosphere of the world in trying to arm themselves against each other.

Then, I should make a reference here to what is going on in the United Nations Security Council. That is also a part of international affairs. I think every one of us appreciates very much the able part played by Mr. Chagla in giving a fitting reply to the allegations and a number of things that Mr. Bhutto said against India on the floor of the Security Council. But one is surprised at the attitude taken by Sir Patrick Dean on behalf of the British Government. While he made a plea for mediation or something like that, there was no mistake in our seeing that his speech was more like that of an advocate of Pakistan than that of a representative of a great nation like England, which had very vital and friendly connections with India. As the British Government as well as the British people must be knowing, India

is making every effort to see that our friendship continues; but it should not be made difficult for India, for instance, to continue that friendship and to continue in the Commonwealth with the goodwill of all the other nations in the Commonwealth. Therefore, I think whatever be the Tory inclinations or the Conservative traditions of British diplomats and British administrators today, they must take into consideration that, if they want real friendship to establish itself between two members of the Commonwealth, they should not adopt a partisan attitude and make it difficult for India and Pakistan to come together. It might be very uncharitable, but some people and historians do say that Pakistan was the creation of the British Government and if such attitudes are struck by the British now and then in the course of diplomacy, well, perhaps that kind of allegation by historians gets support. I think it is necessary that we should raise our voice against such an attitude of the British not only in diplomatic circles in the international sphere but also in this Parliament of ours.

I may now mention a few things about industry—the public sector and the private sector. I need not say that much progress has been made. But after all we are here not merely to register the progress but also to think in terms of where we have failed. So far as mixed economy is concerned, I think it has been declared so many times from the platform as well as in Parliament itself. At the same time, one cannot but feel that the private sector is made to feel a kind of inferiority complex. Those who are running the public sector are naturally in a better position to drive home this kind of inferiority complex. I do not think that Mr. J. R. D. Tata who has made a certain statement in New York to the "New York Herald Tribune" has done it in a lighthearted manner. He is one of the few persons who carries weight with the Government of India. He has easy access to the highest authority and he must be enjoying a number of deserved facilities for building up big industry in the private sector. But even in spite of that, I am glad that he has given vent to the difficulties of the private sector and what the private sector is feeling. This certainly is on behalf of the smaller industries, possibly the smallest of them. What he has said is this that India has infinite capacity and scope for development of industries. While the public sector may go on developing, if the private sector also is given the necessary facilities and encouragement, he says, it will definitely develop faster. These are the words he uses so far as the private sector is concerned. At the same time he asks what it is that comes in the way—well, he says controls and also red-tapism. He has not mentioned the word "red-tapism" but he has mentioned the word "controls". Naturally he does not mean all kinds of controls, but he means that controls have acted in a restrictive manner and they have not been able to give the necessary encouragement for the private sector industries. The third thing that he has mentioned is that these controls have acted as a curb on foreign capital coming into India. I do not mean to say that the Government is not aware of all these difficulties which the private sector is suffering from. I know personally of a few industries where, for instance, they have engaged their capital, carried on the work, constructed buildings, engaged money in machinery and for six months or eight months right from the beginning they have been asking for the necessary licences, and yet at the end of six months or eight months or whatever it is, they do not get the licences; thus all the capital and all the labour is wasted which adds to their frustration. I think this kind of thing should not happen. If this continues to happen, then I think the private sector cannot develop and play its legitimate part in the building up of the nation.

One word about agriculture. Figures have been given that 6 million acres have come under irrigation and 5·5 million acres also are going to come under irrigation. Within my own per-

[Shri R. R. Diwakar.]

sonal knowledge there are two big irrigation projects in which thousands and thousands of acres of land are statistically under irrigation but not a drop of water is passing on to them. And why? The dam is there, about Rs. 100 crores have been sunk on it, Rs. 6 crores are being paid as annual interest, and yet thousands and thousands of agriculturists are not willing to take the water on account of want of co-ordination among the P.W.D., the Irrigation Department, the Revenue Department, and so on, or because the water-cess is heavy or because there are no technical personnel who can give them the proper advice. These things are happening. Therefore, we should not be led away by the figures but we should actually see what is the exact acreage under irrigation. This naturally leads us to the point that agriculture has not been able to play its part in producing enough food in our country, and I think all these matters ought to be looked into. While theoretically we are legislating for social justice, and we are taking action for more production, why is it that production is lagging? Is there want of sufficient incentive to the agriculturist, to the peasant who is working in the field or is this legislation only doctrinaire? We have to see whether this legislation is taking into consideration both social justice and production which are equally important, whether there is a lopsided legislation on the side of social justice and not enough emphasis on the side of production.

I think these are all important matters which have to be taken into consideration. Fortunately I am in the happy position of not being identified with any political point of view. Whatever I have said, I should emphasize I have said as an observer of things, as they are actually being done. While I have every praise and compliment for all that the Government is doing, I would say that they should be far more careful, far more self-introspective and far more responsive to the needs of the small man, to the small industry people and to the man in the street. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Before I call upon the next speaker I would like to know if the House is prepared to sit through the lunch hour as there are a large number of speakers.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Shri Dahyabhai Patel.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, I missed the presence of the dignified personage of the President of India when we had the Address on the opening day of Parliament. We have been so used to seeing him in this House that perhaps some of us might not fully realise how much dignity his presence on the day of the opening of Parliament lends to the proceedings. I hope his illness is insignificant and that he will soon be restored to health. In him we have somebody who is very clear about his thoughts. Indeed a little over a year ago, he said in very clear terms that the Indian reverses in NEFA should be regarded as a matter of sorrow, shame and humiliation, that we have to retrieve our lost prestige and that India's freedom, security and honour are things which are endangered today. Are we doing anything about it?

Next also I would like to say how sorry I am to see our Prime Minister in this state of health. I hope he also will be soon restored to health. But let us recognise that there is such a thing as time, that there is such a thing as age, and the Prime Minister is a sick man and the chances of his being what he was five years ago or ten years ago are rather bleak. Hence his sickness is reflected in the Government. Today we have a sick Prime Minister. We have a sick Government. I am sorry that in certain circles the sickness of the Prime Minister is being exploited by some people, and

people are being asked to be restrained in their criticism, legitimate criticism of Government in Committees. I do not know whether it is going to be repeated here. Sir, we come here as Members of Parliament to do our duty to the country. And I hope that we shall continue to do so fearlessly in spite of what has happened. If the Government is sick, let it go on a rest cure. If the Prime Minister is sick, more so, let him also go on a rest cure. But what is the use of having a Government which cannot make up its mind? The Kamaraj Plan is not going to affect the country, the Government or the Cabinet. What we want is a firm, stable Government. What is happening on both sides of our borders and in the two border States is an indication that the Government is very sick and needs to go on a rest cure. if not go altogether. I must also at this stage take the opportunity of congratulating our representative in the United Nations, Mr. Mohammad Currim Chagla, as he is now known, instead of Mr. M. C. Chagla—Mr. Justice Chagla as we knew him in Bombay—for his bold exposition of India's case in the United Nations. It is a sad reflection on the people who have been in charge, on the people who have been our spokesmen in the United Nations for the last 15 years that they did not raise the many logical points that he raised in his address. His address was cold logic and reasoned. Why did not anybody think of them? So many of them are going to the United Nations again and again. Nobody could think of the point that Kashmir acceded to India as all other Indian States did hrough the Head of the State. Now, this point was not mentioned even in the United Nations all these years. It is a sad reflection on the people who have been in charge of arguing our case. I need not repeat. There are several other arguments in his case—if it is read properly—which were missed previously. (*Interruptions*) We are not dealing. . . .

1 P.M.

SHRI A. M. TARIQ (Jammu and Kashmir): For the hon. Member's information, the Letter of Accession is already on the record of the United Nations; it was from the Maharajah of Kashmir. That is our part.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Tariq, I am not denying that. I am dealing with the presentation of our case. And the people who were there, who went there on behalf of the Government of India to present our case, should have presented it more logically, in a reasoned manner and not with their hearts full of prejudices; they always went and made more enemies for India than friends. That is why our case which is so just and so clear has been bogged down in the Security Council all these years.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Their logic did not win many friends.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is because of the prejudices created by his predecessor. My friend, you know it fully well; you may support him. But the truth cannot be hidden. It is because of his attitude, because he was offensive—his predecessor, I mean—to the free nations of the world that our case has been misunderstood. (*Interruptions.*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Order, order, let him proceed.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): The Communist friends along with Mr. Tariq are trying to defend their leaders.

SHRI A. B. VAJPAYEE: What leaders?

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Please proceed, Mr. Patel.

SHRI BHUPESH GUPTA: We can defend ourselves.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am fully in agreement with the sentiments

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

expressed by Mr. Ganga Sharan Sinha and other friends in this House about the refugees who are coming from across the border. They deserve our every sympathy. It is not their fault that they are in this plight. We have a certain obligation towards them and I hope that the Government will be liberal towards them. Unnecessary obstacles in the way of their coming back should not stand. I know that this means a great drain on our resources, that it means a great burden to the exchequer. But the Government of India will have to stand up and bear it. If the Government—and when the Government—has courage enough—I do not know if it ever will have it—it must demand a portion of territory, land from Pakistan. When so many people are exploited, when they are thrown out from Pakistan, Pakistan must be made to yield so much territory, so that we can house those people. I do not know whether this sick Government will ever have the courage to do so.

Sir, I repeat that this Government is sick. What is happening in regard to the two distinct issues which have figured prominently in this House and how is the feeling of the people being circumvented? I refer to the Serajuddin affair. That has been referred to a Judge.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

But while the proceedings are going on against Serajuddin, the Magistrate, I understand, is being transferred as Chief Presidency Magistrate elsewhere. It is a very ingenious Government that can stop or prolong legal proceedings in this manner by giving promotion to a Magistrate. What will be the result? So many witnesses have been examined.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): The case may remain on the file of the Magistrate even if he is promoted.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Thank you, I know that Even a child knows that. But the purpose of this

• • •

SHRI ARJUN ARORA: I do not consider the hon. Member to be a child, much less my child.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am grateful to God for that. What would have been my fate if I were his child? I am certainly not willing to exchange my position. (*Interruptions.*) Whatever this gentleman may say, I better restrain myself. He will have plenty of opportunities. My time is limited, I am trying to save my time for the other friends of my party who also want to speak.

SHRI LOKANATH MISRA: His friend is involved in the Serajuddin case.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: The trial, I am saying, will go on. Certain people have been examined. Another Magistrate in his place will take up the re-examination of all those witnesses. It is a legitimate request of any accused. Some of the witnesses will be available, some of them will not be available. So, the trial will prolong. Then the matter will go to the higher courts and to the Supreme Court whether such witnesses should be called again or not. These are all dilatory tactics with only one intention, to shield the co-conspirator in this, and I make this charge with a full sense of responsibility, and if this Government tolerates it, they are pleading guilty, demonstrating the charge that I make that this Government is a sick Government.

Sir, the other affair which I would refer to is something much more serious; it is about the border State of Punjab. The Prime Minister has entrusted the enquiry into the allegations against the Chief Minister of Punjab to a Judge. That was expected, of course We know, Sir, of a member of the Legislature, a member of the Congress Party, who was beaten up because he made certain charges. He has

himself said so, he has offered to prove them before anyone. But much more serious is what has happened a few days ago—a person was shot dead, five bullets were fired into his body at eleven of the clock in broad daylight and not one line has appeared in the newspapers anywhere. The person was a close relation of a former Defence Minister of this country. The people who shot him went to shoot him—I am told—in a truck belonging to the son of the Chief Minister. Will the Government enquire into this? Why have no arrests been made? Mr. Nanda wants to arrest Members on a charge of bringing *gur*, under the Defence of India Rules. Where are the Defence of India Rules in the case of murderers, people who murder persons in broad daylight and of their accomplices, people who assist them? What is happening to this Government? It is therefore that I say that this is a sick Government and I do not think that this Government can be cured. The only remedy is to end it, and shall I say also that this country is sick of it? Therefore, they are losing repeatedly all the by-elections that have taken place in the last few months. Let them realise it.

AN HON. MEMBER: Not all.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Most of them.

SHRI A. B. VAJPAYEE: What happened in Mahuwa?

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI (Uttar Pradesh): That is recent.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: My friend, Mr. Bhupesh Gupta, yesterday butted in on my question to make a speech when I asked questions about the affairs of the Bank of China. This is one more example of the sickness of this Government. Responsible Ministers made statements in the Bengal Assembly about the affairs of the Bank of China, of the people who were given money and of a Bombay weekly that is supposed to have received money.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Vice-Chairman . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Mr. Vice-Chairman, I do not yield. He has got his right to speak. He made a speech yesterday butting in during the Question Hour when I was putting questions, which was very wrong. I do not yield, Mr. Vice-Chairman.

SHRI BHUPESH GUPTA: Then there will be a deadlock.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: There can be no deadlock.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Unless he yields you cannot . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: My friend very often returns to the same question. So I presented to the House a statement made by Mr. Prafulla Sen in reply to a calling attention notice given by Mr. Kashi Maitra, the P.S.P. leader, in which Mr. Prafulla Sen said that he had no information. It is in their December proceedings. I made it a part of my question and quoted it. Unfortunately my friend was not here then. The 'Current', a weekly in Bombay, wrote it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: More than one paper wrote it, even a Bengali daily, though I have not got the cuttings with me now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Anyway I leave it at that. He is a good friend otherwise.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Now the Defence of India Rules are used against friends who protest against orders, like the *Gur* Control Order, against people who are agitated about certain things in Bombay, and so on. Somebody who was standing to look at one of these demonstrations was also arrested, because he happened to help certain members of the Swatantra Party, and even my letter to Mr. Nanda explaining the position has not secured his release, while people like this go about freely in this country.

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

What sort of Government have we? Mr. Nanda promised to eradicate corruption in three months.

HON. MEMBERS: Two years.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Two years? Well, six months of the two years have nearly gone.

AN HON. MEMBER: Three months.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Do you see corruption on the decrease? Let Mr. Nanda go to Saurashtra where a by-election is taking place and let him see for himself with open eyes what corruption is taking place at every stage, what pressure is being put on people, how people are being called because they assisted in the previous by-election when Mr. Masani fought at Rajkot. When honest citizens, when people working in State Transport offices and such like offices are being called daily to report to the police station when there is no charge against them, it is simply harassment; it is because they helped others against the Congress. Are these Defence of India Rules or Defence of Congress Rules?, I want to ask, and therefore it is that we demand repeal of this lawless law. If the Government wanted to continue the Defence of India Rules, they must convince us of the reasons therefor. They have to convince this country that they are serious about defending this country. There are rumours, there is documentary evidence —if required it will be forthcoming— that the Prime Minister has already given his assurance that India is not going to advance further than the present line.

SHRI N. C. KASLIWAL (Rajasthan): That is not correct, I will challenge your statement.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: We will come to that, my friend. There are so many defenders of the Prime Minister. You need not be in a hurry. The matter is coming.

SHRI N. C. KASLIWAL: I will show that the letter that you have circulated is completely wrong in facts; you have misquoted facts.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I have not circulated any letter. My friend is labouring under a misapprehension. But the letter that he refers to may come out. What does it matter? Let the Home Minister come out with a full statement on the matter. We want to know about it, and if the Defence of India Rules are there, why not arrest the forgerers? Why don't you use the Defence of India Rules there? Why do you want more power when you cannot use it?

Sir, this sick Government has given us enough worry. Now I will come to the condition of the country as it is. The review of the state of economy, the President has referred to in detail, to every item, and the President has very frankly acknowledged that the overall rate of economic growth has lagged behind despite a certain upward trend in industrial production and improvement in the balance of payments. The President has made the following main points: The general level of industrial output in 1963-64 is expected to be 7 to 8 per cent higher than the previous year. Basic industries like coal and steel have made a little more progress and production in the steel plants is now coming up to what their rated capacity was. They should have come to this some years ago. Now we see some hope of their coming up to that capacity. Then power shortages continue to hinder the growth of industrial progress everywhere; the total availability of power may have improved and the transport position has certainly eased a little There has been an improvement in export earnings and with continuing external assistance from friendly countries our foreign exchange reserves and the country's balance of payments position have not been under the same kind of pressure as it was in the previous year. Some public sector undertakings have made significant progress.

The first Indian manufactured A.C. electric locomotive rolled out of Chittaranjan works. The National Mineral Development Corporation has practically completed the development of the Kiriburu iron ore mines. The Atomic Energy Establishment at Trombay has begun exporting radio isotopes. The expansion of the three public sector steel plants is well underway. Work on the alloy and tool steel plant at Durgapur is in progress, we are told. Action has been initiated for the setting up of the Bokaro steel plant—that is the best that can be said about it, because it is still in a nebulous state. Production in the ordnance factories in 1963-64 is expected to be Rs. 100 crores as compared to Rs. 66 crores in 1962-63 and Rs. 41.45 crores in 1961-62.

To a fair extent, the slow growth of economic progress is due to the shortage of agricultural production which in 1962-63 recorded a fall of 3.3 per cent. While it may be argued that in a country like India in which, over large areas, the volume and distribution of rainfall are decisive factors in agriculture, it is difficult to achieve a steady rate of growth in agricultural production from year to year. This however makes it all the more essential to secure high yields per acre in areas with irrigation and assured rainfall, and the most important factor to be noted in this connection is that the policies and proposals of the Centre and the State Governments regarding ceiling on land, food procurement and distribution, and cooperative cultivation, and the proposed Seventeenth Amendment to the Constitution have disturbed the mind of the agriculturists. They have disturbed the framework in which alone agriculture can progress, and have aggravated the situation by introducing factors of uncertainty and insecurity all round.

As regards industry, the estimated increase of 7 to 8 per cent falls very much short of the postulated annual increase of 11 to 12 per cent. The pace of implementation of new industrial projects as also of expansion of existing ones and therefore of additions to installed capacity suffered on account of the none too encouraging situation which prevailed in the capital market on the one hand, and the growing cost of construction on the other. In the case of nitrogenous fertilisers, vital for the sustenance and growth of the agricultural sector, a number of schemes remain unimplemented. Government seems to have little or no interest in the simple, inexpensive process of introducing *Gobar* gas plant which provides a cheap method of replenishing the land with nitrogenous fertilizers. The Government seem to be thinking only in terms of large factories, importing large amounts worth of machinery from abroad. Fertilizers produced in the factories go mainly to benefit large plantations and sugar factories for, the manner in which the controlled distribution is made it hardly ever reaches the poor agriculturist. And the amount of corruption and red tape involved in getting the fertilizers makes it impossible for him to get any of these fertilizers produced in the large fertilizer factories.

Progress in implementation suffered also in such industries as newsprint, paper and paper board, rayon grade pulp and cement. The uncertainty in the supply position of important raw materials and the general difficulty regarding foreign exchange continue.

A review of the Government's policies discloses considerable lack of coordination. A sick Prime Minister and a sick Government! After all, the whole economy has to function as a single entity. The different parts of it are closely inter-related. There must, therefore, be a uniformity in the working of different policies. This is not fully apparent at present. The monetary policy, while aiming to control prices of certain commodities, has affected the general level of productive activity. If the decontrol of prices on certain commodities announced recently represents a shift in Government's policy, it is certainly

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

a step in the right direction. In isolation, however, this step will not have the desired effect. The fiscal policy is fashioned to draw away resources to the public sector without considering its effect on overall development. It is of less importance whether investment is made in this sector or that sector rather than whether it promotes the development of the whole economy. This purposive co-ordination between different sectors to maximise the flow of production with existing resources is the specific problem of planning and its timely execution. In both these aspects, our administrative machinery has, unfortunately, not reached the high standards which are needed.

A notable development of the year is, however, the record increase of about Rs. 100 crores in export earnings during the year 1963 which has been due mainly to the large quantity exported and the higher unit price. Exports of items covered by the various incentive schemes forming well over 20 per cent. of the total earnings have also shown considerable increase.

This should not, however, make us complacent. It is just possible that the rate of increase attained in the current year may not be sustained in the remaining two years of the Third Plan. For instance, sugar which is expected to account for exports worth Rs. 30 crores during the current year may not go beyond Rs. 15 crores next year due to lack of exportable surplus. Again, in the case of jute the encouraging trend of Rs. 175 crores in 1963-64 as against Rs. 155 crores in the previous year may not be continued in the year to come as the increase in the demand in the world markets is not likely to continue. Further, in respect of oil cakes, the increase in exports in the last two years of the Third Plan might just be moderate because of increasing domestic demand. Nor are the prospects in the case of textiles brighter.

One of the major handicaps to exports lies in the rising costs of Indian goods brought about by fiscal levies, growing labour costs, low productivity, paucity of raw materials, administrative delays and the like little effort seems to have been made to show any improvement in this. The problem of exports cannot be dealt with in isolation and must, in the nature of things, form part of the national endeavour to create surpluses at reduced costs. It cannot be overemphasised that having regard to the increased foreign exchange content of our developmental programmes (heightened on account of defence requirements), the country's repayment obligations, and the fact that the scope for any significant pruning of the country's import bill is very limited, there is imperative need for an all-out effort to solve our export problem in a concerted and urgent manner.

Sir, slow progress is taking place in the matter of oil exploration particularly in Gujarat and in the setting up of refineries. I must repeat that Gujarat suffers from lack of coal. Coal has to be hauled to Gujarat from a thousand miles away. Gujarat suffers from lack of power. The hydro-electric schemes promised to Gujarat during the last two elections by the Congress Party as a sop to the voters have not yielded any power yet. And with the coming of the next election, the carrot of the Narbada Valley scheme is being dangled before the voters of Gujarat. How many years is this Narbada Valley scheme going to stay? We know the fate of the Kakrapara and the Mahi schemes. Is the execution of the Narbada Valley scheme going to be on the same lines? How much of the money allocated for these schemes is going to be spent on administrative set-ups, on payment of salaries to officers and staff, and how much of it is going to be actually used on the working of the scheme, is a matter of doubt if the past experience is any guess. It is going to be very, very unsatisfactory.

Before I conclude, I must say that I agree with my friend, Shri Ganga Sharan Sinha, about the serious omission in the President's Address to refer to the loss to the country in the death of Dr. Rajendra Prasad. It is one more instance of the sickness that our Government suffers from.

کہ پارلیمنٹ کے ممبرس یا وہ لوگ جو ہندوستان کی حکومت میں آ جاتے ہیں وہ اپنے پرانے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں - لہذا ہم کو اس کمی کو پورا کرنی چاہئے -

شری اے - ایم - طارق : جناب والا - میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نائب صدر کے بھاشن پر بولنے کا موقع دیا ہے - ہمارے بزرگ ممبر گنگا بابو نے ہمارے سامنے اس چیز کو رکھا ہے کہ جہاں اس بھاشن میں پریزیڈنٹ کلھدی کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات کہی گئی ہے، وہاں اس ملک کی اس عظیم شخصیت کا جس نے اس ملک کی آزادی کی جنگ میں کافی قربانی کی - یعنی ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ان کے خلوص، ان کی محبت، ان کے ایثار، ان کی وطن پرستی سے واقفیت نہ رکھتا ہوگا انہوں نے اس ملک میں ایک سب سے بڑی چیز پر زور دیا تھا وہ ہندو مسلم اتحاد تھا، ان کے صداقت آشرم کو کبھی بھی ہندوستان کے لوگ نہیں بھولیں گے، لیکن اس عظیم شخصیت کا ذکر ہمارے اس ایڈریس میں کرنا ہم بھول گئے ہیں - میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا جائے ورنہ ہندوستان کے لوگ یہ سمجھینگے

میں اس ایڈریس کی اور باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن ایک مسئلہ ہے جس سے میں ذاتی طور پر وابستہ ہوں، جس کے ساتھ میری وابستگی میرا مستقبل ہے، میری اولاد کا مستقبل ہے اور اس ملک کے رہنے والوں کا مستقبل ہے - وہ ہے کشمیر کا مسئلہ - جناب والا - اس ملک میں اور اس ایوان میں بہت لوگ ہیں جنہیں انتہائی تکلیف ہوئی یہ سن کر کہ امریکہ اور انگریز نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اور جو کہ بہت افسوس ناک ہے لیکن وہ لوگ جو کشمیر کے سوال سے واقف ہیں - جو کشمیر کی تحریک آزادی سے واقف ہیں - جو ہندوستان کو آزادی کس طرح سے دی گئی، ان حالات سے واقف ہیں، ان کے لئے انگریز اور امریکہ کا یہ رول کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو سلوک ہماری شکایت کے ساتھ اقوام متحدہ میں ہوا اور اس کے بعد جس وقت ہم پر چینی حملہ ہوا، اس دور میں بھی جو رول انگریز اور امریکہ کا رہا ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ

کیا تھا اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ کشمیر پر کس طرح سے حملہ کرنا چاہئے - اس وقت یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ جب ہم کسی ایک گروہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں - ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ انگریزوں کی دشمنی ہے اور وہ ہونی چاہئے - میں اس پوری تاریخ کو جو انگریزوں کی اس ملک میں رہی ہے ایک شعر میں بیان کر سکتا ہوں -

ان کا آنا حشر سے کچھ کم نہ تھا
اور جب پلٹے قیامت ڈھا گئے

انگریز جس طرح ہندوستان کو چھوڑ کر گئے اس کے زخم ہم پر اور سو سال تک رہیں گے - یہ انگریزوں کی سازش کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں ہندو مسلم فسادات ہو جاتے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا خون کیا جاتا ہے - یہ بیج انگریزوں کا بویا ہوا ہے - ہم نے صرف کوشش یہ کی تھی کہ اس زمین کی تہہ کو صاف کریں اور ہم اس بیج تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے - اور اس بیج کی جڑ تک -

डा० गोपाल सिंह (नाम निर्देशित) : कंजरवेटिव है, है लेकिन जो वहां का लेबर है और अवाम है, वे खिलाफ नहीं हैं।

[شری اے - ایم - طارق]

یہ دونوں ملک ہندوستان کے ساتھ انصاف کرنا نہیں چاہتے -

یہ بات میں نہیں سمجھ پایا اپنے عزیز دوست سے جو کہ مجھ سے بزرگ ہیں - میرا ایک کیس عدالت میں ہے - اگر میرا وکیل اچھا نہیں ہے، اگر میرا وکیل تھوڑا بہت مشتعل ہو جاتا ہے یا میرا وکیل عدالت کو مشتعل کرتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جج اپنے انصاف کے رخ کو بدل دے - اقوام متحدہ میں یہ بھی ایک بہانہ ہے - یہ بھی کہا گیا ہے کہ شری کرشنا مینن نے کشمیر کے کیس کو اس طرح سے نہیں رکھا - صاحب کشمیر کے کیس کو آپ ایسے رکھئے یا ویسے رکھئے - ہونا وہی ہے جو انگریز اور امریکہ چاہتے ہیں - اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں -

وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے
اقربا میرے کریں قتل کا دعوی کس پر

اگر آپ اس تحریک کے پیچھے جائیں گے - اگر پارٹیشن کے زمانہ میں صوبہ سرحد کے گورنر اولف کیرو کی تقریر کا مضمون پڑھیں گے - اگر آپ کے سامنے وہ خط ہوتا جو گورنر پنجاب سر موڈی نے اس زمانہ میں چودھری خلیل الزماں کو لکھا تھا - سر کیرو نے گورنر کی حیثیت سے مسلمانوں کو مجبور

طرف کشمیری مسلمانوں کے لئے قران اور اسلام کا اسلامی جھنڈا رکھا گیا اور دوسری طرف ان کے سامنے یہ صورت رکھی گئی - ہندو ہندوستان ایک طرف اور اسلامی پاکستان ایک طرف - لیکن کشمیر کے مسلمانوں نے جن کی اکثریت تھی کہا نہیں - یہ سوال ہندو مسلمانوں کا نہیں ہے - یہ سوال بھگوے رنگ کے جھنڈے اور سبز رنگ کے جھنڈے کا نہیں ہے - یہ جنگ بھگوت گیتا اور قران کی نہیں ہے یہ جنگ اقتصادیات کی ہے اور ہمارے روشن مستقبل کی ہے - جہاں ہمارا روشن مستقبل ہوگا ہم وہیں جائیں گے - کشمیری ابھی فیصلہ کر بھی نہیں پائے تھے کہ ہم پر پاکستانیوں نے حملہ کر دیا - اور اس وقت کشمیریوں کا یہ حال تھا کہ نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی نہ کوئی حکومت تھی - اگر کشمیر کے مسلمان چاہتے تو وہ پاکستان جا سکتے تھے اور آپ ان کو نہیں روک سکتے تھے لیکن کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا - انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے اور ہم ہندوستان میں رہیں گے - اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک آپنے کیا ہے اس کو ذرا دیکھئے کتنے لوگ ہیں اس ایوان میں جو کشمیر کے کسی پولیٹیکل ورکر کو ذاتی طور پر جانتے ہوں گے - آپ نے کشمیری عوام کے ساتھ کیا ناتہ رکھا اور کشمیری لوگوں کے

شری اے - ایم طارق : بہر حال

لیبر حلقوں میں ہم ضرور ہیں لیکن ہمارے علم میں اتنی کمی ہے کہ ڈاکٹر گوپال سنگھ ہمیں کسی راستہ میں ڈال سکتے ہیں لہذا اس میں ہم مساوی طور پر شریک ہیں لیکن اس بات کا دکھ نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہئے، ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کے لوگوں کو، ہندوستان کی پارلیمنٹ کو، کہ کشمیر کی حالت اتنی اچھی کر دیں کہ پھر ہمیں اقوام متحدہ میں انگریزوں کی حمایت کی ضرورت نہ پڑے نہ روس کے ویٹو کی ضرورت پڑے - جب تک ہم کشمیر کی اندرونی حالت کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے پاس یہ خوف رہے گا، یہ خوف ہم لوگوں میں خوامخواہ پیدا کر رکھا ہے - پچھلے سولہ سترہ سالوں میں سارے ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا - ہندوستان کی حکومت نے، ہندوستان کے عوام نے، ہندوستان کے سیاست دانوں نے ان کے ساتھ ستم کئے اور ان معصوم، بے گناہ شریف النفس کشمیریوں کی تاریخ سے آپ سب واقف ہیں - آپ جانتے ہیں کہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو جب اس ملک کی تقسیم اس بنیاد پر ہوئی کہ ہندو ہندوستان میں رہے گا اور مسلمان پاکستان میں رہے گا - ایک

[شری اے - ایم طارق]

ساتھ آپ کے کیا تعلقات اور کیا سیاسی رشتہ ہے - لیکن آپ نے وہاں کی جنتا کے سامنے کبھی شیخ عبداللہ اور کبھی بخشی غلام محمد کو پیش کیا - آپ کا تعلق کشمیری عوام کے ساتھ کبھی نہیں رہا اور نہ کشمیری عوام کو یہ معلوم ہے کہ اٹل بہاری باجپئی کون ہیں، بھوپیش گپتا کون ہیں، مسٹر بھارگو کون ہیں اور گنگا شرن بابو کون ہیں - اس میں آپ کا قصور ہے ہم لوگوں کا نہیں ہے -

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार): हमने अली मुहम्मद तारिक से भी अपना सरोकार रखा ।

شری اے - ایم - طارق : بہر حال آپ نے علی محمد طارق سے کوئی سروکار رکھنے کی کوشش نہیں کی - اس کا کریڈٹ طارق کو ہوگا کہ اس نے اپنے آپ پر ٹھونس دیا اور مجبور کیا کہ آپ اس کو مانیں - آپ نے اسے پہلے ماننے سے انکار کیا - لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے - آج پاکستان کی جو شکایت ہے اگر اس شکایت کو دیکھیں تو اس شکایت کے پیچھے چیز کیا ہے - پاکستان شکایت میں یہ کہتا ہے، مسٹر بھٹو نے یہ کہا ہے - پاکستان کے پریذیڈنٹ کہا ہے اور ان کے سامنے

اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بخشی غلام محمد نے بھی کہا ہے کہ لوگ پلیبسائٹ چاہتے ہیں - پریذیڈنٹ ایوب نے اپنی تقریر میں کہا کہ بخشی غلام محمد نے بھی کہا ہے کہ لوگ شیخ عبداللہ کی رہائی کی مانگ کرتے ہیں - اور یہ کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے - پریذیڈنٹ ایوب نے یہ بھی کہا ہے کہ بخشی صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر میں یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہئے - اگر بخشی غلام محمد نے یہ کہا ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے - اگر اس غلطی کو استعمال کیا ہے پریذیڈنٹ ایوب نے تو یہ ان کی دانائی نہیں ہے، یہ ان کی خود فریبی ہے اور انہوں نے خود بھی دھوکا کھایا اور دنیا کو بھی دھوکا دیا - اس دوران کشمیر میں صرف یہ نعرے لگے تھے کہ موئے مبارک کو حاصل کرو، ہندو مسلمان کا اتحاد زندہ باد موجودہ حکومت کو برطرف کرو - یہ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے - یہ ہندوستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ یہ کہے کہ نہرو کی حکومت کو ہٹا دو - اگر گنگا بابو کہہ سکتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کی حکومت کو ہٹا دو تو وہ پاکستانی نہیں ہیں - لیکن جب علی محمد طارق کہتا ہے کہ جواہر لال نہرو کی حکومت کو ہٹا دو تو میں پاکستانی ہوں -

ایک مکان سے شروع کیا اور ۴۸ مکان پر ختم کیا - جس نے کشمیر میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور وہاں کی اقتصادیات پر قبضہ کیا ہے - اس لئے وہاں کی موٹر ٹرانسپورٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، آئل پمپس پر قبضہ کیا ہوا ہے - جنگلات کے ٹھیکے اور سڑکوں کے ٹھیکے، سنیما هاؤز وہ سب اس کے چلتے ہیں - یہ چند چیزیں ہیں جس پر کسی شہر، کسی ریاست اور کسی ملک کا مستقبل ہوتا ہے لیکن ان سب پر ایک خاندان نے قبضہ کیا ہوا ہے -

اس کے علاوہ آپ پچھلے پانچ دس سال کو اور مہاراجہ کشمیر کے تمام عہد حکومت کو دیکھ لیجئے - چتلے ریپ کے کیسز مہاراجہ کے سارے عہد حکومت میں ہوئے ہیں اس سے زیادہ کشمیر میں ایک ہفتہ میں ہوتے ہیں - لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان شکایتوں کو کاغذ پر درج کرے - میرے پاس ایسے ثبوت ہیں - یہ میرے اخباروں کے ثبوت نہیں ہیں - یہ وہ اخبار ہیں جو کشمیر کے چیرمین لیجسلیٹیو کونسل شیونرائن فوتےدار کی پارٹی کے ہیں ایک ہفتہ میں ان میں چھ ریپس کا ذکر ہے - یہ لڑکی معمولی آدمی کی لڑکی نہیں ہے ایک کرنل کی لڑکی ہے، ایک مسلم گریجویٹ لڑکی ہے اور دو کشمیری پنڈتانیاں ہیں جو اسکول جا رہی تھیں لیکن کسی کا کیس درج نہیں کیا گیا - چھ مہینے سے زیادہ عرصہ گذرا ہے

نہیں ہیں - ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کے اخبار مجھے اس طرح سے دبا نہیں سکتے - مجھے بھی اس ملک میں اس بات کا حق ہے کہ میں ظلم و ستم اور جبر کے خلاف آواز اٹھاؤں - آپ مجھ سے پاکستانی کہکر یہ حق چھین نہیں سکتے - آپ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اقلیت کو جن کی لڑکیوں کی عصمت خطرہ میں ہے، جن کے بچوں کا مستقبل تاریک ہے - آپ کشمیریوں کو پاکستانی کہکر ان کی قربانی اور تاریخ کی توہین کر رہے ہیں - آپ صرف کشمیریوں کی توہین نہیں کر رہے ہیں - آپ اپنے انصاف اپنی دانش مندی اور اپنی سمجھ کی بھی توہین کر رہے ہیں - اگر آپ لوگوں کو موت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے تو کل یہ کہینگے کہ ہندوستان کی اکثریت نے کشمیری اقلیت کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت ظلم کیا، انصاف نہیں کیا - کشمیر کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں - لیکن کشمیر کے مسلمان بھی پاکستانی نہیں ہیں - کشمیر کے ہندو بھی پاکستانی نہیں ہیں اگر کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے نفرت ہو تو جائز ہے - انہوں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی - جو دیکھی ہے تو وہ بخشی غلام محمد کی شکل میں دیکھی ہے - جس نے

[شری اے - ایم - طارق]

اور اب تک ایک ملزم نہیں پکڑا گیا ہے کیونکہ ملزم رولنگ پارٹی کے ممبر ہیں - ملزم وہی ہیں جو بر سراقدار لوگوں کے دوست ہیں - ہم پیالہ ہیں ، ہم نشین ہیں -

حضور والا - آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے جو انگریزوں کو شکست دی وہ توپ سے نہیں دی کیونکہ ہمارے پاس توپیں نہیں تھیں - صرف انگریزوں کے خلاف ہم میں ایک نفرت تھی - قوموں کی نفرت ایٹم بم سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے اور جس کے سامنے تاریخ وہ ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے - آپ کس قوم سے نفرت کریں اور ان پر بار بار ظلم کرنے کی کوشش کریں اور جب وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو ان کی نیشنلیٹی بدلنے کا ڈھنگ بہت آسان نہیں ہے - کسی مسلمان کو اس ملک میں پاکستانی کہنا ایک لحاظ سے آسان ہے -

شری فریدالحق انصاری : ہوم سیکریٹری کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی نعرہ لگا رہے ہیں -

شری طارق : یہ درخواست ہے میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا کہ وہاں پاکستان کا نعرہ لگایا گیا ، وہاں شیخ عبداللہ زندہ باد کا بھی نعرہ لگایا گیا - وہاں ایک وقت یہ نعرہ بھی لگایا گیا جواہرلال مردہ باد - میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں اور اگر کشمیریوں نے یہ نعرہ لگایا ہے جواہر لال نہرو مردہ باد ، تو یہ ان کشمیریوں نے نعرہ لگایا ہے جس کا واحد سہارا جواہر لال نہرو ہے - آپ کو معلوم ہو کہ جب امید ٹوٹ جائے جب یقین کو دھکا لگ جائے جب انسان بے سہارا ہو جائے تو وہ اپنے خدا کو بھی گالی دیتا ہے پنڈت جواہرلال جی نہرو تو ایک طرف ان کشمیریوں سے آپ آج بھی پوچھئے کہ میں واحد انسان تھا کہ جب کشمیر میں گولی چلی تو میں ان زخمیوں کو دیکھنے ہسپتال میں گیا - کوئی بخشی غلام محمد اس ہسپتال میں نہیں گیا کوئی شمس الدین نہیں گیا کیونکہ ان کا گھر سے نکلنا بےحد مشکل ہے - وہ اگر گھر سے باہر بھی آ جائیں تو ان کو پولیس کی پناہ میں بندوقوں اور دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ میں گذرنا پڑتا ہے - میں جب اس ہسپتال میں گیا تو مجھے ان بیماروں نے کہا کہ جب آپ دہلی جائیں تو اس چاچا سے کہیں - اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اب چاچا کو ان کی یاد بھی نہیں ہے - انہوں نے یہ بھی کہا - کہ اس چاچا سے کہنا کہ آج بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو آپنے لال چوک میں کہی تھی اور ہمارے سینوں میں جو × ہندوستانی

گولیاں ہندوستانی جسموں میں ہیں - یہ پاکستانی جسم نہیں ہیں - یہ چند لوگوں نے اپنا ظلم اپنے کرپشن اور اپنی شرارتوں کو چھپانے کے لئے نعرہ لگایا - ہم پاکستانی نہیں ہیں - میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ایک کشمیری کی حیثیت سے کہ کشمیر میں بھی کچھ پاکستانی ہیں - میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو دھوکا دونگا یا جھوٹ بولونگا - وہ ہیں ، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ آج سے پاکستانی نہیں ہیں بلکہ ۱۹۴۱ سے پاکستانی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان میں جائے - ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ہیں لیکن ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بخشی غلام محمد کے ساتھ ہیں لیکن ہندوستان کے دشمن ہیں - کشمیر کی موجودہ حکومت آج کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستانی کہتی ہے اس لئے کہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس کے ظلم اور تشدد کے خلاف - کشمیر میں اگر پاکستانیوں کو کسی نے پناہ دی ہے تو وہ بخشی غلام محمد نے دی ہے اور کسی نے نہیں ، میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں اور میں اس بات کو کسی موقعہ پر اور کسی جگہ پر ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں - - -

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Maharashtra): On a point of order, Sir. The hon. Member may avoid personal references.

SHRI A. M. TARIQ: It is the history of the country. It is not a personal reference.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: You are making references to persons who are not present here.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Let him go on.

AN. HON. MEMBER: Let him go on.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: I am appealing to the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: There is *no point of order. He was the former* Prime Minister there and the Kashmir question cannot be discussed without reference to a person who was the Prime Minister there for ten years. How can you do it?

SHRI A. B. VAJPAYEE: Yesterday, a Congress Member, Shri Deokinandan Narayan, referred to a speech delivered by Shri Golwalkar who was not present in the House. But I did not object to that. Why should Congress Members lose their patience?

AN HON. MEMBER: Because it pinches them.

SHRI P. N. SUPRU: How do you know that Mr. Tariq is not prepared to repeat outside the House what he has said here, and repeat it everywhere?

SHRI A. M. TARIQ: Everywhere, wherever you like. Who is the Chief Conservator of Forests there? Do you know, Mr. Patil?

[Shri A. M. Tariq.]

وہ ایلڈر برادر ھیں نام نہاد کشمیر کے پریذیڈنٹ خورشید احمد خاں کے -

AN HON. MEMBER: Who is he?

SHRI A. M. TARIQ: He is the elder brother of the so-called President of the so-called Azad Kashmir.

آج جو کشمیر میں I.A.S سپرفائل ڈھنگ سے بنائے گئے ان میں سے چند کو شیخ محمد عبداللہ نے پاکستانی ایجنٹ کے نام سے گرفتار کیا تھا - اور آج وہ آئی -اے - ایس میں ھیں - کیا یہ حقیقت نہیں ھے کہ خود بخشی غلام محمد کے دور حکومت میں جب ایک قمی آئی - جی-ریٹائر ھوئے اور جو بھی پیسہ ان کو ملا وہ اس پیسہ کو لے کر پاکستان چلے گئے - آج جس مولوی عباس کو آپ نے گرفتار کیا ھے یہ کہکر کہ وہ پاکستانی ھے -- اس میں دو رائیں نہیں ھیں کہ وہ پاکستانی نہیں ھے -- لیکن پچھلے ایک سال سے وہ کس کی سفارش پر ویزا بدلتا رھا - وہ صرف اس جلوس میں نکلنے سے پاکستانی نہیں ھوا ، وہ پاکستانی اس دن بھی تھا جب کشمیر میں آیا تھا اگر وہ پندرہ دن کے لئے یہاں آیا تھا تو اس کے ویزا کے ریکمینڈیشن کون کرتا رھا اس وقت تک اور آج جب اس نے اس تحریک آزادی میں حصہ لیا تو وہ پاکستانی ھو گیا - یہ کس نے کہا تھا کہ جب اس مہر واعظ کے بزرگ مر گئے تو کس نے اس کی موت کے دن کو تعطیل دے کہکر تمام جموں کشمیر میں چھٹی کرائی تھی اور یہ چھٹی اس وقت کے ھوم منسٹر شری لال بہادر شاستری کی مرضی کے خلاف بخشی غلام محمد نے کروائی تھی - کیا یہ حقیقت نہیں ھے کہ مولوی فاروق جو اس ایکشن کمیٹی کا ممبر ھے اس کی دستار بندی خود بخشی غلام محمد نے کی تھی - اگر یہ سب چیزیں درست ھوں تو آج آپ کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بناتے ھیں - کشمیریوں کا قصور کیا ھے - میں پچھلی باتوں کو چھوڑتا ھوں - میں لائسنس کی بات ، امپورٹ کی بات اور بخشی غلام محمد کی دولت کی بات چھوڑتا ھوں - اللہ نے اس کو دی ھے اور دے - ھو سکتا ھے کہ اس کے جانے کے بعد کچھ حصہ مجھکو بھی مل جائے لیکن سوال دولت کا نہیں ھے - میں دولت کی فکر بھی نہیں کرتا ھوں - حضرت بل میں موئے شریف چوری ھو جاتا ھے اور تاریخ کے پچھلے پانچسو سال ... میں آپ سے صرف درخواست کرونگا اور آپ کی گھنٹی کے خلاف پروٹسٹ نہیں کرونگا -

شری فرید الحق انصاری : ان کو بھان کرنے دیجئے -

شری اے - ایم - طارق - حضرت بل میں موئے شریف کی چوری ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں - وہ یہ کہتے ہیں کہ موئے شریف حاصل کرو - چوروں کا پتہ لگاؤ اور کوئی دوسری بات پہلے دن نہیں ہوتی ہے - لوگ جمع ہو جاتے ہیں لال چوک میں اور دوسری جگہوں میں اور ان کے دو ہی نعرہ ہوتے ہیں کہ موئے شریف حاصل کرو اور چوروں کا پتہ لگاؤ - اوقاف کمیٹی انصاف کرے - اب اوقاف کمیٹی ہے کیا - ؟ اوقاف کمیٹی چند لوگوں کا مجمع ہے جو اس زیارت کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے چیرمین ہیں ہمارے خالق کشمیر جناب مردآهن بخشی غلام صاحب اور اس مرد آهن کے ساتھ ہی اس کے تین قریبی رشتہدار ہیں - ایک ایکس ڈی - آئی - جی - جو ان کے ایک عزیز کے فادر ہیں اور ایک ایکس کسٹوڈین جو ان کے ایک اور عزیز کے فادر ان لا ہیں - ان کے علاوہ دو آدمی ہیں جن میں ایک چھوٹے مرد آهن بخشی عبد الرشید خود ہیں اور ایک متولی ہیں اور یہ سات آدمی اس زیارت کی دیکھ بھال کرتے ہیں - اچانک چوری ہونے سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے پروٹسٹ کیا - بخشی غلام محمد کے اثر کا نتیجہ تھا کہ ریڈیو کشمیر نے اس کو اناونس نہیں کیا - آل انڈیا ریڈیو نے بھی کچھ وقت کے لئے اس کا ذکر نہیں کیا اور پریذیڈنٹ ایوب خاں نے نیوز فلیش کی - پاکستانیوں نے کہا کہ اسکا چرانے والا ہندو ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر مشرقی پاکستان میں غریب ہندو ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور ہندوستان میں ، کلکتہ میں ، غریب مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوئے -

لیکن آپ ذرا اس بات کو غور سے دیکھئے - معزز ممبران پارلیمنٹ میں چیئر کے ذریعہ سے اس بات کی درخواست کرونگا کہ آپ اس بات کو دیکھئے کہ اس دن اگر آل انڈیا ریڈیو اس خبر کو براڈکاسٹ کر دے کہ چوری کرنے میں مسلمان کا ہاتھ ہے اور ہندو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مشرقی پاکستان میں بے گناہ ہندو نہیں مارا جاتا اور یہاں بنگال میں بے گناہ مسلمان نہیں مارا جاتا تو اس اثر کو دیکھئے کہ ایک اہم واقعہ کی خبر کو بھی روکا جا سکتا ہے - اس لئے کہ ایک کشمیری کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے ، اس مردآهن کو جو کہ دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہیں آ سکتا ، اور اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے - تو لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور اس پروٹسٹ میں کشمیر کے ہندو شامل

جلانے کے بعد اس گاڑی کو عظیم‌الشان طریقہ سے دریابرد کر دیا - وہ کار سرکاری تھی - ان کی اپنی نہیں تھی - اس کے بعد یہ ہجوم بخشی غلام محمد کی طرف جاتا ہے لیکن اس جائیداد کے پہلے اور اس جائیداد کے بعد غیر مسلمانوں کی لاکھوں روپیوں کی دوکانیں ہیں - جنھوں نے ریپیڈینسی روڈ کو دیکھا ہے - ڈاکٹر گوپال سنگھ یہاں ہیں؟ باجپئی صاحب یہاں ہیں -- وہ جانتے ہوں گے کہ لاکھوں روپیوں کی ہندوؤں کی یہاں جائیداد ہے لیکن کسی ہندو کی جائیداد کو نہیں چھیڑا گیا بلکہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جن کی دوکانیں کھلی ہوئی تھیں ان پر کپڑا ڈالا کہ ان کو نہیں جلایا جائے گا اور اس خاندان کی جائیداد کو ہی جلانا ہے - تو ان کو اتنا صدمہ تھا، ان کو اتنا غصہ تھا - جب کسی قوم کا غصہ کسی فرد کی طرف ہو جائے تو حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ سنگین نکالے اور لوگوں کے غصہ کا جواب دے بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے غصہ کا علاج کرے - اس جائیداد کو جلانے کے بعد لوگ واپس چلے آئے اور وہ کسی اور کی جائیداد کو نہیں جلاتے - اب گولی چلائی جاتی ہے - میری ایک شکایت ہے جو حکومت کے سامنے بھی ہے - ایک ایس - پی -

[شری ے - ایم - طارق]

تھے ؟ مسلمان شامل تھے ؟ سکھ شامل تھے اور کوئی ہندو مسلم فساد کی بات نہیں تھی - اچانک جب لوگ یہ سمجھ کر کہ حضرت بل جائینگے اکٹھے ہوئے تب بخشی عبدالرشید صاحب تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں سرکاری موٹر میں، اس کا جے - اینڈ کے - ۱۴ نمبر ہے ؟ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ؟ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں — میں اس کا اردو ترجمہ کرونگا اور آپ میری ان باتوں کو انٹیلیجنس رپورٹ سے پوری دیکھ سکتے ہیں - وہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ بھکاریو و فقیرو ؟ تمہاری کانگڑی میں آگ نہیں ہے . تم کیوں جلوس نکالنے آئے ہو ؟ جاو ؟ موئے شریف وہاں پہنچ جائینگا - لوگوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور ان کے پاس جتنی کانگڑیاں تھیں وہ سب کانگڑیاں عبدالرشید صاحب کے سر پر قربان کر دیں اور کہا کہ دیکھو ان میں آگ ہے کہ نہیں - وہ دو تین سو کانگڑیاں ان کے سر پر نچھاور کر دیں - جیسے کہ ہم ایک دوسرے پر پھول نچھاور کرتے ہیں - اسی آسانی سے وہ کانگڑیاں ان پر نچھاور کر دیں - کسی طرح یہ دوسرے مرد آہن غائب ہو گئے تو لوگوں نے ان کی سرکاری گاڑی کو جلایا اور

و دماغ کو، ہمارے خلوص کو ہماری محبت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہئے ہیں -- تو پ بھی ہم سے خلوص و محبت کا برتاو کیجئے - آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ کو، ہندوستان کے لوگوں کو، ہندوستان کے اخباروں کو، ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہ آپ کو ایک خاندان وہاں چاہیئے یا ۳۲ لاکھ انسان چاہیئں - آپ کو کشمیر کی پہاڑیاں چاہیں، آپ کو کشمیر کے سبزہ زاروں میں، کشمیر کی جھیلوں اور پھلوں میں دلچسپی ہے یا کشمیر کے انسانوں میں دلچسپی ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے - ہم تو کر چکے، یہ آپ کو کرنا ہے -

گلنا بابو کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ اس ایڈریس میں مرحوم ڈاکٹر راجندر پرشاد کا نام نہیں ہے، مجھکو بھی بہت ناگوار گزرا لیکن ہم کشمیریوں کو بھی ناگوار گزرا جب ہم پر گولی چلی تب کسی نے، نہ اٹل بہاری باجپئی نے منہ کھولا، نہ بھوپیش گپتا نے منہ کھولا اور نہ گلنا بابو کوئی ڈیلیگیشن لے کر گئے - اب تک نہیں گئے تو اب جاو، اب بھی جاکر دیکھو کہ کشمیری کس حال میں ہیں، کشمیر کی ماوں سے پوچھو، کشمیر کی بہنوں سے پوچھو، وہاں کے بچوں سے پوچھو - نے پستول سے ایک ہندو کو نشانہ بنا کر اس کو ایم کر کے گولی چلا دی تاکہ اس ہندو کے مرنے سے ہندو مسلم فساد ہو جائے - یہ میں آپ سے ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے جو اپنے فرائض اور ذمہ-داریوں کو جانتا ہے کہتا ہوں کہ ایک ایس - پی- ایم کرتا ہے اور ایک ہندو کو جو کشمیر کا نہیں تھا، جو سیبا کا نوکر تھا، جو جلوس سے کافی دور تھا، اس کے قریب نہیں تھا، اپنی ریوالور سے مارتا ہے اور اب تک، اس معاملے میں کچھ نہیں کیا گیا - اس کے بعد ہندو مسلم فسادات کو کرانے کی کوشش کی گئی، کسی پر پاکستانی ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر جن سنگھی ہونے کا الزام لگایا گیا -

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیئے- اس لئے نہیں کہ کشمیر بہت خوب صورت جگہ ہے بلکہ اس لئے کہ کشمیر آپ کے سیکولرزم کا نمائندہ بنا ہے اور کشمیریوں کو یہ تمنا ہے کہ وہ اسی ملک میں مریںگے، اسی ملک میں جیئیں گے، لیکن اگر آپ کو واقعی کشمیری قوم کو اپنے ساتھ لانا ہے -- اس کے — یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے علیحدہ ہیں، آپ ہمارے جسم کو ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے دل

یہ جانتے ہیں کرن سنگھ بہت اچھے اور بہت پاپولر ہیں - آپ کو دیکھنا چاہئے کہ کیا کیا حرکتیں کشمیر میں ہو رہی ہیں یا کشمیر میں وہ لوگ کر رہے ہیں - ہندوستان میں ایم - ایل - ایز - کا ڈیلیگیشن لے کر آتے ہیں - بتایئے ایم - ایل - ایز - کیا ہیں - اس سے کیا ہوگا - کشمیر کے اس مرد آہن سے کہئے کہ ذرا سری نگر کی سڑک پر چلے - میں چیلنج کرتا ہوں، میں اور بخشی غلام محمد ہاتھ میں ہاتھ دے کر سری نگر کی گلیوں میں نکلیں اور جو اپنے کپڑوں میں گھر واپس آ سکے وہی پرائم منسٹر ہے - یہ جرات ان میں نہیں ہے - ایم - ایل - ایز - کو لے کر یہاں آنے سے کیا فائدہ ؟ کیوں نہیں کانگریس پریزیڈنٹ کو جموں اور سری نگر میں بلاتے اور وہاں کا نمونہ دکھاتے ؟ یہاں کانگریس پریزیڈنٹ کے پاس آنے کی کیا بات ہے ان کو ذرا وہاں بلا کر دکھایئے -

श्री बैरागी द्विवेदी : (उड़ीसा) : क्या प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया को यह पता नहीं है ?

شری فریدالحق انصاری : یہ سب ان کو پتہ ہے -

श्री बैरागी द्विवेदी : यानी इनको भी पता है ।

شری اے - ایم - طارق : ہم آپ سب کو پتہ ہے - اس میں آپ

[شری اے - ایم - طارق]

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر میں آج چنگیز خاں کے نام میں اور بخشی غلام محمد کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے -

श्री ए० बी० वाजपेयी : जो वहां जाते हैं उन्हें पीटा जाता है ।

شری اے - ایم - طارق : جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ مار سے نہیں ڈرتے -

श्री ए० बी० वाजपेयी : काश्मीर में बुरी तरह से मारते है , बेहद मार पड़ती है ।

شری اے - ایم - طارق : آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہئے -

श्री ए० बी० वाजपेयी : अशोक मेहता का क्या हुआ ?

شری اے - ایم - طارق : اچھا ہوا اور وہ پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیرمین ہو گئے - آپ بھی مار کھایئے - آپ بھی کچھ ہو جائیں گے - ایسی بات نہیں ہے - آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے -

لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کشمیریوں کو دکھ ہے کہ ہم سے کوئی سیاسی تعلق بھی ہندوستان کے لوگوں نے نہیں رکھا - آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کرن سنگھ ڈوگرا ہیں جو افسوس کی بات ہے - یہ ہم کشمیری نہیں جانتے - ہم تو صرف

نے کشمیریوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جواہرلال ہی نہیں ان کے ساتھ گلزاری لال نندا بھی ہیں، اٹل بہاری باجپئی ہیں، بھوپیش گپتا ہیں، گوپال سنگھ بھی ہیں - وہ بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں -

उपसभाध्यक्ष (महाबीर प्रसाद भार्गव). तारिक साहब, आधा घटा हो चका है ।

شری اے - ایم - طارق : میں آپ کا بے حد مشکور ہوں - ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں انگریزوں کو، امریکنوں کو شکست دینی ہے تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ کشمیریوں کے زخم کا علاج کیا جائے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر ان زخموں کا علاج کریں گے -

†[**श्री ए० एम० तारिक़** जनाबे-वाला, मै आपका मशकूर हू कि आपने मुझे नायब सदर के भाषण पर बोलने का मौका दिया है । हमारे बुजर्ग मेम्बर गगा बाबू ने हमारे सामने इस चीज को रखा है कि जहा इस भाषण मे प्रेजीडेन्ट कैनेडी का जिक्र किया गया है, जो कि एक अच्छी बात कही गई है वहा इस मुल्क की उस अजीम शख्सीयत का जिसने इस मुल्क की आजादी की जग में काफी कुर्बानी की याने हिन्दुस्तान मे शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो उनके खुलूस, उन की मुहब्बत, उनके ईसार, उनकी वतनपरस्ती से वाकफियत न रखता होगा और जो उन्होंने इस मुल्क मे एक सब से बड़ी

†[ ] Hindi transliteration

سب شریک ہیں - اس میں آپ بھی ہیں - آپ صرف کانگریس میں نہیں ہیں اور بھی کچھ ہیں - اس میں پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں سب ہیں، صادق علی صاحب بھی ہیں، گوپال سنگھ صاحب بھی ہیں، سب ہیں -

تو اس کو آپ اجتماعی شکل میں دیکھئے - اگر کشمیر کی حالت بگڑے گی تو یہ غلط بات ہوگی، سارے ہندوستان کے نقشے کو بدلنا ہوگا - یہ صرف چند لوگوں کا سوال نہیں ہے، پوری نوازیخ کا سوال ہے - میں آج پوچھتا ہوں کون چیز روکتی ہے گلزاری لال نندا کو، بھوپیش گپتا کو، اٹل بہاری باجپئی کو، صادق علی صاحب کو کہ اکٹھا جا کر کم سے کم اس قوم کی حالت کو معلوم کریں - اگر آپ ان کے زخم پر مرہم نہیں لگا سکتے ہو تو ان کا زخم تو دیکھ سکتے ہو جو زخم دیکھنے سے انکار کرتا ہے وہ انسان نہیں - وہ جاتے ہیں کہ کوئی آکر ان کے زخم کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر ان سے کوئی پوچھے کہ تم پر کیا گذری ہے - اتنا تو کرو - یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے ورنہ یہ بھی واقعہ ہے کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں اس لئے ہیں کہ وہاں جواہرلال ہیں، وہاں پی - این - سپرو ہیں - آپ

[श्री ए० एम० तारिक]

चीज पर जोर दिया था वो हिन्दू-मुस्लिम इत्तफाक था, उनके सदाकत आश्रम को कभी भी हिन्दुस्तान के लोग नहीं भूलेंगे. लेकिन उस अजीब शख्सीयत का जिक्र हमारे इस एड्रेस में करना हम भूल गये हैं । मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस कमी को किसी न किसी तरह पूरा किया जाये । वरना हिन्दुस्तान के लोग यह समझेंगे कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स या वो लोग जो हिन्दुस्तान की हुकूमत मे आ जाते हैं वो अपने पुराने बुजुर्गों को भूल जाते है । लिहाजा हमको इस कमी को पूरा करना चाहिये ।

मैं इस एड्रेस की और बातों की तरफ नहीं जाऊंगा लेकिन एक मसला है जिससे मैं ज़ाती तौर पर बावस्ता हूं, जिसके साथ मेरी बाबस्तगी मेरा मुस्तकबिल है, मेरे ओलाद का मुस्तकबिल है और इस मुल्क के रहनेवालों का मुस्तकबिल है । वह है काश्मीर का मसला : जनाबवाला, इस मुल्क में और इस एवान में बहुत लोग है जिन्हें इन्तहाई तकलीफ हुई यह सुन कर कि अमरीका और अंग्रेज ने क्या रवैया अख्त्यार किया है, और जो कि बहुत अफसोसनाक है, लेकिन वो लोग जो कश्मीर के सवाल से वाकिफ हैं, जो कश्मीर की तहरीके आजादी से वाकिफ हैं, जो हिन्दुस्तान को आजादी किस तरह से दी गई उन हालात से वाकिफ हैं, उनके लिये अंग्रेज और अमरीका का यह रोल कोई नई चीज नही है और हम लोग जानते है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो सलूक हमारी शिकायत के साथ एकवामेमुत्तहिदा में हुआ और उसके बाद जिस वक्त हम पर चीनी हमला हुआ उस दौर में भी जो रोल अंग्रेज और अमरीका का रहा है वह इस बात की जानत है कि ये दोनों मुल्क हिन्दुस्तान के साथ इंसाफ करना नहीं चाहते ।

यह बात मै नही समझ पाया अपने अजीज दोस्त से जोकि मुझसे बुजुर्ग हैं । मेरा एक केस अदालत में है । अगर मेरा वकील अच्छा नही है अगर मेरा वकील थोड़ा बहुत मुश्तइल हो जाता है या मेरा वकील अदालत को मुश्तइल करता है तो इसके मायने यह नहीं है कि जज अपने इंसाफ के रुख को बदल दे । अक्वामेमुत्तहिदा में—यह भी एक बहाना है —यह भी कहा गया है कि श्री कृष्णा मेनन ने कश्मीर के केस को इस तरह से नही रखा । साहब, कश्मीर के केस को आप ऐसे रखिये या वैसे रखिये । होना वही है जो अंग्रेज और अमरीका चाहते है । इसके मुताल्लिक मै यह कहना चाहता हूं —

वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे
अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर

अगर आप इस तहरीक के पीछे जायेंगे । अगर पार्टीशन के जमाने में सूबा सरहद के गवर्नर ओलफ कैरो की तकरीर का मजमून पढ़ेंगे । अगर आपके सामने वो खत होता जो गवर्नर पंजाब सर मूडी ने उस जमाने में चौधरी खलीकुज्जमान को लिखा था । सर कैरो ने गवर्नर की हैसियत से पठानों को मजबूर किया था और उन्होंने समझाया था कि कश्मीर पर किस तरह से हमला करना चाहिये । इस वक्त ये हमारी इन्तहाई बदकिस्मती है कि हम ऐसे माहौल में है कि जब हम किसी एक गिरोह को नाराज नही कर सकते है, वरना यह हकीकत है कि हमारे साथ अंग्रेजों की दुश्मनी है और वो होनी चाहिये । मै इस पूरी तारीख को जो अंग्रेजों की इस मुल्क में रही है एक शिइर में बयान कर सकता हूं—

उन का आना हश्र से कुछ कम न था
और जब पल्टे कयामत ढा गये ।

अंग्रेज जिस तरह हिन्दुस्तान को छोड़ कर गये उसके जख्म हम पर और सौ साल तक रहेंगे । यह अंग्रेजों की साजिश का नतीजा है जिसकी वजह से इस मुल्क में हिन्दू मुस्लिम फसादात हो जाते हैं और बेगुनाह इंसानो का खून किया जाता है । ये बीज अंग्रेजों का बोया हुआ है ।

हमने सिर्फ कोशिश यह की थी कि इस जमीन की तह को साफ करे और हम इस बीज तक भी नही पहुचे होंगे और इस बीज की जड तक

डा० गोपाल सिह (नाम निर्देशित) कजरवेटिव हल्के खिलाफ है लेकिन जो वहा का लेबर का हल्का है और अवाम है, व खिलाफ नही है ।

श्री ए० एम० तारिक़ बहरहाल लेबर ल्को मे हम जरूर है लेकिन हमारे इल्म मे इतनी कमी है कि डा० गोपाल सिह हमे किसी रास्ते मे डाल सकते है लिहाजा इसमे हम मसावी तौर पर शरीक है लेकिन इस बात का दुख नही होना चाहिये बल्कि हम को यह कोशिश करनी चाहिये, हिन्दुस्तान की हुकूमत को, हिन्दुस्तान के लोगो को, हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट को कि कश्मीर की हालत इतनी अच्छी कर दे कि फिर हमे अक्वामेमुत्तहिदा मे अग्रेजो की हिमायत की जरूरत न पडे, न रूस के वीटो की जरूरत पडे । जब तक हम कश्मीर की अदरूनी हालत को ठीक नही करते उस वक्त तक हमारे पास यह खौफ रहेगा, यह खौफ हम लोगों मे ख्वामख्वाह पैदा कर रक्खा है । पिछले सोलह सत्रह सालो से सारे हिन्दुस्तान ने कश्मीर के साथ इसाफ नही किया । हिन्दुस्तान की हुकूमत ने, हिन्दुस्तान के अवाम ने, हिन्दुस्तान के सियासतदानों ने उनके साथ सितम किये और उन मासूम बेगुनाह, शरीफ-उन नफस कश्मीरियें की तारीख से आप सब वाकिफ है । आप जानते है कि पद्रह अगस्त, १९४७ को जब इस मुल्क की तकसीम इस बुनियाद पर हुई कि हिन्दू हिन्दुस्तान मे रहेगा और मुसलमान पाकिस्तान मे रहेगा । एक तरफ कश्मीरी मुसलमानों के लिये कुरान और इस्लामी झडा रख गया और दूसरी तरफ उनके सामने यह सूरत रक्खी गई—हिन्दु हिन्दुस्तान एक तरफ और इस्लामी पाकिस्तान एक तरफ । लेकिन कश्मीर के मुसलमानो ने जिनकी अक्सरियत थी कहा, नही । यह सवाल हिन्दू मुसलमानो का नही है । यह सवाल भगवेरग के झडे और सब्ज रग के झडे का नही है । यह जग भगवत गीता और कुरान की नही है, यह जग एक्त-सादियात की है और रोशन मुस्तकबिल की है जहा हमारा रौशन मुस्तकबिल होगा हम वह जायेंगे । कश्मीरी अभी फैसला कर भी नही पाये थे कि हम पर पाकिस्तानियो ने हमला कर दिया और उस वक्त कश्मीरियो का यह हाल था कि न उनके पास कोई फौज थी न कोई हुकूमत थी । अगर कश्मीर के मुसलमान चाहते, तो वो पाकिस्तान जा सकते थे और आप उनको नही रोक सकते थे लेकिन कश्मीर के मुसलमानो ने पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया । उन्होने यह कहा कि हमारा वतन हिन्दुस्तान है और हम हिन्दुस्तान में रहेगे। इसके बाद उनके साथ जो सलूक आपने किया है उसको जरा देखिये । कितने लोग है इस ऐवान में जो कश्मीर के किसी पोलिटिकल वर्कर को जाती तौर पर जानते होगे और आपने कश्मीरी अवाम के साथ क्या नाता रक्खा और कश्मीरी लोगो के साथ आप के क्या ताल्लुकात और क्या सियासी रिश्ता है । लेकिन आपने वहा की जनता के सामने कभी शेख अब्दुल्ला और कभी बख्शी गुलाम मोहम्मद को पेश किया । आप का ताल्लुक कश्मीरी अवाम के साथ कभी नही रहा और न कश्मीरी अवाम को यह मालूम है कि अटल बिहारी बाजपेयी कौन है, भूपेश गुप्ता कौन हैं, मिस्टर भार्गवा कौन है और गगा शरण बाबू कौन हैं । इसमे आपका कुसूर है । हम लोगों का नही है ।

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिह (बिहार) · हमने अली मुहम्मद तारिक से भी अपना सरोकार रखा ।

श्री ए० एम० तारिक़ बहरहाल, आपने अली मोहम्मद तारिक से कोई सरोकार रखने की कोशिश नही की, इसका क्रेडिट तारिक

[श्री ए० एम० तारिक]

को होगा कि उसने अपने आपको आप पर ठूस दिया और मजबूर किया कि आप उसे माने। आपने उसे पहले मानने से इकार किया। लेकिन यह मसला ऐसा नही है। आज पाकिस्तान की जो शिकायत है उस शिकायत को देखे तो उस शिकायत के पीछे चीज क्या है? पाकिस्तान शिकायत मे यह कहता है, मिस्टर भुट्टो ने यह कहा है, पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट ने कहा है, कि उनके सामने इससे बडा सबूत क्या हो सकता है जिसमे उन्होने कहा है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने भी कहा है कि लोग प्लेबीसाइट चाहते है। प्रेजिडेट अयूब ने अपनी तकरीर मे कहा कि बख्शी गुलाम मुहम्मद ने भी कहा है कि लोग शेख अब्दुल्ला की रिहाई की माग करते है। और ये कश्मीर के लोगो का मुतालबा है। प्रेजीडेट अयूब ने यह भी कहा है कि बख्शी साहब ने यह भी कहा है कि कश्मीर मे यह नारा भी लगा था कि कश्मीर का इलहाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिये। अगर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने यह कहा है तो उन्होने यह गलत कहा है। अगर इस गलती को इस्तेमाल किया है प्रेजिडेट अयूब ने तो यह उनकी दानाई नही है, ये उनकी खुदफरेबी है और उन्होने खुद भी धोखा खाया और दुनिया को भी धोखा दिया। इस दौरान कश्मीर मे सिर्फ ये नारे लगे थे कि मुएमुबारक को हासिल करो, हिन्दु मुसलमान का इत्तहाद जिन्दाबाद, मौजूदा हुकूमत का बरतरफ करो। ये कश्मीर के लोगो का हक है। ये हिन्दुस्तान के हर शहरी का हक है कि ये कहे कि नेहरू की हुकूमत को हटा दो। अगर गगा बाबू कह सकते है कि जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत को हटा दो तो वो पाकिस्तानी नही है। लेकिन जब अली मोहम्मद तारिक कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत को हटा दो तो मै पाकिस्तानी हू, नही हू। हिन्दुस्तान की हुकूमत, हिन्दुस्तान के लोग और हिन्दुस्तान के अखबार मुझे इस तरह से दबा नही सकते। मुझे भी इस मल्क में इस बात का हक है कि मै जुल्मोसितम और जब्र के खिलाफ आवाज उठाऊं। आप मुझसे पाकिस्तानी कह कर यह हक छीन नही सकते। आप इस बात को क्यो नही सोचते कि अगर अक्लीयत को जिन का लडकियों की इसमत खतरे मे है, जिनके बच्चो का मुस्तकबिल तारीक है — आप कश्मीरियो को पाकिस्तानी कह कर उनकी कुर्बानी और तारीख की तौहीन कर रहे है। आप सिर्फ कश्मीरियो की तौहीन नही कर रहे है, आप अपने इसाफ, अपनी दानिशमदी और अपनी समझ की भी तौहीन कर रहे है— अगर आप लोगो को मौत के रहमोकरम पर छोडेगे तो कल ये कहेगे कि हिन्दुस्तान की अक्सरीयत ने एक कश्मीरी अक्लीयत के साथ बिलालिहाज मजहबोमिल्लत जुल्म किया, इसाफ नही किया। कश्मीर के लोक पाकिस्तानी नही है। कश्मीर के मुसलमान भी पाकिस्तानी नही। कश्मीर के हिन्दु भी पाकिस्तानी नही है। लेकिन अगर कश्मीर के लोगो को हिन्दुस्तान से नफरत हो तो जायज है उन्होन आपकी शक्ल नही देखी, जो देखी है तो वो बख्शी गुलाम मोहम्मद की शक्ल मे देखी है, जिसने एक मकान से शुरू किया और ४८ मकान पर खत्म किया, जिसने कश्मीर मे किसी चीज को नही छोडा और वहा की इक्नसादियात पर कब्जा किया है। उसने वहा की मोटर ट्रासपोर्ट पर कब्जा किया हुआ है, आयल पम्पस पर कब्जा किया हुआ है, जगलात के ठेके और सडको के ठेके, सिनेमा हाउसेज, वो सब उसके चलते है। ये चन्द चीजे है जिस पर किसी शहर, किसी रियासत और किसी मुल्क का मुस्तकबिल होता है। लेकिन इन सब पर एक खानदान ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा आप पिछले पाच दस साल को और महाराजा कश्मीर के तमाम अहदेहुकूमत को देख लीजिए। जितने रेप के केसेज महाराजा के सारे एहदेहुकूमत मे हुए है उससे ज्यादा कश्मीर मे एक हफ्ते मे होते है लेकिन कोई आदमी ऐसा नही है जो इन शिकायतों को कागज पर दर्ज करे।

मेरे पास ऐसे सबूत है । ये मेरे अखबारों के सबूत नही है । ये वो अखबार है जो कश्मीर के चेयरमेन लेजिस्लेटिव कौसिल, शिव-नारायण फतेदार, की पार्टी के हैं । एक हफ्ते मे उनमे छः रेप्स का जिक्र है । ये लडकी मामूली आदमी की लडकी नही है । एक कर्नल की लडकी है, एक मुस्लिम ग्रेजुएट लड़की है और दो कश्मीरी पंडितानिया है जो स्कूल जा रही थी लेकिन किसी का केस दर्ज नही किया गया । छ महीने से ज्यादा अर्सा गुजरा है और अब तक एक मुजरिम नही पकडा गया है । क्योंकि मुजरिम रूलिंग पार्टी के मेम्बर है । मुलजिम वही है जो बरसरेइक्तदार लोगो के दोस्त है, हम-प्याला है, हम-नशी है ।

हजूरे वाला, आप खुद जानते है कि आपने और हमने जो अंग्रेजो को शिकस्त दी वो तोप से नही दी क्योंकि हमारे पास तोपे नही थी । सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हममे एक नफरत थी । कौमों की नफरत एटम बम से ज्यादा खतरनाक और तबाहकून है और जिसके सामने तारीख है वो इसका अच्छी तरह से देख सकता है । आप किसी कौम से नफरत करे और उन पर बार बार जुल्म करने की कोशिश करे और जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाये तो उनकी नेशनलेटी बदलने का ढंग बहुत आसान नही है । किसी मुसलमान को इस मुल्क मे पाकिस्तानी कहना एक लिहाज से आसान है ।

श्री फरीदुल हक़ अन्सारी होम सेक्रेटरी कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं ।

श्री ए० एम० तारिक़ : ये दुरुस्त है । मैं इससे भी इंकार नही करता कि वहा पाकिस्तान का नारा लगाया गया । वहा शेख अब्दुल्ला जिन्दाबाद का भी नारा लगाया गया । वहा एक वक्त यह भी नारा लगाया गया कि जवाहर लाल नेहरू मुर्दाबाद । मैं इससे इंकार नही करता हू और अगर कश्मीरियों ने यह नारा लगाया है "जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद" तो यह उन कश्मीरियों ने नारा लगाया है जिनका वाहिद सहारा जवाहरलाल नेहरू है । आपको मालूम हो कि जब उम्मीद टूट जाये, जब यक़ीन को धक्का लग जाये, जब इंसान बेसहारा हो जाये, तो वो अपने खुदा को भी गाली देता है, पडित जवाहरलाल जी नेहरू तो एक तरफ । इन कश्मीरियों से आप आज भी पूछिये कि मैं वाहिद इंसान था कि जब कश्मीर में गोली चली तो मैं उन जख्मियों को देखने अस्पताल में गया । कोई बख्शी गुलाम मोहम्मद इस अस्पताल मे नही गया, कोई शमसुद्दीन नही गया, क्योंकि उनका घर से निकलना बेहद मुश्किल है । वो अगर घर से बाहर भी आ जाये तो उनको पुलिस की तनाह में और बन्दूकों और दूसरे हथियारों के साये मे गुजरना पडता है । मैं जब उस हस्पताल मे गया तो मुझे उन बीमारो ने कहा कि जब आप देहली जाये तो उस चाचा से कहे---और उनके यह अल्फाज हैं कि अब चाचा को उनकी याद भी नही है---उन्होंने यह भी कहा---कि चाचा से कहना कि आज भी हम इस बात पर यकीन रखते है कि जो आपने लाल चौक में कही थी और हमारे सीने मे जो हिन्दुस्तानी गोलिया है वो हिन्दुस्तानी गोलिया हिन्दुस्तानी जिस्मो मे है, यह पाकिस्तानी जिस्म नही है । यह चन्द लोगों ने अपना जुल्म, अपने करप्शन और अपनी शरारतों को छुपाने के लिये नारा लगाया । हम पाकिस्तानी नही है । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हू एक कश्मीरी की हैसियत से कि कश्मीर मे भी कुछ पाकिस्तानी है । मै उन लोगों मे से नही हू जो आपको धोखा दू या झूठ बोलूगा, वो है, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोडी है और आज से पाकिस्तानी नही है बल्कि १९४६ से पाकिस्तानी है, जो यह चाहते है कि कश्मीर पाकिस्तान में जाये । ऐसे भी कुछ लोग है जो शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ है, लेकिन हिन्दुस्तान के दुश्मन नही है और ऐसे भी बहुत से लोग है जो बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ है लेकिन हिन्दुस्तान के दुश्मन है । कश्मीर की मौजूदा हुकूमत आज कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है इसलिये कि लोग आवाज उठाते है उसके जुल्मो तशदद के खिलाफ । कश्मीर में अगर पाकि-

स्तानियों को किसी ने पनाह दी है तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने दी है और किसी ने नहीं। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं और मैं इस बात को किसी मौके पर और किसी जगह पर साबित करने के लिये तैयार हूं।

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Maharashtra): On a point of order, Sir. The hon. Member may avoid personal references.

SHRI A. M. TARIQ: It is the history of the country. It is not a personal reference.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: You are making references to persons who are not present here.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Let him go on.

AN HON. MEMBER: Let him go on.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: I am appealing to the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: There is no point of order. He was the former Prime Minister there and the Kashmir question cannot be discussed without reference to a person who was the Prime Minister there for ten years. How can you do it?

SHRI A. B. VAJPAYEE: Yesterday a Congress Member, Shri Deokinandan Narayan, referred to a speech delivered by Shri Golwalkar who was not present in the House. But I did not object to that. Why should Congress Members lose their patience?

AN. HON. MEMBER: Because it pinches them.

SHRI P. N. SAPRU: How do you know that Mr. Tariq is not prepared to repeat outside the House what he has said here, and repeat it everywhere?

SHRI A. M. TARIQ: Everywhere, wherever you like. Who is the Chief Conservator of Forests there? Do you know, Mr. Patil?

वह एलडर ब्रदर हैं नाम निहाद कश्मीर के प्रेज़ीडेंट खुर्शीद अहमद खां।

AN HON. MEMBER: Who is he?

SHRI A. M. TARIQ: He is the elder brother of the co-called President of the so-called Azad Kashmir.

आज जो कश्मीर में आई० ए० एस० स्पेशल ढंग से बनाये गये उनमें से चन्द को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी एजेण्ट के नाम से गिरफ्तार किया था और आज वो आई० ए० एस० में हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि खुद बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में जब एक डी० आई० जी० रिटायर्ड हुए और जो भी पैसा उनको मिला वो उस पैसे को लेकर पाकिस्तान चले गये। आज जिस मौलवी अब्बास को आपने गिरफ्तार किया है यह कह कर कि वो पाकिस्तानी है—इसमें दो राय नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी नही है—लेकिन पिछले एक साल से वो किस की सिफारिश पर वीज़ा बदलता रहा ? वो सिर्फ इस जुलूस में निकलने से पाकिस्तानी नही हुआ, वो पाकिस्तानी उस दिन से भी था जब कश्मीर में आया था। अगर वो १५ दिन के लिये यहां आया था तो उसके वीज़ा के रिक्मेन्डेशन कौन करता रहा इस वक्त तक और आज जब उसने तहरीके आजादी में हिस्सा लिया तो वो पाकिस्तानी हो गया। ये किसने किया था कि जब उस मीर वाइज़ के बुजुर्ग मर गये तो किसने उसकी मौत के दिन को नेशनल डे कह कर तमाम जम्मू कश्मीर में छुट्टी करवाई थी और यह छुट्टी उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की मर्जी के खिलाफ बख्शी गुलाम मोहम्मद ने करवाई थी। क्या यह हकीकत नहीं है कि मौलवी फारूक जो इस एक्शन कमेटी का मेम्बर है उसकी दस्तारबन्दी खुद बख्शी गुलाम मुहम्मद ने की थी। अगर ये सब चीजें दुरुस्त हैं तो आज आप कश्मीरियों को

जुल्मोसितम का निशाना क्यों बनाते है । कश्मीरियों का कुसूर क्या है । मैं पिछली बातों को छोडता हू । मैं लाइसेस की बात, इम्पार्ट की बात और बख्शी गुलाम मोहम्मद की दौलत की बात छोडता हू । अल्लाह ने उसको दी है, और दे । हो सकता है कि उसके जाने के बाद कुछ हिस्सा मुझ को भी मिल जाये । लेकिन सवाल दौलत का नही है । मैं दौलत की फिक्र भी नही करता हू । हजरतबल मे मुएशरीफ चोरी हो जाता है और तारीख के पिछले पाच सौ साल मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करूगा और आपकी घटी के खिलाफ प्रोटेस्ट नही करूगा ।

श्री फरीदुल हक़ अन्सारी : इनको बयान करने दीजिए ।

श्री ए० एम० तारिक़ हजरतबल मे मुएशरीफ की चोरी हो जाती है और उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते है । वो यह कहते है कि मुएशरीफ हासिल करो, चोरों का पता लगाओ, और कोई दूसरी बात पहले दिन नही होती है । लोग जमा हो जाते है लाल चौक मे और दूसरी जगहों मे और उनके दो ही नारे होते है कि मुएशरीफ हासिल करो और चोरो का पता लगाओ । औकाफ कमेटी इसाफ करे । अब औकाफ कमेटी है क्या ? औकाफ कमेटी चन्द लोगों का मजमा है जो इस जियारत की देखभाल करते है और उसके चेयरमैन है हमारे खालिदे कश्मीर जनाब मरदेआहन बख्शी गुलाम साहब और उस मरदेआहन के साथ ही उस के तीन करीबी रिश्तेदार है एक एक्स डी० आई० जी० जो उनके एक अजीज के फादर-इन-ला है और एक एक्स कस्टोडियन जो उनके एक और अजीज के फादर-इन-ला है । उनके अलावा जो और आदमी है जिनमें एक छोटे मरदेआहन बख्शी अब्दुल रशीद खुद है और एक मुतवल्ली है और ये सात आदमी इस जियारत की देखभाल करते है । अचानक चोरी होने से लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया । बख्शी गुलाम मोहम्मद के असर का नतीजा था कि रेडियो कश्मीर ने इसको एनाउन्स नही किया । आल इंडिया रेडियो ने भी कुछ वक्त के लिये इसका जिक्र नही किया और प्रेजीडेंट अयूब खा ने न्यूज फ्लैश की । पाकिस्तानियो ने कहा कि इसका चुराने वाला हिन्दू है और इसका नतीजा यह हुआ कि उधर मशरिकी पाकिस्तान मे गरीब हिन्दू जुल्मो सितम का शिकार हुए और हिन्दुस्तान मे कलकत्ता मे गरीब मुसलमान जुल्मो सितम का शिकार हुए ।

लेकिन आप जरा इस बात को गौर से देखिये । मुअज्जिज मेम्बराने पार्लियामेंट मे चेयर के जरिये से इस बात की दरख्वास्त करूगा कि आप इस बात को देखिये कि उस दिन अगर आल इडिया रेडियो इस खबर को ब्राडकास्ट कर दे कि चोरी करने में मुसलमान का हाथ है और हिन्दू का सवाल ही पैदा नही होता तो मशरिकी पाकिस्तान में बेगुनाह हिन्दू नही मारा जाता और यहा बगाल मे बेगुनाह मुसलमान नही मारा जाता । तो इस असर को देखिये कि एक अहम वाकिये की खबर को भी रोका जा सकता है इसलिये कि एक कश्मीरी को नाराज नही किया जा सकता है । उस मरदेआहन को जो कि दिन की रोशनी में घर से बाहर नही आ सकता और उसके खिलाफ कुछ नही किया जा सकता है तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में कश्मीर के हिन्दू शामिल थे, मुसलमान शामिल थे, सिक्ख शामिल थे और कोई हिन्दू मुसलिम फिसाद की बात नही थी । अचानक जब लोग यह समझ कर कि हजरतबल जायेगे इकट्ठे हुए, तब बख्शी अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाते है और तशरीफ लाते है सरकारी मोटर में । उसका जे एण्ड के १४ नम्बर है । वो लोगों को देखते है । बाहर खडे होते हैं और लोगों से फरमाते है—मै इसका उर्दू तर्जुमा करूगा और आप मेरी इन बातों को इंटेलिजेंस

[श्री ए० एम० तारिक]

रिपोर्ट से पूरी देख सकते है---वो लोगों से फरमाते है कि भिखारियो व फकीरो तुम्हारी कागडी में आग नही है, तुम क्यों जुलूस निक लने आये हो, जाओ, मुएशरीफ वहा पहुच जायेगा । लोगों ने इसको अपनी तौहीन समझा और उनके पास जितनी कागडिया थी वो सब कागडिया अब्दुल रशीद साहब के सिर पर कुर्बान कर दी और कहा कि देखो इनमें आग है कि नही । वो दो तीन सौ कागडिया उनके सिर पर निछावर कर दी जैसे कि हम एक दूसरे पर फूल निछावर करते है, उसी आसानी से वो कागड़िया उन पर निछावर कर दी । किसी तरह वो दूसरे मरदेआहन गायब हो गये तो लोगों ने उनकी सरकारी गाडी को जलाया और जल ने के बाद उस गाडी को अज मउशान तरीके से दरियाबुर्द कर दिया । वो कार सरकारी थी, उनकी अपनी नही थी । इसके बाद यह हजूम बख्शी गुलाम माहम्मद की तरफ जाता है लेकिन उस जायदाद के पहले और उस जायदाद के बाद गैर मुसलमानों की लाखों रुपयों की दूकाने है । जिन्होंने रेजिडेन्सी रोड को देखा है---डा० गोपाल सिह यहा है, वाजपेयी साहब यहा है, वो जानते होंगे कि लाखो रुपये की हिन्दुओं की यहा जायदाद है लेकिन किसी हिन्दू की जायदाद को नही छेडा गया बल्कि लोग उनके सामने खड़े हो गये और जिनकी दुकाने खुली हुई थी उन पर कपडा डाला कि उनको नही जलाना है और इस खानदान की जायदाद को ही जलाना है । तो उनको इतना सदमा था, उनको इतना गुस्सा था । जब किसी कौम का गुस्सा किसी फर्द की तरफ हो जाये तो हुकूमत का यह फर्ज नही है कि सगीन निकाले और लोगों के गुस्से का जवाब दे बल्कि हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगो के गुस्से का इलाज करे । इस जायदा को जलाने के बाद लोग वापिस चले आये और वो किसी और की जायदाद को नही जलाते । अब गोली चलाई जाती है । मेरी एक शिकायत है जो कि हुकूमत के सामने भी है । एक एस० पी० ने पिस्तौल से एक हिन्दू को निशाना बना कर, उसको ऐम करके, गोली चला दी ताकि इस हिन्दू के मरने से हिन्दू-मुस्लिम फसाद हो जाय । ये मै आपसे एक मेम्बर पार्लियामेट की हैसियत से जो अपने फरायेज और जिम्मेदारियों को जानता है कहता हू कि एक एस० पी० ऐम करता है और एक हिन्दू को जो काश्मीर का नही था, जो सीबा का नौकर था, जो जलूस से काफी दूर था, उसके करीब नही था, अपने रिवाल्वर से मारता है और अब तक इस मामले मे कुछ नही किया गया । इसके बाद हिन्दू-मुस्लिम फसादात को कराने की कोशिश की गई । किसी पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया गया, किसी पर जनसघी होने का इल्जाम लगाया गया ।

मै आपको यकीन दिलाता हू कि आपको काश्मीर को अपने साथ रखना चाहिये । इसलिये नही कि काश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है बल्कि इसलिये कि काश्मीर आपके सेक्यूलरिज्म का नुमाइन्दा बना है और काश्मीरियों की यह तमन्ना है कि वो इसी मुल्क मे मरेंगे, इसी मुल्क मे जियेंगे । लेकिन अगर आपको वाकई काश्मीरी कौम को अपने साथ लाना है---इसके यह माइने नही है कि हम आपसे अलाहदा है, आप हमारे जिस्म को साथ रख सकते है लेकिन अगर आप हमारे दिल और दिमाग को, हमारे खुलूस को, हमारी मुहब्बत को अपने साथ रखना चाहते है---तो आप भी हमसे खुलूस और मुहब्बत का बर्ताव कीजिये । आपको यह फैसला करना है, हिन्दुस्तान की पार्लियामेट को, हिन्दुस्तान के लोगों को, हिन्दुस्तान के अखबारों को, हिन्दुस्तान की तमाम सियासी जमायतों को कि आपको एक खानदान वहा चाहिये या ३२ लाख इसान चाहिये । आपको काश्मीर की पहाड़िया चाहिये, आपको काश्मीर के सब्जाजारों में, काश्मीर की झीलों और फलों में दिलचस्पी है या काश्मीर के इन्सानों

में दिलचस्पी है, इसका फैसला आपके हाथ में है। हम तो कर चुके यह आपको करना है।

गगा बाबू को यह बहुत नागवार गुजरा कि इस एड्रेस मे मरहूम डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का नाम नही है। मुझको भी बहुत नागवार गुजरा लेकिन हम कश्मीरियो को भी नागवार गुजरा जब हम पर गोली चली तब किसी ने न अटल बिहारी वाजपेयी ने मुह खोला, न, भूपेश गुप्ता ने मुह खोला, और न गगा बाबू कोई डेलीगेशन लेकर गये। अब तक नही गये तो अब जाओ, अब भी जाकर देखो कि कश्मीरी किस हाल मे है। कश्मीर की माओ से पूछो, कश्मीर की बहनो से पूछो, वहा के बच्चो से पूछो, मै आपको यकीन दिलाता हू कि कश्मीर मे आज चगेजखा के नाम मे और बख्शी गुलाम मोहम्मद के नाम मे कोई फर्क नही है।

श्री ए० बी० वाजपेयी : जो वहा जाते है उन्हे पीटा जाता है।

श्री ए० एम० तारिक : जो मरदे-मुजाहिद होते है वो मार से नही डरा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर मे बुरी तरह से मारते है, बेहद मार पडती है।

श्री ए० एम० तारिक आपको इससे डरना नही चाहिये।

श्री ए० बी० वाजपेयी अशोक मेहता का क्या हुआ ?

श्री ए० एम० तारिक अच्छा हुआ और वो प्लानिग कमिशन के चेयरमैन हो गये। आप भी मार खाइये, आप भी कुछ हो जायेगे। ऐसी बात नही है। आपने इस चीज को देखा नही है।

लेकिन सवाल यह है कि आज हम कश्मीरियो को दुख है कि हमसे कोई पियासी ताल्लुक भी हिन्दुस्तान के लोगो ने नही रखा। आज हमसे कहा जाता है कि कर्णसिह डोगरा है, जो अफसोस की बात है। ये हम कश्मीरी नही जानते। हम तो सिर्फ यह जानते है कि कर्णसिह बहुत अच्छे और बहुत पोपुलर है। आपको देखना चाहिये कि क्या क्या हरकते कश्मीर मे हो रही है या कश्मीर मे वो लोग कर रहे है। हिन्दुस्तान मे एम० एल० एज० का डेलीगेशन लेकर आते है। बताइये एम० एल० एज० क्या है। इससे क्या होगा। कश्मीर के इस मरदेआहन से कहिये कि जरा श्रीनगर की सडक पर चले। मै चैलेज करता हू। मै और बख्शी गुलाम मोहम्मद हाथ मे हाथ देकर श्रीनगर की गलियो मे निकले और जो अपने कपडो मे घर वापिस आ सके वहा प्राइम मिनिस्टर है। ये जुर्रत उनमे नही है। एम० एल० एज० को सूकर यहा आने से क्या फायदा। क्यो नही काग्रेस प्रेजिडेन्ट को जम्मू और कश्मीर मे बुलाते और वहा का नमुना दिखाते ? यहा काग्रेस के प्रेजिडेन्ट के पास आने की क्या बात है ? उनको जरा वहा बुला कर दिखाइये।

श्री बैरागी द्विवेदी : (उडीसा) : क्या प्राइम मिनिस्टर आफ इडिया को यह पता नही है ?

श्री फरीदुल हक़ अन्सारी यह सब उनका पता है।

श्री बैरागी द्विवेदी : यानी उनको भी पता है।

श्री ए० एम० तारिक़ हम आप सबको पता है। इसमे आप सब शरीक है। इसमे आप भी है। आप सिर्फ काग्रेस मे नही है। और भी कुछ है। इसमे पार्लियामेट के मेम्बर ही नही है, सब है, सादिक अली साहब भी है, गोपाल सिह साहब भी है, सब है।

तो इसको आप इज्तमाही शक्ल देखिये, अगर कश्मीर की हालत बिगडेगी तो यह गलत बात होगी। सारे हिन्दुस्तान

[श्री ए० एम० तारिक]

के नक्शे को बदलना होगा । ये सिर्फ चन्द लोगो का सवाल नही है । पूरी तारीख का सवाल है। मै आज पूछता हू कि कौन चीज रोकती है गगा बाबू को, भूपेश गुप्ता को, अटल बिहारी वाजपेयी का, सादिक अली साहब को, कि इकट्ठा जाकर कम से कम इस कौम की हालत को मालूम करे । अगर आप उनके जख्म पर मरहम नही लगा सकते हो तो उनके जख्म तो देख सकते हो । जो जख्म देखने से इकार करता है वो इसान नही । वो चाहते है कि कोई आकर उनके जख्म को देखे और इसको देख कर उनसे कोई पूछे कि तुम पर क्या गुजरी है । इतना तो करो यह आपका इखलाकी फर्ज है वरना यह भी बाकिया है कि कश्मीरी यह समझते है कि हम हिन्दुस्तान मे इसलिये है कि वहा जवाहरलाल है, वहा पी० एन० सप्रू है । आपने कश्मीरियो को यह यकीन दिलाना है कि जवाहरलाल ही नही, उनके साथ गगा बाबू भी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, भूपेश गुप्ता है, गोपाल सिह भी है, वो भी इस मुल्क मे रहते है और वो भी तुम्हारे साथ है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) तारिक साहब, आधा घटा हो चुका है ।

श्री ए० एम० तारिक मैं आपका बेहद मश्कूर हू । इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खतम करता हू लेकिन आखिर मे यह कहूगा कि अगर हमे अग्रेजो को, अमरीकनो को, शिक त देनी है तो इसका बेहतर इलाज यही है कि कश्मीरियो के जख्म का इलाज किया जाये और मुझे उम्मीद है कि आप सब मिल कर इन जख्मो का इलाज करेगे ।

श्री ए० बी० वाजपेयी उपसभाध्यक्ष जी, उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी के कर्तव्यो का पालन करते हुए जो अभिभाषण दिया है उसमे न तो कोई रग है, न रस है; भाषण मे न स्पष्टता है न दृढता है, भविष्य के बारे मे उसमे न कोई निसदिग्ध दिशा-निर्देश है और न जो लक्ष्य रखे गये है उनकी पूर्ति का कोई उद्दाम सकल्प ही प्रकट किया गया है । शायद इसका कारण यह है कि नई दिल्ली की राजनैतिक परिस्थिति बडी नाजुक है और उपराष्ट्रपति जी के भाषण पर उसका असर हुआ है । हम ने राष्ट्रपति जी अस्वस्थ है और उपराष्ट्रपति ने उनका भार सम्हाल रहे है प्रधान मन्त्री जी दुर्बल है । कोई उप-प्रधान मन्त्री नही है मन्त्रियो मे इस बात पर विवाद है कि किसका नम्बर एक है, किसका दूसरा, किसका तीसरा, और किसका चौथा । उत्तराधिकार का सघर्ष पूरे जोर पर चल रहा है । नित्य नए गठबन्धन हो रहे है । शतरज पर नयी चाले चली जा रही है । इसका परिणाम देश पर अच्छा नही हो रहा है । जनता निराशा मे जा रही है, प्रशासन ढीला हो रहा है और विदेशो मे जो भारत का चित्र है वह धूमिल पडता जा रहा है । आज, जबकि चीन का सकट टला नही है और पाकिस्तान से किसी भी क्षण सघर्ष की आशका बढ रही है, नई दिल्ली मे यह जो राजनैतिक अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण चल रहा है, उसको दूर करना चाहिये । एक उपप्रधान मन्त्री की हमे आवश्यकता है । वह कौन हो यह तय करना काग्रेस पार्टी का काम है । लेकिन उत्तराधिकार के सघर्ष को लम्बा चला कर, देश के भविष्य के साथ खिलवाड नही किया जाना चाहिये ।

2 P. M

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे राष्ट्र के सामने जो सकट है उनका उल्लेख तो किया गया है, किन्तु उस पर विजय कैसे प्राप्त की जायगी, इस सम्बन्ध मे कोई मार्ग निर्देश नही किया गया है । चीन के सकट की चर्चा की गई है । लेकिन चीन के प्रति हमारी नीति क्या है हम कोलम्बो प्रस्तावो से कब तक बधे रहेगे, इन प्रश्नो का उत्तर नही दिया गया । कोलम्बो प्रस्ताव हमे छूट देते हैं कि हम अपनी सेनाए नेफा मे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक भेजे, मगर अभी तक सेनाए भेजी नही गई है । इस सम्बन्ध

मे श्रीमती भण्डारनायके के पत्र को लेकर जो विवाद खडा हुआ है उसने और भी आशकाएं पैदा हो गई है । क्या सरकार ने श्रीमती भडारनायके को यह आश्वासन दिया है कि भारत की सेनाए मेकमाहन रेखा तक नही जायेगी ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये । यह भी बताया जाना चाहिये कि हम अपनी सेनाए कब वहा भेजेगे । कहा जाता है कि रक्षा प्रयत्न प्रगति के साथ चल रहे है, देश को तैयार किया जा रहा है । दो वर्ष मे हमने देश को कितना तैयार किया है इसकी कसौटी यह है कि नेफा मे हम अपनी सेनाए कब भेजते है । जब नेफा मे हमारी सेनाए थी तब हम चीन के आक्रमण का सफलता के साथ प्रतिकार नही कर सके । बरफ पिघल रहा है, बसन्त की ऋतु आ गई है, कोई दावे के साथ नही कह सकता कि चीन फिर सीमा पर गडबड नही करेगा । इस स्थिति मे नेफा मे हमारी सेना का सीमा तक जाना बहुत आवश्यक है, कोलम्बो प्रस्ताव भी हमे इस बात की अनुमति देते है । फिर हम अपनी सेनाए क्यो नही भेज रहे है ?

चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नही किये । हम कब तक उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहेगे ? यद्यपि कोलम्बो प्रस्तावो मे चीन की सेनाओ द्वारा लद्दाख के क्षेत्र का खाली करने का कोई विधान नही है और यह घोषणा करते हुए भी कि हम आक्रामक को उसके आक्रमण के फलो का उपभोग नही करने देगे, सरकार ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये । मै समझता हू कि वह कोलम्बो देशों के लिये एक कन्सेशन था । लेकिन कोलम्बो देश चीन से अपने प्रस्ताव को मनवा नहीं सके । अब हमे वह कन्सेशन वापस ले लेना चाहिये । हमे स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि जब तक चीन की सेनाए लद्दाख के क्षेत्र को भी खाली नही कर देगी तब तक हम चीन से किसी भी तरह की वार्ता नही करेगे । कोलम्बो देशों से भी हमे कहना चाहिये कि वे चीन को मनाने मे व्यर्थ अपना समय नष्ट नही करे । उन्हे भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करना चाहिये । अभी मोरक्को और ट्यूनिशिया मे सीमा सम्बन्धी विवाद हुआ था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के प्रेसीडेंट नासिर उस विवाद को शातिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते थे । मगर शातिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने की उनकी इच्छा ने उन्हे मोरक्को को आक्रामक कहने से नही रोका । भारत और चीन के विवाद को कोलम्बो देश शाति से सुलझाना चाहते है । विवादो को शान्ति से सुलझाना चाहिये यह भावना मै समझ सकता हू । लेकिन अगर आक्रमण के प्रश्न पर तटस्थता मे विश्वास करने वाले देश चुप रहेगे तो तटस्थता के साथ जो नैतिक बल है वह खत्म हो जायेगा और गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद के रूप मे जनता के सामने आयेगी ।

आज सारे देश का और सदन का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की ओर लगा है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे यह कहने के अलावा कि उन्हे बसाया जायेगा, और किसी नीति का दिग्दर्शन नही किया गया है । जब देश का विभाजन हुआ था तो हमने पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओ को आश्वासन दिया था कि उनके जान, माल और इज्जत की रक्षा के प्रति हम कभी उदासीन नही रहेगे । उन आश्वासनों को अमल मे लाने का अवसर आया है । १९५० मे जब पूर्वी पाकिस्तान मे दगे हुए, तब स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया था और भविष्यवाणी की थी कि नेहरू लियाकत अली पैक्ट पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओ की रक्षा नही कर सकेगा । आज उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है । मगर आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे पश्चिमी बंगाल का ऐसा कोई मन्त्री नही है जो कुर्सी को लात मार कर, सरकार को अपनी नीति बदलने को विवश करे । आज केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे सरदार पटेल की तरह का भी कोई मत्री नही है जो कहे कि अगर पाकिस्तान अपने पूर्वी भाग मे हिन्दुओं की रक्षा नही करेगा तो उन हिन्दुओं को बसाने के लिये पाकिस्तान

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

को जमीन देनी पडेगी । हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी ने भी उस समय घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान सीधी तरह से नही मानेगा तो और रास्ते अपनाए जायेगे—**अदर मेथड्स विल बी अडाप्टड** । आज तो प्रधान मन्त्री जी यह घोषणा करने की स्थिति में नही हैं । मगर पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं का क्या होगा ? उनके सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नही है कि वे मर जाय या जबर्दस्ती अपना धर्म छोड दे, या बेघरबार बन कर भारत माता की गोद मे चले आएं । मगर उनके आने के लिये भी दरवाजे नही खोले गए है—हफ्ते मे दो दिन उन्हे आने के सर्टिफिकेट दिये जायेगे, बाकी पांच दिन नही । राजशाही का हमारा कार्यालय बन्द कर दिया गया । क्या आने वाले शरणार्थी अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिये ढाका जायेगे ? कौन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ? जो हिन्दू भारत मे आना चाहते हैं उनकी रक्षा का कोई इन्तजाम नही है, आने वालों पर गोलिया चलाई जा रही हैं । कल रात मुझे त्रिपुरा से एक तार मिला है । मैं आपकी अनुमति से उसको पढ़ना चाहता हूं :

"One lakh refugees crossed in continuous influex of thousands daily. On sixth evening just on the borders Pakistani police fired on four thousand fleeing refugees from three sides. Hundreds shot dead. Many injured in hospitals Thousands in Pakistan are stranded and being tortured"

नेहरू लियाकत समझौते के अन्तर्गत उन्हें भारत तक सुरक्षित लाने की व्यवस्था की गई थी । अगर पाकिस्तानी उस समझौते का पालन करने के लिये तैयार नही है, तो जो हिन्दू आना चाहते है उन्हे भारत तक सुरक्षित लाने के लिये हमें फौज भेजने के लिये भी तैयार रहना चाहिये । हम उन हिन्दुओं को पाकिस्तान में मरने के लिये नही छोड सकते ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का यह कहना ठीक नही है कि उनके प्रति हमारा केवल नैतिक दायित्व है और कोई सवैधानिक, कानूनी दायित्व नही है । हम उनको दिये गये आश्वासनों के साथ बधे हुए है । वे आश्वासन राजनैतिक है, वे आश्वासन ऐतिहासिक है । देश का बटवारा इसी आधार पर हुआ था कि दोनों देशों के अल्पसख्यकों के साथ न्याय किया जायगा । हमने उस आश्वासन का पालन किया है, पाकिस्तान ने उस आश्वासन का पालन नही किया । एक दृष्टि से पाकिस्तान के कायम रहने का सारा आधार ही खतम हो गया है ।

हमने अपने देश में पवित्र अग्नि को लेकर आए हुए पारसियों को आश्रय दिया । तिब्बत से आये हुए बेघरबार बधु हमारे देश में रहते है । क्या पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के लिये हमारे हृदय में उतनी भी मानवता नही है ? उनके प्रति हम क्या करने जा रहे हैं ? कहा जाता है, हम क्या कर सकते है ? पहला काम तो हम यह कर सकते है कि जो भी आना चाहते है उन्हे आने दें और उनको बसाने की पूरी जिम्मेदारी ले । अभी तक, जो पहले के पुरुषार्थी आये हुये है वे सियालदा की सडकों पर पडे है । उन्हे भी अभी बसाया नही जा सका । आवश्यकता हो तो केन्द्रीय वित्त मत्री नए बजट में एक **रिहैबिलिटेशन लेवी** लगा सकते हैं । सारा देश उन अभागे भाइयों को बसाने के लिये कुछ कर देने में संकोच नही करेगा ।

लेकिन शासन का दृष्टिकोण इस संबध में बदलना चाहिये । एक बडी चिन्ता की बात यह हुई कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों की प्रतिक्रिया कलकत्ते में हुई । कलकत्ते में भी झगड़े हुए ये झगडे नही होने चाहिये और हमें पाकिस्तान की नकल नही करनी चाहिये । लेकिन अगर कलकत्ते की पुलिस और पाकिस्तान तत्व जरा संयम से काम लेते तो कलकत्ते में रक्तपात रोका जा सकता था । कलकत्ते के दगों का आरम्भ विद्यार्थियों के

एक जलूस से हुआ । जलूस शान्ति पूर्ण था और उस जलूस से पहले कलकत्ते में कोई उपद्रव नही हुआ । लेकिन उस जलूस पर हमला किया गया उस पर सोडा वाटर की बोतले फेकी गई तीन विद्यार्थियों को छुरा मार दिया गया और पुलिस ने दीन बन्धु एण्ड्रूज कालेज में घुस कर एक विद्यार्थी को गोली से मार डाला । इसके बाद ही दगे की आग भडकी ।

इस बात की जाच होनी चाहिये कि कलकत्ते के उपद्रव मे पाकिस्तानी तत्वों का कितना हाथ था ? क्या यह सच है कि कलकत्ते में दंगे आरम्भ होने से पहले तरह तरह की अफवाहे फैलाई गई थी ? क्या यह सच है कि पाकिस्तानी तत्वों ने अपने मकान और अपनी जायदाद का पहले से ही बीमा करा लिया था ? क्या यह सच है कि जब दगाग्रस्त क्षेत्र से कुछ मुसलमानों को एक ट्रक से हटाया जा रहा था तो उस ट्रक पे बम फेका गया और एक बम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय के सामने फटा ? बाद में उस ट्रक की पुलिस ने तलाशी ली तो बम बरामद नही हुए किन्तु जब ट्रक आगे चली तो उस में आग लग गई । यह सब कैसे हुआ ? यह ऐसे तथ्य है जिन से जनता के मन मे भ्रम पैदा होता है । उस भ्रम का निराकरण करना बहुत जरूरी है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में जाच होनी चाहिये । कलकत्ते के उपद्रव के सम्बन्ध में यह धारणा पैदा होने देना कि जो कुछ किया वह सब हिन्दुओं ने किया और पाकिस्तान के साथ साठ गाठ करने वाले तत्वों ने कुछ नही किया, यह सच्चाई के खिलाफ होगा यह दुनिया में भारत को बदनाम करने के पाकिस्तानी जाल में फसना होगा । कलकत्ते मे जो कुछ हुआ वह लज्जाजनक है । हमारे देश मे हर एक नागरिक के जीवन की, सम्मान की, रक्षा की जानी चाहिये । लेकिन एक बात साफ समझ ली जानी चाहिये कि अगर हम पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की रक्षा की जिम्मेदारी नही ले सकते तो भारत में साम्प्रदायिक शाति बनाये रखना बहुत मुश्किल होगा । आखिर इस देश में इन्सान रहते है और उनके हृदय में भावना है । कलकत्ते की पुलिस में ऐसे लोग थे जिनके घरवाले पूर्वी पाकिस्तान में कत्ल कर दिये गये । हम उनसे कैसे आशा कर सकते है कि वे अपने कर्त्तव्य का दृढता के साथ पालन कर सकेगे । फिर भी हमें मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना है । जितनी दृढता के साथ कलकत्ते में उपद्रव दबा दिये गये, उतनी ही दृढता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिये ।

हमने इस प्रश्न पर विश्व के जनमत को प्रशिक्षित तथा जागृत करने के लिये कोई बात नही की । पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं पर पर्दा डालने के लिये पाकिस्तान ने काश्मीर का सवाल सयुक्त राष्ट्र सघ में उठाया । पूर्वी पाकिस्तान मे हिन्दुओं का जो नरसहार हो रहा है, उसकी ओर हमने किसी विश्व सगठन का ध्यान नही खीचा ।

भारत मे जो पाकिस्तानी रहते है जिनकी सख्या का हमें पता है । हम क्यों नही उनसे भारत छोडकर जाने के लिये कहते ? आसाम में पाकिस्तानी अवैध रूप से घुस रहे है और घुस आए है उनको निकालने में हमने कमी कर दी है, क्योंकि इस से पूर्वी पाकिस्तान मे दगे हो जायेगे । दगे तो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे है फिर भी हम आसाम मे पाकिस्तानियों को निकालने मे ढिलाई कर रहे है । ८ से १० लाख तक पाकिस्तानी आसाम मे बसे हुए है । पश्चिमी बगाल मे उनकी सख्या ४ लाख है । सारे देश मे सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ५० लाख पाकिस्तानी रह रहे है । उन से कहा जा सकता है कि वे भारत छोडकर पाकिस्तान चले जाये । जो भारत के नागरिक है, मजहब के आधार पर उनके साथ भेद भाव नहीं होना चाहिये । मगर पाकिस्तानियों को दो देशों की नागरिकता का उपभोग करने की छट नहीं देनी चाहिये । पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डालना चाहिये । हमे शिलाग

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

में पाकिस्तान के कार्यालय को बंद कर देना चाहिये, हमें बेरुबाडी के समझौते को तोड देना चाहिये । हमें पाकिस्तान से कह देना चाहिये कि अगर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं करेगा तो भारत की शक्ति में जो भी कदम होगा वह उठायेगा ।

गैर सरकारी तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान जाना चाहिये । कठिनाई यह है कि यह सरकार न तो सरदार पटेल की भाषा में बात कर सकती है और न यह सरकार गांधी जी के कदमों पर ही चल सकती है । शांति और अहिंसा का उपदेश देने वाले क्यों नहीं ढाका और खुलना जाते और वहां के हिन्दुओं की स्थिति देखते? प्रोफेसर हुमायूं कबिर जा सकते हैं, जनरल शाहनवाज खां जा सकते है, हमारे श्री फखरुद्दीन अहमद जा सकते है और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों से कह सकते है कि अगर तुम पाकिस्तान मे रहने वाले हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं करोगे तो हम भारत में मुसलमानों के साथ न्याय की मांग कैसे कर सकते है ? मगर गांधी जी का नाम लेने वाले गांधी जी के कदमों पर चलने के लिए तैयार नहीं है । पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है ? क्यों नहीं डा० सुशीला नायर वहां जाती, क्यों नहीं गवर्नर पद्मजा नायडू जाती ? श्रीमती इंदिरा गांधी भी थोड़ा समय निकाल कर वहां जा सकती है ।

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): Why don't you go there?

श्री ए० बी० वाजपेयी : मैं जाने के लिये तैयार हूं, अगर कोई चलने को तैयार हो । मगर हमारे जनरल सेक्रेटरी को तो पश्चिमी बंगाल से ही निकाल दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान में कौन जाने देगा । हम गैर सरकारी आधार पर इस बात का प्रयत्न करे और इस समस्या को सुलझाने के लिये गम्भीरता से आगे बढें ।

उपसभाध्यक्ष जी, पूर्वी पाकिस्तान के दंगो को काश्मीर के साथ जोडा गया । काश्मीर की जनता के साथ नई दिल्ली न्याय नहीं कर रही है । काफी वर्षो के बाद काश्मीर से मिली जुली आवाज उठी कि केन्द्रीय सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिये । अगर हम ऐसा नहीं करते है तो हम काश्मीर की जनता के साथ बेइन्साफी करेंगे । काश्मीर की वर्तमान सरकार वहां की जनता का विश्वास खो चुकी है । अब मौका है केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का । जो सरकारी अफसर हमने भेजे थे, एक को जम्मू काश्मीर का ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बनाकर भेजना चाहते थे और एक को इन्फारमेशन डायरेक्टर, बना कर । जब वे श्रीनगर पहुंचे तो उन से कहा गया कि किसी कागज को हाथ मत लगाना और वे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस आ गये । वहां पर केवल कुछ अफसरों को भेजने का सवाल नहीं है । जम्मू काश्मीर की जनता का जो विश्वास डिग गया है उनको फिर से जमाना होगा और इसके लिए कठोर कार्यवाही होनी चाहिये । मैं श्री तारिक के सुझाव का स्वागत करता हूं कि संसद् के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू काश्मीर जाये और जम्मू काश्मीर की स्थिति का अध्ययन करे । संसद् को भी एक विशेष समिति नियुक्त करनी चाहिये और इस बात की जांच करनी चाहिये कि ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में, जम्मू काश्मीर राज्य को अब तक जो धनराशि दी गई है वह किस तरह से खर्च की गई । पी० ए० सी० और इस्टीमेट कमेटी यह काम नहीं कर सकती । इस के लिये संसद् की एक विशेष समिति नियुक्त होनी चाहिये ।

भारत की जनता को सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जिस तरह से भाषण दिया बड़ा धक्का लगा है ।

चीन के आक्रमण के समय ब्रिटेन जिस तरह से हमारी सैनिक सहायता पर आया और उससे जो सदभावना हुई थी, मित्रता के जो बधन दृढ हुये थे, उन्हे वर्तमान रवैये से गहरा धक्का लगा है । पाकिस्तान और भारत दोनो राष्ट्रमडल के सदस्य है और ब्रिटेन राष्ट्रमडल का प्रमुख है । दो राष्ट्रमडलीय देशो के झगडे मे ब्रिटेन को तटस्थता की नीति अपनानी चाहिये । वह पाकिस्तान को आक्रमणकारी भी नही कहता । वह बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार करने से इन्कार करता है । वह पूर्वी पाकिस्तान के दगो के लिये भी पाकिस्तान को दोष देना नही चाहता । ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धो के लिये बहुत बुरा काम किया है । यदि यह रवैया जारी रहा तो भारत मे यह आवाज उठेगी कि हमे ब्रिटिश राष्ट्रमडल से अपने सम्बन्ध तोडने चाहिये । काश्मीर हमारे लिये राजनीतिक की शतरज का मोहरा नही है । यह हमारे लिये शीत युद्ध का एक अग भी नही है । ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार फूट डालो और राज्य करो की साम्राज्यवादी नीति से अभी तक अपने को पूरी तरह अलग नही कर सकी है । भारत की जनता, अमेरिका के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् में क्या कहते हैं, इस बात की प्रतीक्षा कर रही है ।

हम चाहते है कि पाकिस्तान से झगडा न बढे । देश में कोई ऐसी पार्टी नही है जो पाकिस्तान से लडाई चाहती है । श्री देवकीनन्दन नारायण यहा नही है । कल उन्होने श्री गोलवलकर का नाम लिया और कहने लगे कि वे अखड भारत की बात करते हैं । अखड भारत की बात तो मैं भी करता हू । अखंड भारत की बात करना कोई जुर्म नहीं है । मैं सपना देखता हूं कि भारत और पाकिस्तान कभी एक होंगे । अगर जर्मनी के एक होने का सपना देखा जा सकता है, अगर कोरिया और वियतनाम के एक होने का सपना देखा जा सकता है, तो भारत के एक होने का सपना क्यो नही देखा जा सकता । मगर यह सपना जोर और जबरदस्ती से पूरा नही होगा । इस सपने को पूरा करने के लिये फौज काम में नही लाई जायेगी । यह लडाई के जरिये प्राप्त नही किया जायेगा । यह हृदय परिवर्तन से प्राप्त होगा । पाकिस्तान की जनता जब चाहेगी तभी यह सपना पूरा होगा । उन्हे किसी के भाषण को संदर्भ से तोड कर, मरोड कर, सदन में पेश नही करना चाहिये । मैं वह समय देखता हू जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ढीला महासघ और रक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से और विदेश सम्बन्धों की दृष्टि से हम निकट आ जाये । आज तो यह सपना ही है मगर यथार्थ कितना भी कटु हो हम सपना देखना तो नही छोड सकते । जो "जय जगत" का नारा लगाते हैं वही अखड भारत के सपने पर आपत्ति करते हैं, यह मेरी समझ में नही आ सकता । लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है, हमें पाकिस्तान के प्रति दृढ नीति अपनानी होगी । कमजोर नीति को उदारता नही समझा जाता । उस के ग़लत अर्थ लगाये जाते हैं । जब हम चीन से सघर्ष में फसे है, हम पाकिस्तान से झगडा बढाना नही चाहते । मगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो तीन महीने में पाकिस्तान से सम्बन्ध और भी बिगडेगे और उस समय हमें सतर्क रहना होगा, देश के भीतर काम करने वाले पाकिस्तानी तत्वो पर नजर रखनी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी के उस हिस्से पर भी नजर रखनी होगी जो चीनपरस्त है और चीनपरस्त होने के कारण आज पाकिस्तानपरस्त हो रहा है ।

मुझे खेद है कि कलकत्ता के दंगों के संबंध में जो बातें कही गई हैं वह एकतरफा है और एकतरफा बाते यह बताती है कि हम ऐसा प्रचार करना चाहते है जो प्रचार

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

न तो सत्य पर आधारित है और न राष्ट्र के हितों के लिये काम में आ सकता है। ऐसे प्रचार से हमको सावधान रहना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कह कर खत्म कर दूगा। अभी गृह मत्री जी ने घोषणा की है, आज प्रश्नोत्तर काल में भी उसकी चर्चा हुई थी कि दो साल के भीतर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जायेगा। मैं नही जानता कि किन ज्योतिषियों से विचार विमर्श कर के, किस पचाग को देख कर के उन्होने दो साल का समय निर्धारित किया है। यह समय डेढ साल क्यों नही हो सकता ? यह समय तीन साल क्यों नही हो सकता ? भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है, लेकिन इस समय जो नाटकीय कदम उठाये जा रहे है, वे भ्रष्टाचार नही मिटा सकते। दिल्ली में हमने एक नाटक देखा। कसमें खिलाई गई। रामलीला मैदान में हरिजन बन्धुओं को इकट्ठा किया गया, झाड़ लगाने वालों को, और प्रधान मत्री जी को वहा ले जाया गया, और उन हरिजन बधुओं को कसम खिलाई गई कि वे रिश्वत नही लेगे। हरिजन बन्धु कितनी रिश्वत लेते है? और क्या रिश्वत इसलिये ली जाती है कि लेने वालों ने कसम नही खाई है? क्या कसम खाने के बाद वे रिश्वत नही खाएगे ? अभी दिल्ली मे एक घटना हुई है। एक ठेकेदार थे। वे कही अपना गलत काम करने के लिये रिश्वत देने लगे। जिन अफसर को रिश्वत लेनी थी उन्होने कहा कि मैं तो रिश्वत नही ले सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है। फिर थोडी देर में वे बोले कि मेरी पत्नी ने कसम नहीं खाई है। तो क्या पतियो के साथ पत्नियों को भी कसमें खिलाई जायेंगी ? क्या गाठ बाध कर वेदी पर बैठ कर शपथ ली जायगी ? और अगर पत्नियों को कसमें खिला दी गई तो बच्चे तो बच ही जायेगे और फिर उन के नाम पर रिश्वतें ली जायगी। मुझे एक और आशका है कि जब तक लोगों ने कसमें नही खाई थी तब तक दो चार रुपये में काम हो जाता था। अब कोई दो चार रुपये में काम करने वाला नही है क्योंकि दो चार रुपये अगर कोई देगा तो वे कहेंगे कि हमने कसम खाई है। भला दो चार रुपये के लिये कसम क्यो तोडें ? अगर सौ पचास रुपये दे तो कसम तोड भी सकते है। इस तरह रिश्वत के साथ कसम की कीमत भी मिल जायेगी और देने वाले को यह बडा महगा पडेगा। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को मिटाने का यह तरीका नही है। भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो ऊचे क्षेत्रों मे शुद्धाचरण आदर्श रखा जाना चाहिये। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे बड लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसा ही अनुकरण करते है। कोई यह नही कह सकता है कि मत्री स्तर पर भ्रष्टाचार नही है। उसकी जाच कैसे होगी ? आध्र के मुख्य मत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, मगर पजाब के मुख्य मत्री चिपके हुये हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान आध्र में ही होना चाहिये, पजाब मे नही होना चाहिये ? पजाब के मुख्य मत्री ने इस्तीफा क्यों नही दिया ?

पजाब के गृह मत्री ने विरोधी दल पर आरोप लगाया कि वे विरोधी शक्तियों के साथ साजिश कर रहे है। जब मैंने सदन मे कहा कि अगर यह आरोप साबित नही किया गया तो मैं भूख हडताल करूगा तो वे पलट गये और कहने लगे कि मैंने ऐसा नही कहा अगर उन्होंने ऐसा नही कहा था तो दूसरे दिन उसका खडन कर सकते थे। यदि विदेशी शक्तियों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया जाता है तो फिर उसे साबित किया जाये और अगर साबित न किया जाये तो कम से कम उसका खडन करके उसको खत्म किया जाये। मगर पजाब के गृह मत्री यह भी नही कर सकते।

दास कमिशन के सामने—मैं उस की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जांच हो रही है—जो तथ्य आ रहे हैं वे बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को अगर आश्रय देगी, तो विजिलेंस कमिशन की घोषणाऐं भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकती। आवश्यकता इस बात की है कि जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच की जाय, खुली जांच की जाय और जांच के दौरान में वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर जांच में वे निर्दोष साबित हो जांय तो अपने पद पर सम्मान वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के निराकरण का मतलब यह है कि छोटी-छोटी मछलियों को फांसा जाय और बड़े-बड़े मगरमच्छ जाल में से निकल जांय तो जनता में विश्वास पैदा नहीं हो सकता।

दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि दिल्ली में जो एक कोआपरेटिव स्टोर चलता है, जिस ने गुड़ में मुनाफाखोरी की थी और जिस कोआपरेटिव स्टोर के संचालक एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं, जिनके विरुद्ध जांच हो रही है। उस जांच का परिणाम क्या होगा? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने वाली है? यह एक मामला है जो सब के सामने है। यह कसौटी है कि उस पर गृह-मंत्रालय क्या करता है। गृह मंत्रालय कठोर कार्यवाही कर सकता है। भ्रष्टाचार के निराकरण का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, सब के सहयोग से देश में ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन और हमारा शासन शुद्ध हो, भ्रष्टाचार से रहित हो। मगर इसका प्रारम्भ केन्द्र से होना चाहिये, नई दिल्ली से होना चाहिये। लेकिन नई दिल्ली में आज नया कदम उठाने की, दृढ़तापूर्ण कदम उठाने की स्थिति नहीं दिखाई देती —यह स्थिति बदली जानी चाहिये, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

شری پیر محمد خان (جموں اینڈ کشمیر): وائس چیرمین صاحب میں پریذیڈنٹ صاحب کے ایڈریس پر جو ووٹ آف تھینکس کا موشن آیا ہے اس کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں - میں زیادہ تر کشمیر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرونگا لیکن پہلے چائنا کے متعلق بھی تھوڑا کہنا چاہتا ہوں - چائنا کے متعلق ایک پالیسی ہی کام آئے گی کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنا علاقہ واپس لیں - پاکستان کے متعلق جو کچھ سیکورٹی کونسل میں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اور سیکورٹی کونسل میں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کو دھیان میں رکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں آئندہ یہ کرنا چاہئے کہ اگر پاکستان پھر سیکورٹی کونسل میں جائے تو ہم اس شرط پر ہی وہاں جائیں کہ وہ ایگریشن ویکھت کر دے اور جب تک وہ ایگریشن ویکھت نہ کرے تب تک ہمیں ایسی میٹنگوں میں شامل نہیں ہونا چاہئے -

اب میں کشمیر کے متعلق کہنا چاہتا ہوں - کشمیر میں تازہ واقعہ موئے مقدس کی چوری کا جو ہوا وہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس سے دو دن پہلے غالباً ۲۴ دسمبر کو کشتواڑ میں

شری پیر محمد خان : اس کے بعد وہاں تحقیقات وغیرہ شروع ہوئی۔ اب تک وہاں وہ الیمنٹ جو پرو پاکستانی تھا اور کچھ قسکریلنڈ الیمنٹ تھا انہوں نے مل کر ایک ایکشن کمیٹی جہت پت بنالی۔ ان کو ایک موقعہ ملا اور اس موقعہ سے انہوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ کس کے خلاف۔ انڈیا کے خلاف۔ کشمیر کے خلاف تو کیا ہونا تھا۔ انڈیا کے خلاف فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس ایکشن کمیٹی کے ۱۲ یا ۱۳ ممبر ہیں اور اس میں مجارٹی ان ممبرس کی ہے جو کہ میر واعظ فیملی کے ہیں۔ میر واعظ وہ شخص ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں۔ مسلم کانفرنس کے ۱۹۴۷ع سے پہلے پریذیڈنٹ تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ ریاست کا الحاق چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ مولوی مسعودی صاحب اس کے جنرل سیکریٹری اور کرتا دھرتا ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پلیبیسائٹ فرنٹ اور پولیٹیکل کانفرنس کے آدمی ہیں جو کہ سب پرو پاکستانی ہیں۔ مولوی مسعودی صاحب وہ ہیں جو کہ شیخ عبداللہ صاحب کے ہم خیال ہیں اور ۱۱ تاریخ کی سیکوریٹی کونسل کی ڈیبیٹ میں چاگلہ صاحب نے بالکل صاف شبد میں کہا ہے کہ مسعودی ایونیشن گروپ کا آدمی ہے تو یہ ایک ایکشن کمیٹی بنی اور

[شری پیر محمد خان]

جو کہ جموں سے ۱۲۰ میل نارتھ ویسٹ کی طرف ایک جگہ ہے وہاں ایک زیارت کو آگ لگائی گئی اس کے تھیک دو دن کے بعد یہ موئے مقدس کی چوری سری نگر حضرت بل میں ہوئی اور پھر اس کے تین دو دن کے بعد جموں میں ایک مندر سے دو مورتیاں نکالی گئیں۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : وائس چیرمین صاحب۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔

شری پیر محمد خان : آپ میرا وقت ضائع نہ کیجئے۔ مجھے کہنے دیجئے۔

SHRI A. M. TARIQ: I rise on a point of order.

کشمیر واز میں کسی زیارت میں آگ نہیں لگائی گئی۔ یہ غلط ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : तारिक साहब, आप बोल चुके हैं, उनको बोलने दीजिये ।

SHRI A. M. TARIQ: He is giving wrong information.

SHRI B. D KHOBARAGADE (Maharashtra): Congress people should not fight amongst themselves.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI (Punjab): How can he say that he is giving wrong information?

انہوں نے لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ یہ سب کچھ بخشی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کرایا ہے - بیچ بیچ میں یہ ہوا پھیلی - ایک مسلمان کے سنٹیمینٹس کو آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز کا جب نقصان ہو بڑے فلیرڈ اپ ہو جاتے ہیں - ایک تو اس وقت ان کلہور لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا اور جوش پیت ایک دھار بخشی صاحب کی طرف موڑ دی - ماس سمپتھیٹی تیار کی - لوگ اکٹھے ہوئے، جلسہ جلوس ہوا، بڑا رونا پیٹنا ہوا - اس کی گمشدگی پر - تو اس کی دھارا اس طرح پھیر دی اور اس طرح بھڑنے پر کیا ہوا - لال چوک میں --- بہت سے صاحبان نے وہ جگہ دیکھی ہوگی وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے - ان میں جب یہ بات پھیل گئی تو لال چوک کے قریب بخشی صاحب کے رشتہ داروں کی جو کچھ عمارتیں تھیں ان کو آگ لگائی گئی - ان کو چھوڑ دیجئے وہ تو ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی پھر ان کو اکسایا گیا اور انہوں نے پھر پولیس تھانہ پر حملہ کرکے اس کو جلا دیا - ہوم منسٹر صاحب نے اپنے بیان میں جو کہ کل انہوں نے دیا ہے صاف بتایا ہے کہ فائرنگ تھانہ جلانے کے بعد ہوئی اور اس وقت ہوئی جب کہ پولیس پر باہر ایسالٹ ہونا شروع ہو گیا - فائرنگ تب ہوئی - اس طرح فائرنگ نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ مجھے انصاف دو اور آگے سے اسے پکڑ کر گولی مار دی - یہ بات نہیں تھی - فائرنگ اس وقت ہوئی جب کہ ایک تو تھانہ جلا رہے تھے اور دوسرے اس وقت جس وقت کہ پولیس پر حملہ شروع ہو گیا تھا - تو سیلف ڈیفنس میں فائرنگ ہوئی -

خیر یہ چیز ہوئی - اب گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹیٹ کی ہمدردی ہونے کی وجہ سے جو کہ اس کو کرنا چاہئیے تھا کچھ یہاں سے امداد بھیجی - انٹیلیجنس برانچ کے کچھ افیسرس اور ہوم سیکریٹری وہاں گئے - تو انٹیلیجنس برانچ نے موئے مقدس کو ڈھونڈنے میں حصہ لیا اور اس کی تحقیقات میں حصہ لیا - اس تحقیقات کے متعلق ایک دو بیان ہوم سیکریٹری نے دئے تو اس کلہور گروپ نے لوگوں میں کہنا پھیلا دیا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ معطل ہو گئی ہے اور اب انڈیا گورنمنٹ نے سارا کچھ انتظام ہاتھ میں لے لیا ہے، اس طرح کچھ اور فضا خراب ہوئی - خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیز گم ہوئی ہے اور پاکستان ریڈیو میں اور وہاں کے لیڈروں کے بیان میں یہ بات

جانتا ہوں - جو اس کا اسٹینڈ، جو اس کا دلی لگاؤ انڈیا کے ساتھ اس وقت تھا وہی لگاتار اس وقت تک ہے اور اس سے بڑے لوگوں میں وہ بات نہیں رہی - اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کشمیر اسمبلی سے ایکسیشن پر مہر لگوائی - آپ میں سے بہت حضرات نے جموں اور کشمیر دیکھا ہوگا آپ دیکھئے وہاں کیا پروگریس ہوئی ہے اور جو پروگریس ہوئی ہے وہ بخشی ہی کے ریجیم میں ہوئی ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کی طبیعت ایک آدمی کو نہیں چاہتی تو اس کی اچھی باتیں کوئی نہیں دیکھتا البتہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو خراب ظاہر کیا جائے -

پھر ایک بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ اب اس حکومت کو نہیں چاہتے کوئی وقتی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس سے کچھ شیک اپ ہوتا ہے - جیسا کہ اس معاملہ میں ہوا - لوگوں کے کان بھر دئیے گئے کہ یہ سب کچھ بخشی نے کرایا - اور بخشی نے اور حکومت نے دونوں نے کرایا ہے کیوں کہ دونوں کو اپنی تباہی کرنی ہے - اس واسطے ان کی تھوڑی مخالفت بھی ہوئی - مگر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں - جو اس کا اسٹینڈ، جو اس کا دلی لگاؤ انڈیا کے ساتھ اس وقت تھا وہی لگاتار اس وقت تک ہے اور اس سے بڑے لوگوں میں وہ بات نہیں رہی - اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کشمیر اسمبلی سے ایکسیشن پر مہر لگوائی - آپ میں سے بہت حضرات نے جموں اور کشمیر دیکھا ہوگا آپ دیکھئے وہاں کیا پروگریس ہوئی ہے اور جو پروگریس ہوئی ہے وہ بخشی ہی کے ریجیم میں ہوئی ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کی طبیعت ایک آدمی کو نہیں چاہتی تو اس کی اچھی باتیں کوئی نہیں دیکھتا البتہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو خراب ظاہر کیا جائے -

(شری پیر محمد خان)

آئی ہے کہ ایک ہندو نے چرایا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کرایا ہے اور اس واسطے کرایا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نیست و نابود کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ - وہ جماعت جو اس وقت وہاں ریاست میں مجارٹی میں ہے اس : یہ ٹریڈیشن تھا نیشنل کانفرنس کا یہ ٹریڈیشن تھا کہ کمیونل ہارمنی ہو اور سب کو اپنا بھائی سمجھیں اور یہی ٹریڈیشن نیشنل کانفرنس کا رہا ہے جس کی وجہ سے ۱۹۴۷ء میں کشمیر ویلی میں کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہونے دیا گیا-یہ اسی جماعت کی ٹھچلک تھی اور وہی چیز اور وہی ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے - پاکستان ریڈیو کے اتنا اکسانے کے باوجود اور سب کچھ کرنے کے بعد وہاں کوئی کمیونل ٹینشن نہیں ہوا اور موئے مبارک کے گم ہونے کا رنج، اس کا افسوس، اگر ایک طرف مسلمان نے کیا تو دوسری طرف ہندو نے بھی کیا، سکھ نے بھی کیا اور جو کوئی بھی وہاں تھا سب نے کیا -

اب بخشی صاحب کے خلاف بہت سی باتیں کہی گئی ہیں - میں یہ نہیں کہتا کہ بخشی فرشتہ ہے، وہ بھی ایک انسان ہے - مگر یہ بخشی وہی ہے جس کو ۱۹۴۷ء سے میں ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں اور

کرنا چاہتا ہے - اس کے واسطے راستے کھلے ہوئے ہیں - وہ ہر برے یا اچھے راستے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے - مثلاً ابھی اتنی چیزیں بتائی گئیں کہ جیسے کشمیر سے ہندوستان نے انصاف نہیں کیا - کیوں انصاف نہیں کیا؟ کیا کشمیری بھوکے مر رہے ہیں؟ ہندوستان مدد نہیں دیتا، کسی طرح کی سہولت نہیں دیتا، کسی بھی بات میں کوئی مدد نہیں کرتا، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں - بخشی صاحب کے متعلق ایک لطیفہ ہے --- یہاں تو ہوا ہی سیکرٹری کونسل میں بھی پاکستان کے ڈیلیگیٹ نے کہا--- بخشی صاحب کا کوئی بیان ریفر کر کے کہا - کہ بخشی صاحب بھی پلیبسائٹ چاہتے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اور وہ بیان جعلی طور پر، جعلی دستخطوں سے جاری کیا گیا اور اس کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ہوم منسٹری کو اچھی طرح سے پتہ تھا - اور اس جعلی بیان کی بنیاد پر کچھ دوستوں نے یہاں پر باتیں کہی ہیں اور کچھ دوستوں نے جموں سے بیان بھیجا - اس جعلی بیان کی بنیاد پر جس کے بارے میں ۱۱ تاریخ کی سیکرٹری کونسل کی میٹنگ میں مسٹر چھاگلا نے جعلی کہا - تو اس طرح کی چیزیں ہیں - بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان کا جواب دینا بھی اخلاق کے خلاف سمجھتا ہوں- بخشی صاحب اور ان کی فیملی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جائیداد اور پیسہ ہے - یہ بڑا الزام دو مورتیوں کی چوری ہوئی وہاں ان کی تحقیقات ہو رہی ہے - بد قسمتی سے وہ ابھی تک نہیں ملیں- وہاں کہا ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں اس حکومت کو بدل دو - ہماری پرجا پریشد جو جن سنگھ کی ایک شاخ ہے کہتی حکومت کو بدل دو، پریزیڈنٹ رول کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو- پرجا پریشد عبد اللہ کے وقت بھی یہی چاہتی تھی کہ پریزیڈنٹ رول ہو اور حکومت ختم ہو - پرجا پریشد بخشی صاحب کے وقت بھی یہی چاہتی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا - تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر کئی افیسر یہاں سے گئے تو ادھر ادھر پبلک کو بتایا گیا کہ یہ تو سینٹرل گورنمنٹ رفتہ رفتہ اس گورنمنٹ کو معطل کر رہی ہے اور اب اس سے چارج لے لیگی - آج اور کل کے نیوز کو دیکھیں - ذمہ دار سرکاری آدمیوں کے بیان بیانات اخبار میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس گورنمنٹ نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کو ایڈمنسٹریشن کو ذرا اور اچھا کرنے کے لئے قابل آدمیوں کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس بات کو ویلکم کیا اور کچھ آفیسرس کشمیر بھیجے اور شاید کچھ اور اسپیئر کریں گی تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے- چیز یہ ہے - ٹھیک ہے کوئی شخص طبعی طور پر ایک چیز کی مخالفت

[شری پیر محمد خان]

لگایا جاتا ہے - دیکھئے - بخشی صاحب کی جو ذاتی جائیداد ہے اس کا حساب آپ دیکھ لیں - اس کو پوچھ لیں - باقی رہی ان کی فیملی، وہ اگر بزنس کرکے چار پیسے کما رہی ہے تو میں اور آپ کو کیا غرض - وہ ڈاکہ مار کر نہیں لائے - کسی کا گھر لوٹ کر نہیں لائے -

شری اے - ایم - طارق : تو کہاں سے لائے ؟

شری پیر محمد خان : اور پھر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ بخشی نے پاکستانیوں کو رکھا اور چند ایک افسروں کے نام گئے - آپ انڈیا میں دیکھیں - بہت سے آدمی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جو یہاں ملازمت میں ہیں اور ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں - تو میر واعظ کے باپ کے مرنے پر بخشی نے چھٹی کر دی اور میر واعظ کے باپ ایک مانے ہوئے بھلے اور ایماندار آدمی تھے - دیکھئے - میر واعظ کے باپ بالکل پاکستانی نہیں تھے، بالکل سیدھے سادھے آدمی تھے - اور اگر ان کے مرنے کے بعد چھٹی بھی کر دی تو وہ ٹیزرو کرتے تھے یہ چیز - حالانکہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ چھٹی کر دی تو یہ بھی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے - یہ حکومت کی نگاہ میں ہے - مگر وہ چھٹی کی بھی گئی تو ٹھیک ہے - یہ بھی کہا گیا کہ دو تین سو آگ کی بھری ہوئی کانگڑیاں بخشی عبدالرشید کے سر پر ماری گئیں - ذرا اندازہ کیجئے، آگ کی بھری ہوئی کانگڑی ابھی ایک آدمی کو دو بھی مار کر دیکھ لیجئے، ایک کے بعد ہی کیا حال ہوگا اس کو دیکھ لیجئے اندازے کے طور پر - یہ تو مبالغہ کی انتہا ہے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے - اس کے علاوہ ایک کہانی گھڑی گئی کہ ایک ایس - پی - نے، سرکاری ملازم نے ایک ہندو کو پستول سے مار دیا تاکہ ہندو مسلمان میں فسادات پیدا ہوں - تو آپ ان دونوں میں فرق دیکھئے کہ ایک جگہ تو کہا جائے کہ ایک ہندو نے موئے مبارک چرایا ہے اور دوسری جگہ یہ کہا جائے کہ ایک مسلمان ملازم نے ہندو کو مار ڈالا - زمین آسمان کا فرق ہے -

تو چیز یہ ہے کہ ایسی چیز کہدینے سے کیا فائدہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ۳۰۰ آگ سے بھری کانگڑیوں کی یورش کسی آدمی پر چلیگی - جب یہ کسی آدمی کے سر پر لگتی ہیں تو وہ بچ نہیں سکتا - ابھی ہمارے خلاف دو سائڈ ہیں - ایک تو ڈسگرنٹلڈ گروپ کے پانچ چھ آدمی ہیں جن کو کامیابی نہیں ہوئی - پیچھے ابھی جو الیکشن ہوا، ان لیڈر آف دی ہاوس کے، اس میں ۱۰۰ کے مقابلہ میں انہیں چھ ووٹ ملے -

(THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

ہم نے کشمیر میں سوائے سترہ برسوں میں بہت کام کیا اور اس کو آگے بڑھایا - لیکن مہر واعظ یوسف صاحب اور چودھری غلام عباس کو پاکستان سے واپس لایا جائے یہ مانگ ہمارے مولانا مسعودی صاحب کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بیٹھکر کشمیر کے معاملہ کا فیصلہ کریں - کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا - مولانا مسعودی صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷ میں اور ۱۹۴۸ء کے شروع میں چودھری عباس کو جو جموں کی جیل میں قید تھے وہاں سے چھڑوا کر پاکستان بھجوایا تھا - اب وہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان سے واپس لایا جائے - مہرواعظ محمد یوسف اور غلام عباس یہ دونوں ریاست کی پاکستان میں شمولیت کے حق میں تھے - اس وقت غلام عباس فوجی تیاری کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں تاکہ وہ کشمیر کے اس حصہ پر جو کہ ہمارے قبضہ میں ہے اس پر حملہ کر سکیں - مولوی مسعودی صاحب - مہر واعظ صاحب ، غلام عباس صاحب اور شیخ عبداللہ صاحب بھی کیا کشمیر کے معاملہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں ؟ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے - گر

شری اے - ایم - طارق : آپ بھی مبالغہ سے کام لے رہے ہیں -:۷ ہیں؟ ۱۰۰ نہیں ہیں -

شری پیر محمد خان : کسی وجہ سے جو ووٹ پانے والوں کو لیڈر آف دی ہاوس تسلیم کیا جا سکتا ہے - میں اس میں کونسل کے ممبروں کو بھی شامل کرتا ہوں - میں کہتا ہوں کہ اس گروپ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے کافی اسٹریلنگتھ بنالی ہے کشمیر گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائے گا - تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ ایک کلسٹی ٹیوشنل وے ہے - آپ تو کانفیڈنس موشن لائیے اور ساری بات ٹھیک ہو جائے گی - اگر وہ پاس ہو جائے گا تو آپ کی اسٹریلنگتھ معلوم ہو جائے گی - لیکن آپ قیامت تک اس کو نہیں لا سکتے ہیں - جو کچھ مرضی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے - میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک زندہ شخص ۲۰۰ کانگڑیوں کی آگ کی یورش کے نیچے آئے گا تو زندہ نہیں رہ سکتا - آپ لوگ اور مولوی مسعودی صاحب جو اس ایکشن کے روح رواں ہیں اور نئی ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں؟ جن کی بڑی تعریف ڈسگرنٹلڈ گروپ میں کی جاتی ہے؟ وہ نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں -

[شری پیر محمد خان]

آپ ایکشن کمیٹی کے ممبران کو دیکھینگے تو اس میں ۱۲ یا تھوڑے آدمی ہیں اور جس میں اکثریت میر واعظ محمد یوسف کے رشتہ داروں کی ہے اور باقی آدمی پرو پاکستانی پارٹیز کے ہیں جو مسلم پولیٹیکل کانفرنس اور پلیبیسائٹ فرنٹ کے ممبر ہیں - اس ایکشن کمیٹی میں ایک آدمی بھی نیشنل کانفرنس کا نہیں ہے - بخشی صاحب نے اس ایکشن کمیٹی کے کاموں کو چلنے نہیں دیا اور حکومت میں ۱۹۴۷ع سے لے کر آج تک اس قسم کے ایلیمنٹس کو ابھرنے نہیں دیا - یہی ان کا قصور ہے جس کی وجہ سے انہیں بدنام کیا جا رہا ہے - آج ان کو مذاقاً آہنی آدمی کہہ رہے ہیں - یہی تھوڑے عرصہ پہلے صحیح طور پر آہنی آدمی تھے اور ان کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے - خوش قسمتی سے ہوم منسٹر صاحب نے ۱۲ تاریخ کو راجیہ سبھا میں یہ بتایا کہ اس موئے مبارک کی چوری میں نیشنل کانفرنس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ۔ اس میں ایک سے زیادہ آدمی ہیں اور ابھی ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں کچھ گرفتاری اور کرنی پڑے - نندا صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ دو تین دن میں اصلی کلپرٹس کے نام بتادونگا اور اعتراض کنندگان کے متعلق معاملہ روشن ہو جائے گا کہ ان پروپیگنڈا کہاں تک صحیح ہے اور پھر بھی آہنی آدمی فولادی آدمی بن جائیں گے -

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have taken enough time. Please wind up.

شری پیر محمد خان: پہلے اسپیکر کو کافی ٹائم دیا گیا - اس لئے مجھے تھوڑا وقت اور ملنا چاہئے - تو میں کہہ رہا تھا -

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nearly half an hour.

شری پیر محمد خان: تو میں کہہ رہا تھا کہ اعتراض کرنے والے نہ گھبرائیں دو تین دن میں دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا - اور مرد آہنی کی پوزیشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی - پارلیمنٹ میں اس طرح سے توہین آمیز باتیں کرنا پارلیمنٹ کے رولس کے خلاف ہے - اس طرح کی باتیں کرنا بے جا ہے بجا نہیں - اس کے بعد میں موشن آف تھینکس کی تائید کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقعہ عنایت کیا -

شری ایم - این - انور (مدراس): میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اس نازک دور میں بخشی غلام محمد اور عبدالرشید وہ کہاں تھے - اور وہ میدان چھوڑ کر کدھر چلے گئے -

تو کیا مولانا مسعودی صاحب نے ہی اس نازک سچویشن کو سنبھالا تھا ؟

شری پیر محمد خاں : مجھے اجازت ہو تو میں ان کا جواب دے دوں - میں نے جس وقت جواب دیا تھا اس بات کا اس وقت انہوں نے فالو نہیں کیا - میں نے کہا تھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی اس ایکشن کمیٹی کی جس میں تقریباً سینٹ پرسینٹ پرو پاکستانی ایلیمنٹ شامل ہیں اور انہوں نے موقعہ کا فائدہ اٹھایا ہے - انہوں نے لوگوں کے کان پھونکا کہ یہ سب کچھ بخشی نے اور نیشنل کانفرنس نے کرایا ہے -

†[**श्री पीर मुहम्मद खान** (जम्मू और काश्मीर): वाइस चैयरमैन साहब मैं प्रेजिडेंट साहब के एडरेस पर जो वोट आफ थेंक्स का मोशन आया है इसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। मैं ज्यादातर काश्मीर के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करूंगा लेकिन पहले चाइना के मुतल्लिक भी थोड़ा कहना चाहता हूं। चाइना के मुतल्लिक एक पालिसी ही काम आयेगी कि हम अपने आपको मजबूत करें और अपना इलाका वापस लें। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो कुछ सिक्यूरिटी कौंसिल में हो रहा है उसको देखने के बाद और सिक्यूरिटी कौंसिल में जो कुछ पहले हो चुका है उसको ध्यान में रखने के बाद मेरा ख्याल है कि हमें आइन्दा यह करना चाहिये कि अगर पाकिस्तान फिर सिक्यूरिटी कौंसिल में जाये तो हम इस शर्त पर ही वहां जायें कि वह एग्रेशन वेकेट कर दे और जब तक वह एग्रेशन वेकेट न करे तब तक हमें ऐसी मीटिंगों में शामिल नहीं होना चाहिये।

अब मैं काश्मीर के मुतल्लिक कहना चाहता हूं। काश्मीर में ताजा वाकया मुए-मुकद्दस की चोरी का जो हुआ वह कुछ इस तरह हुआ कि इससे दो दिन पहले, गालिबन २४ दिसम्बर, को, किश्तवाड़ में जो कि जम्मू से १५० मील नार्थ वैस्ट की तरफ एक जगह है वहां एक जयारत को आग लगाई गई, उसके ठीक दो दिन के बाद यह मुए-मुकद्दस की चोरी श्रीनगर हजरतबल में हुई और फिर उसके एक दो दिन के बाद जम्मू में एक मन्दिर से दो मूर्त्तियां निकाली गई।

श्री ए० एम० तारिक़ : वाइस चैयरमैन साहब। मै आपकी तव्वजो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह वाकया नही है, यह गलत है।

श्री पीर मुहम्मद खान : आप मेरा वक्त जाया न कीजिये। मुझे कहने दीजिये।

श्री ए० एम० तारिक़ : I rise on a point of order. किश्तवाड़ में किसी जयारत में आग नही लगाई गई यह गलत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : तारिक साहब, आप बोल चुके हैं, उनको बोलने दीजिये।

SHRI A. M. TARIQ: He is giving wrong information.

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Maharashtra): Congress people should not fight amongst themselves.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI (Punjab): How can he say that he is giving wrong information?

श्री पीर मुहम्मद खान : इसके बाद वहां तहकीकात वगैरा शुरू हुई। अब तक वहां वह एलीमेंट जो प्रो-पाकिस्तानी

†[ ] English translation.

[श्री पीर मुहम्मद खान]

था और कुछ डिसग्रेन्टल्ड एलीमेन्ट था उन्होंने मिल कर एक एक्शन कमेटी झटपट बना ली। उनको एक मौका मिला और उस मौके से उन्होंने फायदा उठाना चाहा। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, काश्मीर के खिलाफ तो क्या होना था, इंडिया के खिलाफ फायदा उठाना चाहा। इस एक्शन कमेटी के १२- या १३ मेम्बर हैं और उसमें मेजोरिटी उन मेम्बरस की है जो कि मीर वाज फैमिली के हैं। मीर वाज वह शख्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। मुस्लिम कांफ्रेंस के १९४७ ई० से पहले प्रेजिडेंट थे और वह पाकिस्तान के साथ रियासत का इलहाक चाहते थे। इसके अलावा मौलवी मसऊदी साहब इसके जनरल सेक्रेटरी और कर्त्ता धर्त्ता हैं। इसके अलावा कुछ प्लेबीसाइट फ्रन्ट और पोलिटिक्ल कांफ्रेंस के आदमी हैं जो कि सब प्रो-पाकिस्तानी हैं। मौलवी मसऊदी साहब वह हैं जो कि शेख अब्दुल्ला साहब के हम-ख्याल हैं और ११ तारीख की सिक्यूरिटी कौंसिल की डिबेट में छागला साहब ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा है कि मसऊदी अपोजिशन ग्रुप का आदमी हैं। तो यह एक एक्शन कमेटी बनी और उन्होंने लोगों में यह बात फैलाई कि यह सब कुछ बख्शी साहब ने और उनके साथियों ने कराया है। बीच बीच में यह हवा फैली। एक मुसलमान के सेन्टीमेन्टस को आप जानते हैं कि ऐसी चीज का जब नुकसान हो बड़े फ्लेयर्ड-अप हो जाते हैं। एक तो उस वक्त उन क्लेवर लोगों ने यह फायदा उठाया और झटपट एक धार बख्शी साहब की तरफ मोड़ दी। मास मेन्टैलिटी तैयार की। लोग इकट्ठे हुये, जलसा जलूस हुआ, बड़ा रोना पीटना हुआ, इसकी गुमशुदगी पर। तो इसकी धारा इस तरह फेरदी और इस तरह फेरने पर क्या हुआ? लाल चौक में—बहुत से साहबान ने वह जगह देखी होगी वहां एक जलसा होता है। उनमें जब यह बात फैल गई तो लाल चौक के करीब बख्शी साहब के रिश्तेदारों की जो कुछ इमारतें थी उनको आग लगाई गई। उनको छोड़ दीजिये, वह तो एक प्राइवेट प्रापर्टी थी। फिर उनको उकसाया गया और उन्होंने फिर पुलिस थाना पर हमला करके उसको जला दिया। होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में जो कि कल उन्होंने दिया साफ बताया है कि फ़ाइरिंग थाना जलाते वक्त हुई और उस वक्त हुई जब कि पुलिस पर बाहर एसाल्ट होना शुरू होगया, फाइरिंग तब हुई, इस तरह फाइरिंग नहीं हुई कि एक आदमी कहता था कि मुझे इन्साफ दो और आगे से उसे पकड कर गोली मार दी, यह बात नही थी। फाइरिंग उस वक्त हुई जब कि एक तो थाना जला रहे थे और दूसरे उस वक्त जिस वक्त की पुलिस पर हमला शुरू हो गया था, तो सेल्फ डिफेंस में फारिग हुई।

खैर यह चीज हुई। अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट की हमदर्दी होने की वजह जो कि उसको करना चाहिये था कुछ यहां से इमदाद भेजी। इन्टेलीजन्स ब्रांच के कुछ आफीसर्स और होम सेक्रेटरी वहां गये। तो इन्टेलीजेन्स ब्रांच ने मूए-मुकद्दस को ढूढने में हिस्सा लिया और उसकी तहकीकात में हिस्सा लिया। इस तहकीकात के मुतल्लिक एक दो बयान होम सेक्रेटरी ने दिया तो इस क्लेवर ग्रुप ने लोगों में क्या फैला दिया कि स्टेट गवर्नमेंट मौअतल हो गई है और अब इंडिया गवर्नमेंट ने सारा इतजाम हाथ में ले लिया है। इस तरह से कुछ और फिजा खराब हुई। खैर अब देखना यह है कि एक चीज़ गुम हुई है और पाकिस्तान रेडियो में और वहां के लीडरों के बयान में यह बात आती है कि एक हिन्दू ने चुराया है, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कराया है और इस वास्ते कराया है कि मुसलमानों को वहां से नेस्तोनाबुद कर दिया जाये

वगैरा, वगैरा। वह जमायत जो इस वक्त वहां रियासत मे मेजोरटी मे है उसका यह टरेडीशन था, नेशनल कांग्रेस का यह टरेडीशन था कि कम्यूनल हार्मनी हो और सब को अपना भाई समझे और यही टरेडीशन नेशनल कांग्रेस का रहा है जिसकी वजह से १९४७ ई० मे काश्मीर वादी मे कोई कम्यूनल रायट नही होने दिया गया। यह उसी जमायत की टीचिंग थी और वही चीज और वही टरेडीशन चला आ रहा है। पाकिस्तान रेडियो के इतना उकसाने के बावजूद और सब कुछ करने के बाद वहा कोई कम्यूनल टेनशन नहीं हुआ। और मूए-मुबारक के गुम होने का रंज, इसका अफसोस, अगर एक तरफ मुसलमान ने किया तो दूसरी तरफ हिन्दू ने भी किया, सिक्ख ने भी किया और जो कोई भी वहां है सब ने किया।

अब बख्शी साहब के खिलाफ बहुत सी बाते कही गई है। मै यह नही कहता कि बख्शी फरिश्ता है, वह भी एक इंसान है। मगर यह बख्शी वही है जिसको १९४७ ई० से मै जाती तौर पर देख रहा हू और जानता हू। जो उसका स्टेंड, जो उसका दिली लगाव इंडिया के साथ उस वक्त था वही लगातार इस वक्त तक है। और उससे बडे लोगो मे वह बात नही रही और मै आपको यह बात बताऊं कि यह वही शख्स है जिसने काश्मीर असेम्बली से एक्सेशन पर मोहर लगवाई। आप मे से बहुत हजरात ने जम्मू और काश्मीर देखा होगा, आप देखिये वहां क्या प्रोग्रेस हुई है और जो प्रोग्रेस हुई है वह बख्शी ही के रेजिम मे हुई है और कायदे की बात है कि अगर एक आदमी की तबीयत एक आदमी को नही चाहती तो उसकी अच्छी बाते कोई नही देखता अलबत्ता यह कोशिश की जाती है कि उसको खराब जाहिर किया जाये।

फिर एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कहा जाता है कि काश्मीर के लोग अब इस हुकूमत को नही चाहते। कोई वक्त चीजे ऐसी भी होती है कि जिससे कुछ शेकअप होता है। जैसा कि इस मामले में हुआ, लोगों के कान भर दिये गये कि यह सब कुछ बख्शी ने कराया और बख्शी ने और हुकूमत ने, दोनों ने कराया है। क्योंकि दोनों को अपनी तबाही करनी है। इस वास्ते उनकी थोड़ी मुखालफत भी हुई। मगर मै एक चीज अर्ज करना चाहता हू कि अभी जम्मू में जहा कि दो मूर्तियों की चोरी हुई वहा इनकी तहकीकात हो रही है, बदकिस्मती से वह अभी तक नही मिली, वहा क्या हो रहा है कि कहते है इस हुकूमत को बदल दो, हमारा प्रजा परिषद् जो जनसंघ की एक शाख है कहती है हुकूमत को बदल दो, प्रेजीडेंट रूल कर दो, यह कर दो, वह कर दो। प्रजापरिषद अब्दुल्ला के वक्त भी यही चाहती थी कि प्रेजीडेंट रूल हो और हुकूमत खत्म हो। प्रजा परिषद बख्शी साहब के वक्त भी यही चाहती थी और इसका यही नारा था। तो यह कोई नई चीज नही है। और फिर कई आफिसर्स यहा से गये तो इधर उधर पब्लिक को बताया गया कि यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट रफता रफता इस गवर्नमेंट को मुअत्तिल कर रही है और अब इससे चार्ज ले लेगी। आज और कल के न्यूज़ को देखे। जिम्मेदार सरकारी आदमियो के यहा बयानात अखबार मे देखें, तो पता चलेगा कि इस गवर्नमेंट ने यह रिक्वेस्ट की कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन को जरा और अच्छा करने के लिये काबिल आदमियो की जरूरत है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात का वैल्कम किया और कुछ आफिसर्स काश्मीर भेजे और शायद कुछ और स्पेयर करेगी। तो यह कोई खास बात नही है। चीज यह है, ठीक है कोई शख्स तबई तौर पर एक चीज की मुखालफत करना चाहता है उसके वास्ते रास्ते खुले हुए हैं वह हर बुरे या अच्छे रास्ते से करना चाहे तो कर सकता है। मसलन अभी इतनी चीजे बताई गई जैसे काश्मीर से हिन्दुस्तान ने इंसाफ नही किया। क्या इंसाफ नहीं किया? क्या काश्मीरी भूखे मर रहे है? हिन्दुस्तान मदद नही देता? किसी तरह की सहूलियत नहीं देता? किसी भी बात मे कोई मदद नही करता, यह सब बाते कही जाती है। बख्शी

[श्री पीर मुहम्मद खान]

साहब के मुतल्लिक एक लतीफा है---यहां तो हुआ ही, सिक्यूरिटी कौसिल मे भी पाकिस्तान के डेलीगेट ने कहा---बख्शी साहब का कोई बयान रेफर कर के कहा---कि बख्शी साहब भी प्लेबीसाइट चाहते है, यह है, वह है। और वह बयान जाली तौर पर जाली दस्तखतों से जारी किया गया और उसके बारे में गवर्नमेट आफ इंडिया की होम मिनिस्टरी को अच्छी तरह से पता है और इस जाली बयान की बुनियाद पर कुछ दोस्तों ने यहां पर बातें कही है और कुछ दोस्तों ने जम्मू से बयान भेजा। इसी जाली बयान की बुनियाद पर जिसके बारे मे ११ तारीख की सिक्यूरिटी कोसिल में मिस्टर छागला ने जाली कहा। तो इस तरह की चीजे है। बहुत सी ऐसी बातें है कि उनका जवाब देना भी अखलाक के खिलाफ समझता हू। बख्शी साहब और उनकी फैमिली के मुतल्लिक कहा जाता है कि उनके पास जायदाद और पैसा है। यह बडा इल्जाम लगाया जाता है। देखिये बख्शी साहब की जो जाती जायदाद है उसका हिसाब आप देख लें, उसको पूछ ले, बाकी रही उनकी फैमिली वह अगर बिजनेस कर के चार पैसे कमा रही है तो हमें और आप को क्या गरज। वह डाका मार कर नही लाये। किसी का घर लूट कर नही लाये।

श्री ए० एम० तारिक़ : तो कैसे लाये ?

श्री पीर मुहम्मद खान : और फिर एक इल्जाम यह लगाया गया कि बख्शी ने पाकिस्तानियो को रखा और चन्द एक अफसरों के नाम गिने। आप इंडिया मे देखे बहुत से आदमी है जिन्हे मैं जानता हू जो यहा मुलाजमत में है और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है। तो मीर वाज के बाप के मरने पर बख्शी ने छुट्टी कर दी और मीर वाज के बाप एक माने हुए भले और ईमानदार आदमी थे। देखिये, मीर वाज के बाप बिल्कुल पाकिस्तानी नही थे, बिल्कुल सीधे सादे आदमी थे। और अगर उनके मरने के बाद छुट्टी भी कर दी तो वह डिजरव करते थे यह चीज। हालांकि जो मैं यह कहता हूं कि छुट्टी कर दी तो यह भी सबजेक्ट टू कन्फर्मेशन है। यह हुकूमत की निगाह में है। मगर वह छुट्टी की भी गई तो ठीक है। यह भी कहा गया कि २-३ सौ आग की भरी हुई कांगडिया बख्शी अब्दुल रशीद के सर पर मारी गई। जरा अन्दाजा कीजिये आग की भरी हुई कांगडी अभी एक आदमी को दो भी मार कर देख लीजिये, एक के बाद ही क्या हाल होगा, इसको देख लीजिये अन्दाजे के तौर पर। यह तो मुबालिगा कि इन्तहा है और लोगो के जज्बात को उभारने के लिये यह तरीका अख्तियार करना कोई अच्छी बात नही है। इसके अलावा एक कहानी घडी गई कि एक एस० पी० ने सरकारी मुलाजिम ने, एक हिन्दु को पिस्तौल से मार दिया ताकि हिन्दु मुसलमान में फसादात पैदा हो। तो आप इन दोनों मे फरक देखिये कि एक जगह तो कहा जाये कि एक हिन्दु ने मूए-मुबारक चुराया है और दूसरी जगह यह कहा जाये कि एक मुसलमान मुलाजिम ने हिन्दु को मार डाला। जमीन आसमान का फर्क है।

तो चीज यह है कि ऐसी चीज कह देने से क्या फायदा जिसका कोई सबूत नही है---कि तीन सौ आग से भरी कांगडियो की यूरश किसी आदमी पर चलेगी जब यह किसी आदमी के सर पर लगती है तो वह बच नही सकता। अभी हमारे खिलाफ दो साइड है। एक तो डिस्ग्रेन्टलड ग्रुप के ५-६ आदमी है जिनको कामयाबी नही हुई। पीछे अभी जो इलेक्शन हुये थे लीडर आफ दी हाउस के उसमे १०० के मुकाबले मे उन्हे ६ वोट मिली।

श्री ए० एम० तारिक़ : आप भी मुबालगे से काम ले रहे है। ७५ हैं, १०० नही है।

श्री पीर मुहम्मद खान : किसी वजह से ६ वोट पाने वालो को लीडर आफ दी हाउस तसलीम किया जा सकता है? मै इसमें कौसिल के मैम्बरो को भी शामिल करता हूं

मैं कहता हूं कि इस ग्रुप की तरफ से जो यह कहता है कि हमने काफी स्ट्रेंथ बना ली है, काश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कान्फीडेन्स मोशन लायेगा, बड़ी अच्छी बात है। और यह एक कान्सटिट्यूशनल वे है। आप तो कान्फीडेन्स मोशन लाइये और सारी बात ठीक हो जायेगी। अगर वह पास हो जायेगा तो आपको स्ट्रेंथ मालूम हो जायेगी। लेकिन आप कयामत तक इसको नहीं ला सकते है। जो कुछ मर्जी है आप कह सकते है और वह आपके लिये ठीक है। मै फिर आपको याद दिलाऊं कि एक जिन्दा शख्स २०० कांगडियो की आग की यूरश के नीचे आयेगा तो जिन्दा नही रह सकता। आप लोग और मौलवी मसऊदी साहब जो इस एक्शन के रूहेखान है और नई डिमान्ड पेश करते है, जिन की बड़ी तारीफ डिसग्रेन्टल्ड ग्रुप में की जाती है और वह नई नई बातें पेश करते है।

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*]

हमने काश्मीर में १६–१७ बरसों में बहुत काम किया और इसको आगे बढ़ाया लेकिन मीर वाज़ यूसुफ साहब और चौधरी गुलाम अब्बास को पाकिस्तान से वापस लाया जाये यह मांग हमारे मौलाना मसऊदी साहब करते हैं ताकि वह लोग राउन्ड टेबल कांफ्रेंस में बैठ कर काश्मीर के मामले का फैसला करे। कितनी हैरानी की बात है कि जो लोग इस तरह की बात किया करते है उनके खिलाफ अभी तक कुछ नही किया गया। मौलाना मसऊदी साहब वही शख्स है जिन्होने १९४७ ई० में और ४८ ई० के शुरू में चौधरी अब्बास को जो जम्मू की जेल मे कैद थे वहा से छुड़वाकर पाकिस्तान भिजवाया था, अब वही कह रहे है कि उन्हें पाकिस्तान से वापस लाया जाये। मीर वाज़ मोहम्मद युसूफ और गुलाम अब्बास ये दोनो रियासत के पाकिस्तान में शमूलियत के हक में थे। इस वक्त गुलाम अब्बास फौजी तैयारी कर रहे हैं आजाद काश्मीर मे ताकि वह काश्मीर के उस हिस्से पर जो कि हमारे कब्जे में है उस पर हमला कर सके। मौलवी मसऊदी साहब, मीर वाज़ साहब, गुलाम अब्बास साहब और शेख अब्दुल्ला साहब भी क्या काश्मीर के मामले पर फैसला कर सकते हैं? यह कितनी मज़हेका खेज़ बात है? अगर आप एक्शन कमेटी के मैम्बरान को देखेंगे, तो उसमें १२–१३ आदमी है और जिस में अक्सोरीयत मीर वाज़ मुहम्मद युसूफ के रिश्तेदारों की है। और बाकी आदमी प्रो-पाकिस्तानी पार्टीज के है जो मुस्लिम पोलिटिकल कांफ्रेंस और प्लेबीसाइट फ्रंट के मेम्बर है। इस एक्शन कमेटी में एक आदमी भी नेशनल कांफ्रेंस का नही है। बख्शी साहब ने इस एक्शन कमेटी के कामों को चलने नहीं दिया और हुकूमत में १९३७ ई० से लेकर आज तक इस किस्म के एलीमेंटस को उभरने नही दिया, यही उनका कुसूर है जिसकी वजह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आज उनको मजाकन आहनी आदमी कह रहे हैं। यही थोड़े अर्से पहले सही तौर पर आहनी आदमी थे और उनकी तारिफ करते थकते नही थे। खुश किस्मती से होम मिनिस्टर साहब ने १२ तारीख को राज्य सभा में यह बताया कि इस मूए-मुबारक की चोरी में नेशनल कांफ्रेंस का कोई हाथ नहीं था, उसमें एक से ज्यादा आदमी हैं और अभी मुमकिन है कि इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारी और करनी पड़े। नन्दा साहब ने आज यह भी कहा है कि दो तीन दिन में असली कल्परिट्स के नाम बता दूंगा। और एतराज कुनिन्देगां के मुताल्लिक मामला रौशन हो जायेगा कि उनका प्रापेगन्डा कहां तक सही है और फिर यह आहनी आदमी फौलादी आदमी बन जायेगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have taken enough time. Please wind up.

श्री पीर मुहम्मद खान: पहले स्पीकर को काफी टाइम दिया गया है इसलिये मुझे थोडा वक्त और मिलना चाहिये। तो मैं कह रहा था . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nearly half an hour.

श्री पीर मुहम्मद खान तो मैं कह रहा था कि एतराज करने वाले न घबरायें, दो तीन दिन मे दूध और पानी अलग हो जायेगा और मर्दे आहनी की पोजिशन आपको अच्छी तरह मालूम हो जायेगी । पार्लियामेंट मे इस तरह से तौहीन आमेज बाते करना पार्लियामेंट के रूल्ज के खिलाफ है । इस तरह की बाते करना बेजा है । बजा नही । इसके बाद मै मोशन आफ थैंक्स की ताईद करता हू और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हू कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत किया ।

श्री एन० एम० अनवर (मद्रास) मैं आपसे एक सवाल कर सकता हू कि इस नाजुक दौर मे बख्शी गुलाम मुहम्मद और अब्दुल रशीद वह कहा थे । और वह मैदान छोड कर क्यो चले गये ? तो क्या मौलाना मसऊदी साहब ने ही इस नाजुक सिच्युएशन को सम्भाला था ?

श्री पीर मुहम्मद खान मुझे इजाजत हो तो मै इनका जवाब दे दू । मैने जिस वक्त जवाब दिया था इस बात का, उस वक्त उन्होने फोलो नही किया । मैने कहा था कि लोगों मे यह बात फैलाई गई इस एक्शन कमेटी की जिसमे तकरीबन सेन्टरमेन्ट प्रो-पाकिस्तानी एलीमेन्ट शामिल है और उन्होने मौके का फायदा उठाया है । उन्होने लोगो के कान मे फूका कि यह सब कुछ बख्शी ने और नेशनल कांग्रेस ने कराया है ।]

THE DEPUTY CHAIRMAN You need not begin another speech You can give the explanation Shri Mehta

SHRI M M MEHTA (Gujarat): Madam, I rise in support of the Motion Our worthy Vice-President has elaborately discussed the various problems at home and abroad in his Address In the very first paragraph he said·

"In spite of difficulties and distractions, we have continued to move forwards our objective of a democratic and socialist order at home . . ."

I will agree with him as far as the democratic part is concerned but I have grave doubts as to whether we are marching towards a socialistic pattern or order He has said rightly only 'moved in spite difficulties and distractions' We talk too much of socialism—is it not—now-a-days and practically we do nothing absolutely It is a mockery of socialism I will say Our beloved Prime Minister alone has fought for socialism in this country and I am very sorry to say over here that no colleague of his has participat ed or shared his sentiments as yet and that is why, if we all his colleagues had given him—that is what I say, we all,—full support to his sentiments we would have achieved socialism long before but he is a great democrat He has accommodated the sentiments of others and that is how to-day if we look at the situation in India, I will dare say—as so many Members of the Planning Commission even agree with the opinion—that socialism is still far a way, unfortunately or I should say rather fortunately I am very glad that, you all know, by the Grace of God our beloved Prime Minister has come out of his serious illness The whole of India was very anxious about his health He is still one of the greatest figures in the world at present He is the only architect of modern India and idol of young India for ever I know how the younger people of India love him I know and I run an institution of young people in Kutch which is called the Tarun Mitra Mandal I know many of its members prayed to God, when our Prime Minister was not keeping well—they were prepared to give away their lives—to give Panditji a very long life so that he may consolidate his work of relieving the exploited masses of India and human beings everywhere I am very happy to see him again getting back his health and our ever-young Panditji is blossoming just like a flower

Since long the Congress has been the ruling party. While even in 1930 when Sardar was the President in Karachi, the Congress was talking since long about socialism. My heart always used to thrill when Sardar and Panditji roared that the people who did not believe in socialism should get out of the Congress. I will ask the Secretary, Shri K. K. Shah, here—unfortunately he is not here—how many people who did not believe in socialism, have left the Congress or will he give the list of members whom he has driven out of the Congress who did not believe in socialism.

AN HON. MEMBER: How can he?

SHRI M. M. MEHTA: I say that of Mr. Shah, I do not say that of the Minister. He must have a list and I ask for the list. The Secretary keeps a list. Up to this time the definition of socialism was not clear even. To some, capitalism was socialism and they wanted to define socialism. Now, today, I hope we are very clear about it. I think now in the coming year, if at all socialism is to come, it will come under the leadership of Panditji only; otherwise it is not going to come in India at all.

SHRI P. N. SAPRU: What is socialism?

SHRI M. M. MEHTA: I will define it. That is what I say. Still the Congress people have no clear idea of what socialism is. Gandhiji, who preached to us for so many years, was telling all these years: 'When you do not find the way, look at the poorest man of India.' That is what I am telling you, find out the way to satisfy his needs. To-day we have unfortunately not seen to the needs of the poorest man in India. Look at our Plans. As the very basis of the Plan we have taken the village with more than 10,000 people and we have done everything to give facilities to them but the real poor people in India live in the villages. Those villages of below 10,000 people are still rotting as such. I was saying so many times on the floor of the House that even drinking water is denied to them. Even in my State of Gujarat, there are more than 4,000 villages where there is no drinking water at all. There is no source of drinking water. I come from a district of Kutch, a border district. It was promised by Sardar Patel that it would be put in the line of the neighbouring States. The Centre took it and I am very miserable and I have to say with pangs in my heart that today there are plenty of villages that are being evacuated only because of lack of drinking water. I do not ask for anything beyond any necessities or for luxuries. Do you call this the socialism that we have marched forward to? I will give you one example about the administration. Last time, while speaking on ex-Rulers' Privy Purses that are being given to them, when it was said that they are not to pay taxes on their investments and Government Securities, the Government was surprised as to under what law this was given to them and as I come to know, they have decided to exempt them up to 1963 and henceforward to charge the taxes on their investments. I do not understand it, the gross callousness on the part of the administration and yet no officer or no Department is taken to task. I do not understand why the Princes are being exempted as such up to 1963 when we come to know that it is not a legitimate thing. Do you call this socialism?

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): This is not socialism.

SHRI M. M. MEHTA: Still we talk of socialism so proudly. That is what I say. That does not mean that I do not believe in planned economy. I myself believe in planned economy and I am an admirer of planned economy. But as I told you, our plans are very faulty. We have lost the very basis of planning. Even so many members of the Planning Commission have expressed the same view.

AN HON. MEMBER: Who are the persons?

SHRI M. M. MEHTA: If you read the papers, you will find it. There are plenty of them. The main occupation of the village, namely agriculture, has been neglected as has been agreed to by the President himself in his Address. You can see it in paragraph 7 of the Address where it is stated:

> "Despite these satisfactory trends, the overall rate of economic growth has lagged behind the Plan target. This is mainly due to the shortage in agricultural production which in 1962-63 showed a fall of 3.3 per cent."

And further:

> "A steady increase in agricultural production is the most important task before us today."

AN HON. MEMBER: That is an admission.

SHRI M. M. MEHTA: They have lagged behind the target and the main question is agricultural production and that is being neglected. This rise in the price of essential commodities we are not able to control. That is the main thing today and the middle-class people and the poor people find that the rise in prices of essential commodities comes in their way. That is their main concern. Of course, we have developed some big projects, as has been referred to by the President. The whole of India will be proud of these big projects that we have in the public sector. I have visited so many of them and I feel proud of them and the whole of India will be proud of them. But then there are the other problems which daily touch the people. Today after nearly completing three Plans, if the people still find that they do not get enough to eat and they feel that they are being neglected then I do not know how we are marching towards socialism at all.

The second thing and the most important thing that I would like to submit is that unless this present pattern of the administration is changed, we are never going to achieve socialism. It is the same British bureaucratic pattern of administration under which we are being administered. Even the I.A.S. people newly recruited today, do not know anything about what India wants to achieve. They are just minted a bureaucratic officers.

AN HON. MEMBER: But they are honest.

SHRI M. M. MEHTA: As far as this machinery is concerned, whether it is working under Lord Mountbatten or Pandit Nehru, the coin comes out with the same print. There is exploitation and corruption, nothing else. We require to change the whole of this machinery. However good the metal may be that you put in, the coin that comes out will be the same. The whole die requires to be changed.

AN HON. MEMBER: What is your suggestion?

SHRI M. M. MEHTA: I will give one or two examples. I was very much surprised to know that in all the public sector concerns there is no auditing of the store purchases. You visit any public sector big project, I was told that there is no auditing of the store purchases.

SHRI N. C. KASLIWAL: You are quite wrong.

SHRI M. M. MEHTA: What about Mr. Goenka?

SHRI N. C. KASLIWAL: It is absolutely wrong. There is audit.

SHRI M. M. MEHTA: You mean after the store is disposed of there is audit? I am prepared to prove it from the very people who are there. Even when I asked the people in the Food Ministry, they agreed that in the case of foodgrains there is no auditing about it. It is only on paper.

AN. HON. MEMBER: Question

SHRI M. M. MEHTA: There is no actual auditing. It is shown in the figures.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: On a point of personal explanation. As a member of the Public Accounts Committee, I would submit that whatever the hon. Member has stated just now is not borne out by the facts.

AN HON. MEMBER: He said it is shown on paper.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mehta, you better carry on. You have only nine more minutes.

SHRI M. M. MEHTA: That is what I came to know from the Head of the Department in the Natural Gas Commission—Mr. Goenka. At Dehra Dun I asked him about it and he told me that there was no auditing.

SHRI JOSEPH MATHEN (Kerala): You probably did not understand what he said.

SHRI M. M. MEHTA: You don't bother about my understanding. I know that. The second thing is . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is the third thing.

SHRI M. M. MEHTA: May be third thing. Whether it is first or third, it is immaterial, but it is a very important thing when we talk of socialism. Due to certain geographical and geological conditions, some parts of India are coming up, while certain other parts of India lag behind like anything. So the people in some parts get more facilities of life while the people in certain others do not get the opportunities to come up. The Administration should do something about this. Is it not our duty, when we talk of socialism to give equal opportunities to all the people in India?

AN HON. MEMBER: Are they not being given?

SHRI M. M. MEHTA: Definitely no. There are States which because of their geographical and geological position are in a much better position than other States in India. That is one of the reasons why a change in the way of the Administration is needed.

SHRI JOSEPH MATHEN: Can you change geography?

SHRI M. M. MEHTA: It is not a question of changing geography. It is a question of the economic distribution of the revenue, of all the revenue that we collect Pool all the revenues of all the States and hand them over to a Board composed of all the Finance Ministers of all the States, the Union Finance Minister being its president or chairman. And then distribute that pooled revenue according to the needs of the States. I can discuss about this plan, for I have my own way of thinking. And if you do that then all these quarrels about boundaries and rivers and so on, will not be there and India will remain one integrated whole. This does not mean that I advocate a unitary form of Government at the Centre. No, for I know the practical drawbacks of that. I only advocate this in the case of revenue. If consideration is given to this point then we will have an integrated India and only then will everybody feel a thrill when any part makes an advance. In this way I think we can achieve the goal of socialism.

I am very happy and I feel like congratulating the Finance Minister, Shri T. T. Krishnamachari.

AN HON. MEMBER: For what?

SHRI M M. MEHTA: I think he has decided to give pension to the widows and minor dependants of Government servants. I think he will find out a way to give the same kind of facilities to all servants not only to Government servants but to all concerned. It is a very difficult task, but you will have to do it. The time will come when you cannot differentiate between Government servants and other servants. Otherwise it becomes an official socialism and not real socialism, the socialism of the nation. I know that the Finance Minister has the real picture about the middleclass and lower classes also. He was the first person

[Shri M. M. Mehta.]

also who put up a Budget which can be called an attempt towards going in the direction of socialism. Now the next Budget is coming and I know that at least there will be no more taxes.

SHRI JOSEPH MATHEN: How? You know the Budget?

SHRI M. M. MEHTA: The Government has collected all the money. As you know from the appraisal of the Plan we have not put up anything new and so all that money should be there lying. One thing I would like to say. There are some hillocks in the social plain of India in the form of some few rich houses. They should be tapered off to the level of the plain. Only then will real socialism come. Due to the emergency or whatever it is, it is these few houses that have benefited. The other point is the availability of plenty of money in religious trusts absolutely unused. Why not that money be mobilised for the sake of those people who belong to those sects? This will go a long way.

The Address contains reference to many projects but I would like to remind the House that Khandla is being neglected. It is still not connected with a Broad Gauge line and there has been talk of a free trade zone ever since the inception of the port but I am sorry to tell Manubhai that nothing much has been done, no work has been started. Khandla is not even linked to a highway. It requires some more attention. (*Interrupton*). Yes it is in his charge, the creation of a free trade zone.

I totally agree with our Vice-President in regard to the coming up of the projects but there is one danger facing us and I would like to draw the attention of the House to this fact and that is about future intentions of Mr. Bhupesh Gupta and his friends on the opposite. They are trying to agitate industrial labour for a general strike like the one we had in 1957. I think this will retard our industrial progress if we are not very careful about it and if we do not take proper steps. This, of course, is a first step in the election campaign of 1967. Whatever may be the thing, we must be prepared to meet that threat. It is not that we can meet the threat only by yielding to their demands, by giving a few more rupees to industrial workers. They constitute only a small section of the people depending on manual labour. The real solution, as I said earlier, is to bring down the prices of essential commodities. We have seen that labour in Ahmedabad was given bonus, and in other places too, but what is the result? A few of the people in the area got an increase and the rates immediately go up, they get inflated. Similarly, increase in emoluments will have repercussions.

It is complained that our coastal trade is not coming up. We have a coastline of 2900 miles and 150 working ports. In spite of this, the complaint is that freight is not coming in. Some people say that the freight rate is not well adjusted. I agree with this. I know about Khandla and that is why I can say this. It is said that Khandla is to replace Karachi. I will ask the Government and our worthy Ministers present here, what was the freight rate to Karachi before partition? It was much cheaper to send goods from Cochin to Karachi than even to Bombay but today the rates and other charges in Khandla are so high that even North Gujarat people prefer to go to Bombay and export their materials than having them shipped from Khandla. So many items are there. I specially want to draw the attention of the House to the question of adjustment of freight rate.

There are plenty of things to speak about but time being limited I would now talk about the problems abroad, especially about China and Pakistan. It is said about China that there is now no war but I want to ask this House, what about our promise to reoccupy our land conquered by the Chinese? There is plenty of misunder-

standing about the letter of Mrs. Bandaranaike to Mr. Chou En-lai, as pointed out by some friends there. This requires immediate clearing up of our intentions on the floor of the House. If we do not talk anything about it, the boundary will remain where it is today. What are our intentions? Are we going to march up to the MacMahon Line or not? This should be made clear.

I am happy to note that we have started taking some strong action against Pakistan and the Western Powers, the sponsors of the Resolution. It has been made clear before the world that these Western Powers, Britain and America pamper Pakistan and all the mischief that is done against India is due to this. There is no doubt anywhere about this. I am happy that Mr. Chagla boycotted a reception given at the U.N. in New York. I am happy also to see reports in the Press that Shri Lal Bahadur called the American Ambassador and the British High Commissioner and talked to them some plain thing about our thinking. This attitude is required in a dynamic way to deal with Pakistan. We have the while been writing protest notes; I do not know what is their number and Pakistan has become immune to them. We must speak in the language that Pakistan understands. There is no point in speaking any other language which has the same effect as talking to a deaf man. I congratulate our Government for talking from this angle.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Madam Deputy Chairman, first of all I thank you for giving me an opportunity early to express my views We are considering the Motion of Thanks on the Address delivered by the Vice-President discharging the functions of the President.

Naturally when we are discussing this Motion, everybody is overwhelmed with the events that have recently occurred in East Pakistan and West Bengal, events in Khulna, Narayangunj, Jessore which were well-organised and pre-planned. There is no doubt about this because we learn from newspapers that more than twenty thousand people were organised to lead the procession and parade through the streets of the cities of Pakistan indulging in loot, arson, massacre and mass murder. The question is, who is responsible for all those things? There is no doubt that the President of Pakistan, the Foreign Minister, Mr. Bhutto, and the officials in East Pakistan were responsible for inciting the feelings of citizens in East Pakistan. President Ayub Khan had issued several statements instigating the masses in East Pakistan. Mr. Bhutto had mischievously issued a statement that sacred relic at Hazratbal shrine was stolen by Hindus, the most irresponsible statement to be made by a person like the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Bhutto. The Pakistan Radio also was indulging in a most mischievous and malicious propaganda and hatred campaign against India. It was announced by the Pakistan Radio that more than one lakh of Muslims from the Twentyfour Parganas District had crossed into Pakistan. Therefore, it will be noticed that high-ranking officials and Ministers from Pakistan have instigated people there to start this communal frenzy and orgy and incited those people to indulge in mass murder, looting and arson. Madam, we in this country are perturbed about the minority people in East Pakistan. Thousands of people have come from Pakistan. I think this morning only the number was given by the Chief Minister of West Bengal and according to the statement made by him about 15,000 people have crossed the border from Pakistan into India. Apart from that, thousands of people had to lose their lives. No doubt the Press is controlled in Pakistan. There was strict censorship and no news could trickle out of Pakistan but whatever news has trickled out of Pakistan clearly proves that thousands of people have lost their lives and property.

Madam, a report appeared in the *The Guardian* published from Man-

[Shri B. D. Khobaragade.]

chester and London. In that report which was despatched from Dacca by Reuter it is mentioned that this was the biggest Hindu-Muslim riot there in the last ten years. The Reuter correspondent form Dacca has claimed that this was the biggest riot in the last ten years in Pakistan. Another proof is also there. One American peace corps nurse who came from Dacca has revealed that six hundred people were dead in the Dacca Medical College Hospital alone. From this fact we can realise that the number of people who lost their lives in these riots must be more than thousand.

If we refer to the Nehru-Liaquat Ali pact, we find that it is one of the conditions of the agreement that there will be complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to law and morality and the members of the minority community shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in public life of their country. It is one of the conditions of this pact that the life, property and honour of the minority community should be respected and protected but unfortunately this has not been the case. It is also one of the conditions of this pact that the Government will take prompt and effective steps to prevent the dissemination of news and mischievous information calculated to rouse communal passion by the Press, Radio or by any individual or organisation but this condition also has been violated by no less a person than President Ayub Khan and Foreign Minister, Mr. Bhutto. Therefore what is the use of having this Nehru-Liaquat Ali pact if the conditions of this pact are to be violated by the highest officials in Pakistan?

Madam, what is the solution to this problem? It is suggested by some political leaders in India that there should be exchange of population but I do not approve of this solution. Whatever the number of Hindus who want to come from East Pakistan, we would welcome them and I would suggest that whatever restrictions are imposed on immigrants should be removed. Whichever Hindu wants to come to India from Pakistan must be allowed to come but it does not mean that we must forcibly ask the Muslims in this country to go to Pakistan in exchange for the Hindus who come to India from Pakistan. We cannot force the Muslims in this country to leave the country. It is our responsibility to protect their lives also. Unfortunately in West Bengal and in Calcutta we could not take steps earlier. The State Government in Calcutta did not take steps earlier. The Chief Minister was busy with his Congress session in Bhubaneswar. In view of the incidents and happenings in East Pakistan, the Chief Minister should have returned immediately to Calcutta but he did not return. He came later on when the situation had deteriorated to such an extent that it had gone out of control, so that he had to summon the military there. Naturally, during this period the minorities in West Bengal had to suffer to some extent. There are Press reports to that effect and the Muslims in Calcutta and West Bengal had to suffer. Had the State Government been prompt enough, I am quite sure that the Government would have been in a position to control the situation and to save the lives and property of the Muslims in Calcutta and West Bengal but unfortunately they could not do so. Therefore we should try to protect the life and property of the Muslims and minorities in this country. We should not ask them to go out of the country to Pakistan. But we should allow all the Hindus if they want to come, to come to India and there should be no restrictions on them whatsoever. If possible, we should try to bring moral and diplomatic pressure on Pakistan and try to get some territory from

Pakistan to rehabilitate those persons who are crossing over from Pakistan to India. (*Interruption*) Naturally it is difficult task; perhaps an impossible task but it does not matter. Our Government should make an effort and try to bring diplomatic pressure on Pakistan. Instead of giving one bit here one bit there as in the case of Berubari, we should try to get territory from Pakistan and try to rehabilitate our people who are coming from Pakistan.

Madam, I will refer to the incidents in Kashmir also because this Pakistan trouble is the outcome of the most unfortunate incident that took place in Kashmir. There is no doubt that the theft of the sacred relic from the Hazratbal shrine was also pre-planned; otherwise how was it possible for the people to organise a rally at four of the clock in the morning, just two hours after the sacred relic was stolen? The sacred relic was stolen at about two of the clock in the night and immediately afterwards even before the break of day they could organise a mass rally and a demonstration. It means that those people who organised the rally and the demonstration knew all about it. They must have planned and conspired to steal the sacred relic. Madam, there have been reports in the Press that the State Government is rather trying to protect some persons there. This is the most unfortunate thing. This morning also there was demand in this House that the names of those culprits who were responsible for this theft should be disclosed but the names have not been disclosed even today. According to Press reports, Bakshi Ghulam Mohammed and some of his colleagues who were disgruntled because they were removed from power, had to do something with the theft. Only on the 6th February last when Bakshi Ghulam Mohammed tried to address a public meeting in Jammu, he had to face angry demonstrations and he could not hold his meeting successfully there It means that those people, those disgruntled elements definitely had a hand in the theft of the sacred relic and, therefore, it is very essential that all those persons, however highly placed they may be, must be dealt with severely according to the provisions of law. Of course, Mr. Lal Bahadur Shastri has been in a position to secure the sacred relic back and also to get it verified by all those persons who knew about it. But that is only the end of one chapter. It does not solve the whole Kashmir problem. It is essential that in Kashmir we should have such a Government which will enjoy the confidence of the masses in Kashmir. From Press reports and from the feelings of the people there, we learn that they had agitated against the State Government and not against the Government of India. They have always been saying that the Indian Government should intervene. The people of Kashmir have been demanding that the Central Government should take the whole case in their own hands, that the Central Government should investigate the offence and deal with all the culprits. Not only that. The demand has been persistently made that a judge from outside Kashmir should be brought to try the offence. It means beyond doubt that the people of Kashmir have full faith and confidence in the Government of India, in the Indian people, in the Indian nation as a whole. They have lost faith only in the Government of Mr. Shams-ud-Din, who wants to rule there according to the good wishes of Bakshi Ghulam Mohammed. Therefore, if we want to solve the Kashmir problem, if we want to have law and order and peace and tranquility in Kashmir, it becomes essential that those people who have lost the confidence of the people in Kashmir should be removed from power and those persons who are still enjoying the confidence of the masses in Kashmir should be allowed to govern that State. A suggestion has been made that the President's Rule should be imposed there. I do not agree with it. In the present international situation it will create more complications. Therefore instead of imposing the President's Rule over Kashmir, we can only

[Shri B. D. Khobaragade.]

change the Government which has lost the confidence of the people and instal such Government and such people there as would enjoy the people's confidence.

Madam, we have spoken about the minorities in East Pakistan. We have spoken about the atrocities perpetrated on Muslim minorities in Calcutta, in West Bengal. But what about the atrocities that are being perpetrated on the Buddhist minorities in this country? I will refer to one incident. On the 22nd December 1963, four or five Buddhist women, Scheduled Caste women, were paraded through the streets of a village completely naked. This happened in December, 1963, in Shirazgaon village, in the Aurangabad district of Maharashtra State. It is unfortunate that Members of Parliament do not know it. Even Mr. Manubhai Shah's facial expression seems to suggest that he does not know about this incident. It means that the press in India has completely slept over this incident. It is more shameful and disgraceful than that. Women are paraded through the streets naked and the people of this country do not know it. Why? We have tried to raise this question in this House. I had also given notice of a Motion for Papers, but unfortunately when the Buddhist minorities are being treated in this way no notice is being taken. Madam, we have taken notice of the atrocities perpetrated on Muslim minorities in West Bengal. Is it because Pakistan is there to voice their protest against this happening? If you give the impression that the minorities will be protected only if there is some foreign power to protest against it, if it is the attitude of the Government that they will take cognisance of atrocities perpetrated on the minorities only if foreign Governments are voicing their protests, then I think the Government is following a most dangerous policy. Are you going to take cognisance of atrocities perpetrated on Christians only if some Christian powers come and voice their protest? Are you going to take cognisance of atrocities perpetrated on Muslims only if some Muslim powers come and protest? Are you going to take cognisance of atrocities perpetrated on Buddhists only if some Buddhist nations come and protest? This is a dangerous trend and a dangerous policy. We are citizens of this country and we are entitled to live in this country with respect and honour and, therefore, it is the responsibility of the Government to see that no such atrocities are perpetrated on the minorities whether they happen to be Muslims, whether they happen to be Christians, whether they happen to be Buddhists. Therefore, I would urge upon the Government that they should look into the affair in Shirazgaon village in Maharashtra State, give protection to the Buddhist minorities there and assure the whole country.

Finally, I would refer to one more question and that is regarding the issue of Belgaum and the issue of Goa. We have been told again and again that the question of Belgaum and Karwar may be solved soon and assurances were also given by the former Home Minister, Mr. Lal Bahadur Shastri. Unfortunately, so far, this question has not been solved. Only a few days back there appeared in the Press the news that our Home Minister, Mr. Gulzarilal Nanda, has evolved his own formula, by which he wants to solve the problem. Belgaum and Karwar, the two district towns, are to be handed over to Mysore State. If the news about this formula is correct then I must emphatically state here that the people from Maharashtra will never be satisfied with this solution or with this formula. We have been agitating since long that Belgaum and Karwar are predominantly Marathi-speaking areas and, therefore, they should be merged with Maharashtra In the past so many elections—local elections as well as parliamentary elections—the people of Belgaum and Karwar have demonstrated beyond reasonable doubt that they want to merge with Maharashtra and, therefore, it is essential that Belgaum and Karwar should be merged

with Maharashtra immediately. I hope our Government will soon find a favourable solution and try to solve this problem.

Then, coming to the problem of Goa, about two or three months back elections were held to the Goa Assembly. The people in Goa, by voting in favour of the Maharashtra Merger Party—the Maharashtra Gomantak Dal—have clearly indicated that they want Goa to be merged with Maharashtra. Unfortunately, in spite of this clear verdict given by the people in Goa, the Government is trying to keep Goa separate. Immediately after the election results were out, the Government tried to bring before this House a Bill by which they wanted to remove Goa from the jurisdiction of the Bombay High Court. That Bill seeks to establish a separate Court in Goa and thus promote separatist tendencies in Goa. This is a most unfortunate development and is uncalled for. According to the law, immediately after the elections, three Members are to be nominated to the Assembly. But spite of the fact that the elections were over about two months back, in spite of the fact that the Assembly had its first session also, these three members have not been nominated so far. Are we to understand that the Central Government is still manoeuvring to convert its minority in Goa into a mojority and to overthrow the majority Government by this indirect way? Madam it is high time that these three people are nominated. There were reports in the Press that when the Chief Minister of Goa, Mr. Bandodkar, was in Delhi for the Republic Day celebrations, he was shabbily treated by a Central Government official, and a protest has been voiced against this. While speaking on the Goa Bill last year, I had opposed this provision of nominating three members, because at that time itself I had said that by this provision perhaps the Central Government would try to convert the majority into a minority and the minority into a majority That apprehension is still in the minds of the people of Goa and Maharashtra. Therefore, I suggest that those three members should be immediately nominated, and if they are to be nominated they should be nominated according to the advice tendered by the Chief Minister of Goa, that is , Mr. Bandodkar. His advice in this respect should not be ignored and should not be neglected. In view of all those developments in Goa, Madam, I would suggest that Goa should be merged immediately with Maharashtra. Unfortunately we find that there is some kind of animus, there is some kind of indifference towards Maharashtra's problems. The other day only we have read in the papers and this morning also this question was raised in the House that an important and influential person, the President of the Maharashtra Congress Committee—not of any opposition Party but the President of the Maharashtra Congress Committee—was not allowed to hold a meeting in Nagar Haveli. Why? Because the people of Nagar Haveli want it to be merged with Maharashtra and the Central Government does not want it. Does it mean that the President of the Congress Committee should not be allowed to hold meetings? Is there any restriction on it? As a citizen of this free country everybody is entitled to travel throughout the whole country, to hold meetings, to organise mass meetings, to solve their own problems. Therefore, Madam, I would only say that all these problems, whether it is Dadar and Nagar Haveli or whether it is Goa or whether it is Belgaum or Karwar, should be solved as early as possible, and in no case injustice should be done to Maharashtra.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR (Madras): Madam, our hearts bleed when we hear about the atrocities in East Pakistan. We are entirely in agreement with the previous speaker that all minorities, their life, property and honour should be protected, but it is unfortunate that all happenings in East Pakistan have their inevitable reactions in West Bengal. What we are immediately concerned with is a greater prob'em

[Shri T. S. Avinashilingam Chettiar.]

It seems as if you cannot any more stop a large migration of Hindus from East Pakistan to West Bengal. Time was when we pacified them, time was when they themselves had hopes that life would get settled for them in Pakistan. But those hopes are being belied and we will not be surprised if millions of people in the next few months or years cross over to West Bengal. That makes us face the problem as to what we shall do with the large masses of men that are bound to come. Already 20,000 people have come. You cannot prevent their coming. I am happy that it has been stated that the problem will be tackled on a national basis and not on a West Bengal basis. While that is true, yet the fact remains that the increase in population in India by way of addition to its strength of a few lakhs, 10 lakhs or 15 lakhs or 30 lakhs, will make a considerable difference.

In this connection I cannot help referring to the illegal migrants from East Pakistan, Muslim migrants most of them, to Tripura and Assam. What stands in the way of our Government in those places from preventing them, I am unable to see. Part of the blame must be borne by the Ministry of Assam. Assam's politics have been such that I do not want to say anything more than this that they seem to prefer Bengali Muslims to Bengali Hindus for political reasons That statement has been made more than once in this House, but still we see that immigrants from Pakistan are entering Assam. Apart from pious explanations, nothing much has been done to prevent it. If Muslims are coming into India on the one side and Hindus from East Pakistan are coming into India on the other side, what is going to happen to us? Madam, this is a very grave problem. There is no easy way of solving that problem. But it seems as if the time has come when at least we will have to face a forced exchange of population, not by our own volition but by the action of those populations. I think this must be raised internationally when such a large number of population is coming and when we cannot claim compensatory land from East Pakistan for that purpose. We will be cowards if we do not raise this problem. When populations come, they have been living on land in that country and they must be provided with the requisite amount of land contiguous to this country so that those populations may live on them.

This leads to another problem, and that is the question of population. It is unfortunate—I would not say unfortunate—it is a well-recognised *problem but the President has not* chosen to refer to it in his statement. What has happened to us in this country? During the decade 1911—21 the population was only 249 million During the 30 years following 1921, however, the population has grown by about 44 per cent and the number has increased from 250 million to 360 million. During the decade 1951—61 the growth of the Indian population has been exceptionally high recording a growth of the order of 22 per cent or 2.2 per cent per annum. The population is already around 465 million on record, that is at the end of December last year. Demographers have calculated that it is not 438 million but it is 465 million. It is anticipated that by 1976 the figures would be round about 625 million. That is what the projection of figures by demographers has told us in this scientific paper. What is going to happen to us with this explosion of population? This is based on the population of India and not of the new entrants. And then we have development plans, we want to raise the standard of life of our people, we want to raised the standard of income of our people. Something has happened. When the national income has risen by nearly 50 per cent, the *per capita* income has risen only by 16 per cent; and 16 per cent and Rs. 272 will only mean Rs. 300 per year, not per month. It

is per year, the *per capita* income of the population, with all the Five Year Plans that we are having. We have a proverb in Tamil: mixing asafoetida in the sea. Asafoetida is a sweet-smelling thing which you mix in preparations in pots.

THE MINISTER OF SUPPLY (SHRI JAISUKHLAL HATHI): Hing.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Yes, hing. If you mix it in the ocean, what will happen? Nothing will happen. This is the case with our development plans. What has happened to our food? We wanted to increase the food production to nearly 90 million tons. Instead of having nearly 90 million tons, we have gone back. The President's Address makes it clear that we lost 3·3 per cent. in the last year, and about this year, what does the newspaper say? The production of food has not been very much better, and what does this mean? We wanted to reach one hundred million tons by the end of the Third Year Plan but the population that is growing will not be satisfied even if it is one hundred million tons. All that we produce will not satisfy the growing population of this country. And the greatest and the gravest problem that faces us in this country is how we are going to face the population explosion in this country. And not a word about that has been said—a great problem—in this Address. While I support the Motion of Thanks, I would like to draw the attention of this House, this Government and this country that something should be done. Something is being done. We have family planning clinics; we have a Family Planning Board. Something is being done. Well, I was talking with certain foreigners, Americans, and we were discussing India's problems in some of the universities where I was asked to speak about the problem. Some of them said that they wanted to help us, that they were willing. They said, "But sometimes when we see the population explosion in your country, when we see the tremendous growth of population in your country, we begin to doubt whether with all our help you can raise the standard of life of your people because all the income that you get gets divided up among the exceedingly large population which is growing." They want to help us with the idea that our standard of living will increase and that we will become a stable Government. But with misery all round, with poverty all round, with squalor all round, with the population increasing all round, what will happen to all the aid that they are giving? This is a doubt which is creeping not only into them but into the minds of economists and other people who see the future of India with a vision. And I want to know whether the steps that we have taken for the control of the population in the last few years—we have taken some steps—have been effective enough to arrest the growth of population. That is the question. I know that questions are answered. My friend, Mr. Karmarkar, when he was the Health Minister, and the present Health Minister would give us a long list of the things that were being done; with those answers you can shut the mouths of the people in this House but you cannot arrest the growth of population in this country.

4 P.M.

SHRI D. P. KARMAKAR (Mysore): You can avoid marriage.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: I say, Madam Deputy Chairman, all that has been done in this direction has not been much effective and unless something effective is done, all our efforts at improving the status of the people of this country and the standard of their life will be in vain. And we have not been seized of the urgency of this problem. That is my complaint.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: What is your solution?

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: My solution is . . .

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: . . . that they should follow your example.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: That is a great solution which every one cannot follow, many people cannot. Whatever steps the other countries might have taken—you do not expect me to tell you, explain to you, the ways and means how this can be done—this must be done, something drastic. Firstly, the people must be convinced that this is good. Many people are not yet convinced. Even villagers with eight or ten children say that it is God's will. It is for us to preach. We go out for elections, to get votes. I know what efforts we make. Do we make any efforts to convince people having too many children about this? We have not done that. Not only that. Are we convinced as to the methods? Have we given them facilities? We are having family planning clinics in the cities, but have we given those facilities to the villagers? Everybody knows how it can be done. The only thing is that it has not been taken seriously. The urgency of it has not been imported into this problem. And then it will remain unsolved for ever, and I want that urgency to happen. I want this problem to be faced not only by the upper strata of society. In the upper strata of society it always happens, because they are very clever: Many civil servants with two or three children have undergone this operation, two thousand or three thousand. But people with a low income, people with many children, they do not see the urgency of it. It requires a tremendous amount of propaganda to bring to them a sense of urgency, and that must be done if India is to live.

I may refer to another matter. This matter of agricultural production has been talked about so many times in this House. But somehow agricultural production, with all the tricks that you are trying to do, is not going up. What is the reason? I see a fundamental reason for our failure in agricultural production. When the cost of production rises up, what do the industrialists do? They shout, they come to the Ministries and the Ministry people hear them. Tariff Boards are appointed; recommendations are made and up go the prices. But what happens to agriculture? Here is a statement made by the Minister of Food only in the last session. He said:

> " . . . I was referring to the question of the cost of production which we have to bear in mind when we approach this question. I mention that as far as West Bengal is concerned, it has been calculated by our surveys that it comes to Rs. 24·30 nP. per maund of rice."

But the price paid in West Bengal for getting rice is from Rs. 21 to Rs. 25. In Madras, the cost of production is Rs. 19·05 nP. while the purchase price is from Rs. 15 to Rs. 17. In Andhra Pradesh, the cost of production comes to Rs. 21, whereas the price paid is from Rs. 16 to Rs. 18. And he says further—

> "We agree that this price is less than the cost of production."

Then he has got another argument as to why he wants to get rice at a lower price than the cost of production and here is what he says. He says that Americans have come to this country and have made recommendations that you must give a price which is near the cost of production and more. He says that you cannot give protection to that section to the extent that protection is given in the West. He refers to the West. He says:

> "Of course, we cannot afford to give price support of the level that is being given in countries like the United States or for that matter any developed country in the West because, as far as India is concerned, 70 to 75 per cent. of the population directly or indirectly depends on agriculture. So, if you protect that section to the extent that protection is given in the West, what would happen is that the en-

tire burden would shift on to the 20 per cent. section, which would be an unbearable burden. So, there is a limit to our giving price support or a remunerative price to the farmer. That has also to be borne in mind. In the USA, only 11 or 12 per cent. of the population is dependent on agriculture . . ."

Madam, I entirely disagree with what the Government has said in this matter. Who pays the price of the rice? The man who eats it. Seventy per cent of the people live in villages and twenty per cent of the people who consume rice pay a higher price. How do you say that the 20 per cent in the cities will not bear the price rise simply because 70 per cent live in villages and 20 per cent in towns? I say, this is not giving a proper deal to the agriculturist.

SHRI R K BHUWALKA (West Bengal): In West Bengal it is Rs. 35 now.

SHRI T. S AVINASHILINGAM CHETTIAR: And so long as this policy is pursued, the agriculturist will not put his heart and mind. If he does not produce, he will not starve, but it is towns people who will starve. Even if he does not produce, he will get enough to eat, but it is the other people who will not get enough to eat and so, this is a very wrong policy not to give a proper price to the agriculturist. I say unless your attitude towards food production and towards agriculture is peasant-oriented so that the peasant may live, so that the peasant may prosper, however much you may cry from the house-top, with all the big officials that you have in the Secretariat you cannot produce one grain of rice. They can advise They draw circulars. They can issue orders, but that cannot produce grains It is the peasants who are in the six lakhs of villages and who are actually engaged in agriculture who have to produce the grains, and if they are to produce rice, they must be encouraged, they must be given the proper price, and according to the statement made in this House by the Minister for Food, it is very correct; he said it very plainly that the price that they are giving for procuring rice is less than the cost of production of rice. To do so is wrong, entirely wrong and I think it will not do for encouraging higher production. I do not like to go into other steps which can give greater production, but the basic policy of not paying a proper price for the agriculturists and cultivators is not a right policy, and unless that policy is changed, I look upon with gloom at the prospect of higher production in agriculture. Make it worth while. If a man in the town can have a motor-car and can send his son to the engineering college or medical college, why should not a man in the village do it? He will have the ambition. He must do it. And if you don't get him a proper price, how will he educate his children? This is not the proper way, and I would appeal that the point of view which has been represented by the Food Minister in his statement before this House should change, and the sooner it changes, it will be better for higher production in this country.

Now, Madam Deputy Chairman, I come to another matter, and that is the matter of avoidance of corruption. I am very happy that Shri Gulzarilal Nanda, since he became the Home Minister, has been devoting himself to this very big question. I hope we will have some time for a discussion on that Vigilance Commission which he is proposing to appoint. Fifteen years back we thought that corruption was impossible at higher levels in the Secretariat, for example, even at the level of Secretary; about fifteen or twenty years back we never thought that corruption would prevail even at the higher levels; we thought it was impossible, but it is unfortunate today, we, hear charges of corruption. People come to us and tell us about them. Somebody says that it is impossible, but somebody else comes and says that it is possible—it was only a matter of money. They say: you go

[Shri T. S. Avinashilingam Chettiar.]

with a decent sum of money and you get a licence. And they prove it too. I say, maybe that the Government thinks that these controls are inevitable. But the greater the controls, the greater the corruption. They go together; you cannot avoid it. I have a few suggestions to make to show how it can be tackled. Mere *danda* (stick) does not stop corruption. You can do it, there is some deterrent punishment and you can give it. But then there is so much temptation for them and when one sees the other making a fortune through corrupt means, he begins to think, "Why not I too make something out of it?" Now I make a few suggestions to the Government. In those departments where favours are shown, where licences are issued, where they have a lot of discretion, a man takes some time to learn and to think about corruption. And here I say that at least once in three or five years the man must be changed from the tempting departments to more innocent departments.

SHRI D. P. KARMARKAR: Like post office.

SHRI T S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Yes, like post office, like education, like health and other departments which are fairly innocent. It is where you deal with the rich people that the danger comes in. They don't care for a lakh of rupees; they care nothing. The Ashoka Hotel today is a very fine place—I understand—where people can meet over cups of tea or coffee, or dinner or lunch, and talk many things. Now I think that the transfer of officials from these dangerous departments to innocent departments once in three years or five years will at least deter them before they get emboldened to take to corruption. After all they require time to pick up courage.

SHRI D. P. KARMARKAR: The incoming people will get the opportunity also.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: Our ex-Health Minister seems to have experience, but I do not think so. Now I shall also ask the same question. The question was asked about Ministers, as to what organisation was being set up to enquire into the conduct of Ministers. You know, Madam Deputy Chairman, as things stand, allegations are being made, and there is some truth in them. Certain very grave allegations have been made against Ministers, and corruption gets encouraged when the top people go free.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA) in the Chair]

I would like to know what is being done in this regard; something must be done. I know this is politics; this is more than administration and when politics comes in, many things have to be reckoned with—the man's strength, how many followers he has in the Parliament or in the Assembly; many things come in. Therefore I say that some top man in the judicial line, one who is beyond influence, one who will go into these matters also must be put on the job, because when the top source is corrupt, the others alone cannot be blamed. Thirdly, deterrent punishment should be given whenever they are found out. Many times the really corrupt persons cannot be found, and whenever they are found, there should be no mercy on any ground whatsoever. Having known a little of Government, many times, when you see a thing, you get angry, and if you delay taking action against the delinquent, other people come, pressure comes, influence comes and many things happen, and that is one of the reasons why some of the Members wanted that necessary action should be taken immediately.

These are some of the suggestions which I am making to eradicate corruption, and the sooner we are able to do something about it, the better. Thank you. I support the Motion.

SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, at the very outset let us express our greatfulness to Providence for the recovery of our Prime Minister, and we trust and believe that his services will be available to the nation for many years to come and that we will have the benefit of his guidance.

Mr. Vice-Chairman, I fully share the views and feelings exhussed by a number of hon. Members here regarding Kashmir, regarding Pakistan and regarding the miserable rhythms of foreign policy expressed by the representative of Great Britain in the Security Council. I trust that Britain would realise the pathetic nature of its policy and try to mend the mistakes committed in relation to Kashmir as early as possible.

Mr. Vice-Chairman, the Vice-President was pleased to refer in the course of his speech to various aspects of socialism and democracy, and he has stated that it is the aim of this country to take this country to socialism through democracy and peaceful means. In this context I presume that he meant that through various forms of economic policies the economic disparities are to be brought down. I may in this context, Mr. Vice-Chairman, refer to a very learned statement made by Professor K. N. Raj, an eminent economist of this country. In one of his articles he has stated:

> "The view that economic inequalities can be dealt with by fiscal measures and that, therefore, it is not really necessary to substitute social for private ownership to prevent concentration of economic power is based on wrong premises. Economies of scale in industry lead inevitably to the corporate form of organisation, to larger-sized corporations, and to various kinds of integration and it is difficult to check these tendencies without coming in the way of economic growth itself. There are many difficulties in applying the principle of progression to the taxation of companies. The corporate form of organisation also facilitates evasion of tax in various ways by those associated with it (such as through expense accounts). As long as privately-owned corporations are given an important functional role in an economy, concentration of economic power in private hands cannot really be avoided."

The Congress President, Mr. Kamaraj, with his sense of realism and practicality, had stated, in the course of his presidential address at Bhubaneshwar, with a telling simplicity and with full sense of practical approach to this problem, as follows:

> "Many of us may have believed in the past that we can reduce disparities through taxation. Since apparently this means has not proved sufficiently effective, we should have a second look at it and adjust our taxation and other policies to accomplish this very desirable end."

I hope the sentiments expressed by the Congress President and the learned Professor would have some effect on the budgetary policy which the hon. Finance Minister is going to enunciate in the near future.

In this context, at page 30 of his book, "Liberty in the Modern State", Prof. Laski has said:—

> "The private ownership of the means of production is no longer compatible with democratic institutions and that accordingly the more prolonged its continuance, the more certain it is to result in the problems which are unlikely to be settled by peaceful means."

Hence, I humbly ask whether the time has not come when we should exercise our minds over these various policies, consider the nature of changes in social and economic policies that would really bring about to reduce economic disparities.

In this context, Sir, inevitably one should understand as a student of economics that there is absolute neces-

[Shri K. V. Raghunatha Reddy.]

sity for nationalising all important sectors of our economy, the basic step being the nationalisation of banks. When I speak of nationalisation, I am immediately reminded of the contemporary juristic thoughts that are prevalent in this country either through judgments or interpretations of law. With your permission, Mr. Vice-Chairman, I may refer to a very recent judgement of the Supreme Court which raises certain very important issues which concern the various economic policies that Parliament, the Central Government and the State Governments may have to consider and decide.

The Supreme Court has gone into the question of policy enunciated by the State in relation to the nationalisation of bus routes in the Kurnool district of Andhra Pradesh. Hon. Members, Mr. Vice-Chairman, must be quite aware of the situation which led to the resignation of a very able Chief Minister of one of the States of the country. Mr. Vice-Chairman, this is not purely an individual problem that confronts either a particular Chief Minister or a Minister of a certain State. This is a problem which has to be faced squarely in principle, not in relation to any particular personality. This problem has to be understood in the context of social and institutional changes since we believe in the results of charges in social institutions for the purpose of development of socialism. Every time, every day an administrator has to face this problem. And in political life, Mr. Vice-Chairman, you cannot always expect only friends. Often you have to deal with your friends as well as your adversaries. You will have to deal with all kinds of persons. Especially when there is a struggle between the private sector and the public sector, the private sector will not consider any means at their disposal to be mean enough not to be used against the public sector or the protagonists of the public sector. In that context, Mr. Vice-Chairman, this judgment has to be viewed. We have to view how far the courts can interfere with the questions of policy which are the main responsibility of the executive and the legislatures.

Further, Sir, we have always believed that no man will be condemned without being made a party to a proceeding and without a proper notice being issued to him by the court either by his designation or by name. Without making him a party to a proceeding no adverse comments can be passed against him. Mr. Vice-Chairman, any allegations of *mala fides* or misconduct in law are in the nature of charges in the criminal law. In relation to opportunity, trial or enquiry and burden of proof, the principles applicable to criminal trial and the rules of procedure apply to arrive at a finding of *mala fides*. Unfortunately, this rule of procedure or the rule of burden of proof which says that all the allegations must be proved beyond reasonable doubt has been set at naught. These are matters which the jurists of this country, which the Members of Parliament will have to ponder over and see whether there is any crisis in the development of juristic processes and offer their advice.

Mr. Vice-Chairman, all that happened in this matter was that instead of nationalising the bus routes in one district nationalisation was taken up in another district because it was felt by the Government and by the Chief Minister that the routes in that particular district were more contiguous to the already nationalised sector. Under the Motor Vehicles Act, under section 34, the Government has got the power to issue directions to the Road Transport Corporation to nationalise in any particular manner. But in this case the Government, without resorting to the power granted to them under section 34 what they did was they requested the Road Transport Corporation to consider the various suggestions, which the Government is entitled to make, whether nationalisation of routes in a particular district like

Kurnool would be beneficial or not On considering the various suggestions the Road Transport Corporation came to a certain conclusion.

Now a test has to be applied in all these matters If an act done is manifestly good, the intentions of a human being will have to be judged on the face of the act because it is impossible for any man to find out how the mind of a man works If the act is done, on the face of the act the intentions of the man are manifest If it is not judged in this way, by a court of law, I am afraid this is an act of juristic misconception

Mr Vice-Chairman, there is one more principle If there are two conclusions that can be reasonably drawn by a court of law, one consistent with the *bona fides* and another consistent with the *mala fides,* in the criminal jurisprudence the primary rule that has to be followed in this matter says that the one consistent with the *bona fides* should be taken up for the purpose I am afraid this rule also has been set at naught and this leads to a crisis in juristic thought I hope the jurists of the country would take note of this matter and raise this issue for a public discussion so that these principles may be well settled

It is said, Mr Vice-Chairman, by Prof Laski in one of his essays that "Humanity in history has always crucified its pioneers" And the Chief Minister of Andhra Pradesh as a Congress man—I am not a Congress man—has set a very noble example by his conduct By offering to resign he has enhanced the prestige not only of the Congress organisation but also the prestige of the judicial institutions But while his conduct has to be appreciated and while his nobility has to be emulated, I ask all Congress persons who are charged with administration—if this principle is not settled—whether it would not lead to a dangerous precedent Mr Vice-Chairman, as a politician you must know that while contesting elections you have to meet all kinds of political people and it is not necessary always that you may meet friends everywhere All kinds of allegations will be made and day after day the Government has to pass not one order but thousands of orders and if a Government is likely to be faced with such a problem, the question is what are the principles to govern and what are the principles that are to govern the conduct of human beings in relation to these matters

While we appreciate the attitude shown by Shri Sanjeeva Reddy, while he has set an example as a pioneer in this field by coming forward to relinquish power which is not easily done by human beings, still I wish he should not have yielded his ground because all that he had done he had done for public good though due to legal technicalities and legal interpretations the orders may not have been found to be good by the courts

I do trust that the people of Andhra in particular and the people in general would certainly appreciate his stand and stand in solid phalanx as far as Shri Sanjeeva Reddy is concerned in the attitude he had taken and certainly support his leadership, for he has now become the first pioneer in this field Probably his case stands unique in contemporary political history I think the year 1964 is seeing a good beginning I hope the Parliament and the leaders of the nation would decide this principle and see that the policy matters are not interfered with and the example set up by Mr Sanjeeva Reddy however noble it may be, I am afraid, is a dangerous precedent and he should have been persuaded not to resign

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P BHARGAVA) Shri Dayaldas Kurre

श्री दयाल दास कुर्रे (मध्य प्रदेश) उपाध्यक्ष महोदय, उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के सिलसिले मे हमारे हाउस के वयोवृद्ध सदस्य श्री देवकीनंदन नारायण जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मै उसका हार्दिक समर्थन करने के लिये यहा पर खडा हुआ हूं ।

[श्री दयाल दास कुरे]

हमारे देश की वैदेशिक नीति पर, हमारी सीमा पर आई हुई आपत्तियों और राष्ट्र उन आपत्तियो का उन आक्रमणों का और उन समस्याओ का किस प्रकार से सामना कर रहा है उस पर, राष्ट्र मे किस प्रकार की औद्योगिक तरक्की हो रही है, खेती मे किस प्रकार की तरक्की हो रही है तथा राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊचा लाने के लिये किस प्रकार से आगे प्रगति कर रहा है, इन सब पर उपराष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मे एक विहगम दृष्टि डाली है और इन स्थितियो पर जो उन्होने प्रकाश डाला है या उसके लिये जो प्रयास किया है उसके लिये हम उनके बहुत आभारी है ।

कल मैने इस सदन मे इस सदन के दो सीनियर माननीय सदस्यो का भाषण सुना, उसको सुनने का मुझे अवसर मिला, उनमे से एक वयोवृद्ध सदस्य है श्री घोष और दूसरे है श्री गगाशरण सिह और उन दोनो ने काश्मीर और पाकिस्तान की समस्या को ले कर बहुत ही सुन्दर चित्रण किया और उन्होंने सरकार के सामने और इस सदन के सामने जो अपने सुझाव दिये है वे सचमुच मे प्रशसनीय है । श्री घोष ने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों की शासन पद्धति अलग अलग है, जब कि हम प्रजातत्र मे विश्वास करते है, बालिग मताधिकार को ले कर के हमारी शासनपद्धति चल रही है और हमारे देश मे प्रजातात्रिक आधार पर तीन चुनाव हो चुके है तब पाकिस्तान मे हम देखते है कि प्रजातत्र का नाम भी नही है, वहा प्रजातात्रिक आधार पर, बालिग मताधिकार के आधार पर, चुनाव की या शासन की कोई पद्धति नही है, वहा एकसत्तात्मक राज्य है तो हम कैसे समझ सकते है कि हमारी स्थिति पाकिस्तान मे ठीक तरह से समझी जायगी और हम सबों का, सदन का और सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिये कि ऐसा वातावरण वहा भी बनाया जाये जिससे कि पाकिस्तान हम सबको और यह समझे कि हमारी और पाकिस्तान की मित्रता की कितना आवश्यकता है ताकि एक समय ऐसा आयेगा कि जब कि वह इस पर विचार कर सकेगा । काश्मीर के सिलसिले मे श्री गगाशरण सिह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक पवित्र बाल की चोरी के सिलसिले मे पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसा षडयंत्र रचा गया जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर एक सुन्दर चीज वह ला सके और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे एक ऐसा नमूना वह पेश करे जिससे कि हिन्दुस्तान बदनाम हो और काश्मीर की यह समस्या पाकिस्तान के पक्ष मे जाय । यह जो बात श्री गंगाशरण सिह ने रखी उसका मै समर्थन करता हूं ।

हमारे राष्ट्रपति जी ने विदेशो के साथ जिस प्रकार के सम्बन्ध रखे और ससार के दूसरे देशो---अमेरिका, इग्लैड, नैपाल, अफगानिस्तान और ईरान आदि प्रदेशों का दौरा कर के उन्होने उनके साथ जिस मित्रता का और जिस भाईचारे का सम्बन्ध बनाया और जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ाया उसके लिये भी वह हमारे बडे आदर के पात्र है । उसी प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी सूडान, इथोपिया और सयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की और उससे उन देशों के साथ हमारी मित्रता बढ़ी, उनकी हमारे साथ अच्छी कामनाये बनी और उन देशो के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे बने । इसी प्रकार से विदेशो के महान पुरुषो ने भी महामहिम लाओस नरेश, महामहिम नेपाल नरेश और उनकी महारानी तथा जोर्डन और अन्य देशों के नायक लोगो ने हमारे देश की यात्रा की और इससे हमारे और उन देशो के सबध बढे । हम देखते है कि भारतवर्ष का सबध विश्व के और देशों के साथ बहुत अच्छा है और जब चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया तब विश्व के ६२ राष्ट्रो ने हमारे प्रति जो सद्भावना दिखाई और जो हमे सहायता भजी उससे प्रमाणित होता है कि विश्व के अन्य राष्ट्रो के साथ हमारे सबध अच्छे है । केवल यह बात प्रदर्शित करती है

कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। हम किसी गुट मे शामिल होना नही चाहते और हम 'जिओ और जीने दो" की नीति पर विश्वास करते है। तथा जिओ और मिलजुल कर जिओ की इस नीति पर भी विश्वास करते है।

हमारे उपराष्ट्रपति जी ने अभिभाषण मे खेती की उन्नति के बारे मे सुन्दर प्रकाश डाला है। हमारे देश का जो सब से बडा उद्योग है, जो बहुमत को लेकर चलता है वह खेती है। हम देखते है कि ७० से ८० प्रतिशत लोगो का जीवन खेती पर आधारित है। तो खेती का जो उत्पादन हुआ है उस विषय मे अभिभाषण मे कहा गया है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खेती का उत्पादन कुछ कम हो पाया है इसलिये भावों मे भी कुछ उतार-चढाव आया है परन्तु सन् १९६३-६४ मे सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है कि खेती का उत्पादन बढे और राज्यों की तरफ से इस विषय मे प्रगति के पथ पर जाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। खेती की तरक्की के सबध मे मै सदन का ध्यान आकर्षित करूगा कि इस समय हमारे यहा सीमा पर ६० हजार एकड भूमि ऐसी ऊजड पडी हुई है और उस विषय पर सरकार और सदन विचार करे और अगर उसे खेती मे ले ले तो विशेष तरक्की खेती की हो सकती है, वह सीमा चम्बल का डाकूग्रस्त एरिया है। जहा पर मध्य प्रदेश, यू० पी० और राजस्थान इन तीन राज्यों की सीमा आती है वह डैकोइट एरिया के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य मे जब तीन, चार राज्यों का विलय हुआ तो उसके बाद डाकू समस्या का हल करने के लिये प्रयत्न किये गये और अब भी प्रयत्न जारी हैं और उसके फलस्वरूप सैकडों डाकू गोली के शिकार बनाए गए और हजारों को पकड कर जेल मे डाला गया है। फिर भी वह बीहड की समस्या और डाकुओं की समस्या वहा आज विद्यमान है। तो मै सदन से इस बात के सिलसिले मे निवेदन करना चाहता हू कि यदि इस डाकू समस्या को हम हल करना चाहते है तो केन्द्र सरकार इसको अपने हाथ मे ले। यदि वह डाकू समस्या हल हो जाती है तो जनता का बहुत हित हो सकता है।

साथ ही साथ, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ६०,००० एकड़ जमीन जो इस समय चम्बल के बीहड के अन्दर आती है, यदि सरकार उसे कृषि के योग्य परिवर्तित करना चाहे तो वहा पर अधिकाश लोगों को जो भूमिहीन है, किसान है, मजदूर है, उनको जमीन दे सकते है और खेती का उत्पादन अधिक बढ सकता है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, गत वर्ष मध्य प्रदेश शासन के अग्रिकलचर विभाग से और केन्द्रीय शासन के एग्रिकलचर विभाग से इस विषय मे चर्चा हुई है और केन्द्रीय शासन ने मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग को ५ करोड रुपये बुलडोजर, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिये देने का आश्वासन दिया है। यदि यह बात सही है तो यह केन्द्रीय सरकार का बहुत बडा कदम है और यदि वह खुद अपने हाथ मे ले तो बहुत ही अच्छा कदम हो, और हम ऐसा करके खेती के उत्पादन को मध्य प्रदेश मे बढा सकते है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि मैंने देखा है, खास कर मध्य प्रदेश के उस भाग मे जहां से मैं आता हू, कि इस समय गल्ले की चीजों की कमी होने के कारण गल्ले की कीमत बढ गई है और इस समस्या को हल करने के लिये प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार दोनो के पास अन्न का जो स्टाक है और वहा से फेयर प्राइस शाप को जो अनाज देते है, उसमे हमने देखा कि बडी कमी आ गई है और मैने यह भी महसूस किया कि फेयर प्राइस शाप जो इस समय खुले है यदि उनकी सख्या बढाई जाय तो गरीब, लोअर और लोअर मिडिल क्लास को अधिक सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ

[श्री दयाल दास कुर्रे]

ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को राइस मिल्स जितनी है, उनके कोटा में भी वृद्धि करनी चाहिये । जहां तक मुझे ख्याल है, चालीस प्रति शत राइस मिल का उत्पादन केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार लेती है—२० प्रतिशत केन्द्रीय शासन और २० प्रतिशत प्रान्त। शासन लेती है जब कि हम देखते है कि प्रान्तीय शासन स्टाक को जब फेयर प्राइस शाप मे देती है तो वह इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि उन्हे केन्द्रीय सरकार से परमिट लेने का रास्ता देखना पड़ता है और इसमें समय लगता है । तो ४० प्रतिशत जो राइस मिलों से कोटा लिया जाता है उसको बढ़ा कर ६० प्रतिशत किया जाय और उसमें से चालीस प्रतिशत प्रान्तीय शासन को दिया जाय, उसको गोदाम मे रखा जाय जिससे हम लोगों को राहत दे सकते है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमे हम ज्यादा सफल हुए है, हम अधिक लोगों को आगे राहत दे सकते है ।

इसी के सिलसिले मे मैं वेयरहाउसिंग की बात भी करना चाहता हूं । वेयरहाउसिंग द्वारा जहा हम सरकारी गोदाम बनाते है वहा हम अन्न को अधिक अच्छी तादाद मे रख सकते हैं । उनकी संख्या आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है और उनको अधिक संख्या में खोलने की जरूरत है जिससे कि हम सरकारी माल के अलावा गैर सरकारी माल को भी अधिक तादाद में रख सकते हैं । तो मैने खास कर मध्य प्रदेश मे देखा कि वहा वेयरहाउसिंग की कमी है । खास करके कम्युनिटी डेवलपमेंट इनके लिये बडी प्रयत्नशील है । लेकिन इसको बढाने की आवश्यकता है और जहा हम गैर सरकारी प्रतिवर्ष के उत्पादन की चीजों को रख सकते है वहा उन लोगों को जो ऐसी चीजें को रखते है ऋण के रूप मे रकम भी दे सकते है । इससे किसान वर्ग को अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते है ।

उप सभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखते हुए मुझे भी यह महसूस हुआ कि हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है । अभिभाषण में कहा गया है कि गत वर्ष के उत्पादन को देखते हुये जब हम उद्योग धधों की कार्य विधि को देखते है तो सन् १९६३–६४ में ७ ८ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि होने की सभावना है–ऐसी आशा उप राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में व्यक्त की है। मैं भी इससे सहमत होता हू । मै आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, खास कर मध्य प्रदेश का वह भाग जो कि पुराना महाकौशल कहलाता है, वह इस समय पूरे राष्ट्र को रा मैटीरियल देने के लिये बहुत उत्तम स्थान बन गया है। खास कर लोहा, कोयला, मेंगनीज, ये चीजे आपको उस स्थान में मिलती है, और आपका ध्यान उस ओर तो अवश्य जाता होगा जहा भिलाई का कारखाने जैसी एक बहुत अच्छी चीज अपने देश में बन गयी है। उसी तरह से बस्तर जिले में बेलाडिला का नाम आपने सुना होगा जहा हम अच्छे दरजे का लोहा देश को दे रहे है। पर मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि इतनी अच्छी चीजे, रा मैटीरियल हम उस भाग से देते है, लेकिन हम उस प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर नही पाते है। आज ही मुझे अपने प्रदेश के वयोवृद्ध नेता श्री माडलोई जी से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि सन् १९५२ से लेकर आज तक १० वर्ष के दर्मियान में, जैसा कि मालूम हुआ, प्राइवेट सेक्टर में केवल १० करोड़ रु० खर्च हो पाए है ? यह हमारे प्रदेश की तरक्की का एक नमूना है। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, यह भारतवर्ष में सबसे बडा प्रदेश है और रा मैटीरियल की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह है। यदि हम औद्योगिक

दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास न कर सकें तो हम वहा के पिछडे लोगो की तरक्की नही कर सकेंगे ।

जहा तक कच्चा माल जो उद्योग धंधो के काम आता है उसका परमिट केन्द्र सरकार से प्रान्तो को दिये जाने की बात है उसमे भी हमारे पास बहुत कम हिस्सा आता है । सन् १९६२ का एक आकड मैं देता हू जिससे मालूम होगा कि आवश्यक चीजे, जैसे तावा, जस्ता, पीतल अल्यू-मिनियम और दूसरी चीजे जैसे स्टेनलेस स्टील का कोटा इतना कम दिया जाता है हमारे प्रदेश को कि बहुत से कारखाने बद हो गए और बहुत से उत्साही लोग जो नए कारखाने प्राइवेट सेक्टर मे चलाना चाहते है उनका उत्साह खत्म हो गया क्योकि उनका लाइसेन्स कैन्सिल हो गया और उनकी आशा निराशा मे बदल गई । जैसा कि मैने कहा, एक आकडा स्टेनलेस स्टील का है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पजाब, और मद्रास को दिये गये कोटा की जरा तुलना कीजिए । सन् १९६२ मे गुजरात को ५६ टन मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को केवल ७ टन मिला है और महाराष्ट्र को २०४ टन, पजाब को १०८ टन, मद्रास को १३२ टन और मैसूर को १४२ टन । तो उन राज्यों की तलना मे मध्य प्रदेश को केवल ७ टन मिला है स्टेनलेस स्टील । अब आप समझ लीजिए कि इसमे कितने कारखाने चलाये जा सकते है और किस प्रकार से उनको हम प्रात्साहन दे सकते है । यह तो मैने एक ही उदाहरण दिया । इसी प्रकार से टिन की चादरो के सिलसिले मे, तावे के सिलसिले मे, जस्ते के सिलसिले मे, पीतल के सिलसिले मे, जितनी भी चीजो का लाइसेन्स सेन्टर द्वारा किया जाता है उसमे मध्य प्रदेश को नेगलेक्ट किया गया है और मै बडे अदब के साथ कहूँगा कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिये और मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र मे बदलना चाहिये ।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) भिलाई भी तो वहा है ।

श्री दयाल दास कुरें एक भिलाई से क्या होता है । सारा लोहा हम दे देते है । हमारे लिये बडी खुशी की बात है कि कोरबा मे एक थर्मल प्लान्ट बन रहा है, वहा एक ऐसा स्थान नियुक्त किया गया है जहा अल्यूमिनियम का एक कारखाना बनने जा रहा है । हमदो प्रोजेक्ट का एक केन्द्र स्थान कोरबा बन रहा है ।

इस प्रकार हम देखते है कि कोरबा का एक छोटा सा गाव भिलाई की तरह हो रहा है । मै केवल इस विषय मे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि कोरबा एक औद्योगिक बस्ती के रूप म परिवर्तित हो रहा है लेकिन वहा पर सरकार ने टाउन डेवलपमेट की कोई स्कीम अभी तक नही बनाई और न प्रान्तीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया । जब तक वहा पर टाउन डेवलपमेट की स्कीम नही बनती तब तक हम वहा पर किसी तरह की स्कीम लागू नही कर सकते है । आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि कोरबा तक जाने के लिए हमारे पास कोई अच्छी सडक नही है । वहा की सडक की स्थिति इतनी खराब है कि जो गाडिया वहा सामान लेकर जाती है तो उनका अधिक खर्च अपनी ट्रको और गाडियो के रिपेयरिग करने मे ही हो जाता है । वहा पर जो टाउन डेवलपमेट की स्कीम है वह पचायत अपनी जो २ हजार रुपया उसकी आमदनी होती है उससे कर रही है ।

दूसरी बात जो मै सदन के सामने रखना चाहता हू वह यह है कि मध्य प्रदेश का एक तिहाई भाग पिछडा है, फारेस्ट मे भरा हुआ है और उसमे हरिजन तथा आदिवासी लोग रहते है । ये लोग हर दृष्टि से पिछडे हुए

[श्री दयाल दास कुर्रे]

है और उन्हें तरक्की के रास्ते मे लाने की बहुत आवश्यकता है । मैं सदन के सामने यह निवेदन करूंगा उस क्षेत्र की तरक्की के लिए एक पायलट स्कीम की जरूरत है । इसमें कोई शक नही कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे उस क्षेत्र के लिए बहुत कार्य कर रही है । केन्द्रीय सरकार की ओर से उस क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रान्तीय शासन भी इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है । परन्तु मैं केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह से ईस्ट यू० पी० के क्षेत्र को प्रगति के पथ पर लाने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने पायलट स्कीम बनाई है उसी तरह की स्कीम इस क्षेत्र के लिए भी उसे बनानी चाहिए । इस महाकोशल एरिया का जो छत्तीसगढ का भाग है उसकी जो आबादी है वह हरिजनों और आदिवासियों से ही भरी हुई है और उन लोगों के लिए विशेष काम खोले जाने चाहियें ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत मे सुधार हो सके । अगर इस तरह की कोई स्कीम वहां पर लागू की गई तो उन लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा और वे भी प्रगति के पथ पर देश के और लोगों के साथ आगे बढ़ सकेंगे । मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस तरह की स्कीम बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम अपने देश मे रोड की स्थिति को देखें तो अन्य देशों की अपेक्षा वह बहुत कम है । हमारे यहां रोड की स्थिति बहुत कमजोर है । भारत के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में मध्य प्रदेश मे रोड की स्थिति और भी खराब है । मै सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू । मध्य प्रदेश की हालत को देख कर मै केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में अधिक रोड की लाइन देने की जरूरत है और उसके लिए प्रान्तीय सरकार के बजट मे एक अलग फन्ड बनाने की आवश्यकता है । जिससे इस प्रदेश में रोड की स्थिति ठीक हो सके । इस फन्ड से पुरानी रोड़ा की मरम्मत हो सकेगी और नई सड़के तैयार की जा सकेगी ।

एयर लाइन की सुविधा भी वहा पर बहुत कम है । दिल्ली से भोपाल को जोड़ने के लिए एक नई लाइन आई है । इसी तरह से भोपाल, नागपुर, जबलपुर और रायपुर को मुख्य स्टेशनों से कनेक्ट करने की व्यवस्था की गई है । मध्य प्रदेश भारतवर्ष के अन्य राज्यों से कम से कम एरिया में सब से बड़ा है । उसके प्रत्येक डिविजनल हैडक्वार्टर्स को एयरलाइन्स से जोड़ने की आवश्यकता है ।इस के लिए सरकार को शीघ्र ही व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सके । अगर इस तरह की व्यवस्था कर दीगई तो लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी और शासन का कारोबार भी ठीक तरह से चलेगा ।

SHRI A. D. MANI: Mr. Vice-Chairman, in taking part in this debate on the President's Address, I should like to join other Members who have paid a tribute to our President who has undergone an eye operation. I should like to join with all in wishing the President a very speedy recovery and return to his office. We also are much obliged to the Vice-President for his addressing the joint session of Parliament, discharging the functions of the President of India during his illness. Sir, the House also deeply regrets that illness has prevented the Prime Minister from taking an active part in the proceedings of Parliament. We have seen for ourselves what the Prime Minister means to Parliament today. It seems to me that he was the soul of the Parliament and we are sorry that illness has prevented him from taking an active part in its proceedings.

Sir, I do not wish to introduce a note of controversy in the debate at this late stage of the evening but I

should like to say that the time has come for us to provide in the Constitution for emergencies of the character which has arisen on account of the illness of the Prime Minister. In the United States there is at present a furious public debate going on on the question of Presidential disability on account of illness and there are suggestions that the Constitution of the United States should be amended in order to provide for the effective leadership of Government if in any case the President or the Vice-President is disabled or incapacitated from functioning. Sir, I think the time has come, for the effective leadership of Government, that the Constitution should be amended in order to provide for the appointment of a Deputy Prime Minister who will be appointed by the President on the advice of the Prime Minister so that there is continuity of leadership if for any reason the Prime Minister on account of illness is not able to discharge his functions. I must say that the so-called troika that is functioning today, the leadership being distributed among three persons does not seem to be effective. We have seen for ourselves how ineffective the leadership of Government is in both Houses of Parliament and I do hope, Sir, that in view of the illness of the Prime Minister, serious attention will be given by Government and the Members of the Congress Party as well as of the Opposition parties to the question of amending the Constitution for this purpose. Sir, I do not propose to go into the way in which the Congress Party evolves its leaders; the way in which the Congress Party discovers its leaders seems to be as mysterious as that of the Conservative Party in Great Britain where the leadership is evolved through a mysterious process. Whatever may be the manner in which the leadership of the ruling party is evolved, I think that we should provide in the Constitution itself for the effective leadership of Government and it need not be presumed that a person who is chosen as Deputy Prime Minister will inevitably become the Prime Minister in case a vacancy arises. It is only to see that with effectiveness the Government is carried on that I am making this suggestion.

Sir, I must confess that I am disappointed with the reference in the Address in paragraph 14 to the Chinese threat. The emergency is continuing. The Defence of India Act and the Defence of India Rules are in force. And so great is the emergency and so great is the impact of the emergency on Government and the public mind that in the whole Address there are only four lines devoted to the Chinese threat. I am reading the lines concerned:

> "The Chinese threat has continued throughout the year, though there has been no actual fighting along our borders. China still maintains its intransigent attitude on the Colombo proposals and Chinese military build-up along our borders has increased."

On November 8, 1962, we passed in this House as well as in the other House . . .

AN HON. MEMBER: November 14th.

SHRI A. D. MANI: On November 8 the Resolution was moved and on November 14 the Resolution was adopted in this House as well as in the other House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You can continue later.

The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

> The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 14th February, 1964.

GMGIPND—RS—1100 RS—2-4-64—550.